सूर्योदय 6.04 सूर्यास्त 6:31

आज का तापमान

शिमला	16.5 न्यू	23.9 अधि
धर्मशाला	17.6 न्यू	28.0 अधि

बाजार

सेंसेक्स	74,781
निफ्टी	23,398

सोना 1,53,000 चांदी 2,30,000

भारतेन्दु शिखर

हिमाचल, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू व उत्तराखंड में प्रसारित

आरएनआई नं. HPHIN/2000/02437 | शिमला | शनिवार, 12 सितंबर 2026 | 27 भाद्रपद, विक्रमी संवत 2083 | वर्ष 28, अंक 138, कुल पृष्ठ 12 | मूल्य : 5 रुपए | info@bhartendushikhar.com | 8894677702

न्यूज शॉर्ट्स

कठुआ में पाकिस्तानी घुसपैठिया गिरफ्तार

एजेंसी, कठुआ। जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास सुरक्षा बलों ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उसे हिरानगर सेक्टर के बोबिया इलाके में सीमा पर लगी फेंसिंग के पास पकड़ा गया। सूत्रों के मुताबिक, गिरफ्तार व्यक्ति की उम्र करीब 65 साल है। सुरक्षा बलों ने पाकिस्तानी नागरिक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। सीमा पार करने की परिस्थितियों और इलाके में उसकी मौजूदगी के मकसद की जानकारी जुटाई जा रही है। ये पिछले 3 दिन में एलओसी पर घुसपैठ की 5वीं घटना है।

26 साल के युवक के पेट में मिला गर्भाशय

एजेंसी, नई दिल्ली। दिल्ली के 26 साल के युवक की बांझपन की जांच में पेट के अंदर गर्भाशय (यूटेरस) मिला है। दोनों अंडकोष भी पेट के अंदर थे। युवक राजौरी गार्डन स्थित आरजी हॉस्पिटल्स में प्राथमिक बांझपन का इलाज कराने पहुंचा था। जांच में उसके वीर्य में शुक्राणु नहीं मिले हैं। एमआरआई में पेल्विस के अंदर गर्भाशय जैसी संरचना दिखी। डॉक्टरों के मुताबिक, यह पर्सिस्टेंट म्यूलरियन डक्ट सिंड्रोम जैसी दुर्लभ जन्मजात स्थिति हो सकती है। पूरी दुनिया में इसके सिर्फ 300 मामले हैं। युवक की दोनों टेस्टिस यानी अंडकोष नीचे नहीं उतरे थे। वे लंबे समय से पेट के अंदर थे और गंभीर रूप से सिकुड़ चुके थे।

दुनिया का ग्रोथ इंजन है भारत : आईएमएफ

एजेंसी, नई दिल्ली। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारतीय अर्थव्यवस्था की तारीफ की है। साथ ही भारत को दुनिया का ग्रोथ इंजन भी बताया है। भारत की अर्थव्यवस्था ने ऊर्जा संकट और वैश्विक चुनौतियों के बीच भी अपनी तेज रफ्तार बरकरार रखी है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल-जून में देश की रियल जीडीपी ग्रोथ 7.8% दर्ज की गई है। आईएमएफ ने भारत के इस बेहतर प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि मजबूत सर्विसेज सेक्टर और बेहतर एक्सपोर्ट के दम पर यह ग्रोथ उम्मीद से काफी बेहतर रही है। आईएमएफ की प्रवक्ता जूली कोजाक ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि अप्रैल-जून तिमाही में भारत की 7.8% की जीडीपी ग्रोथ उनके अनुमान और मार्केट एक्सपर्ट्स की उम्मीदों से कहीं ज्यादा है।

बैंक में कर्मचारियों पर मिर्च डालकर 4.53 लाख लूटे

एजेंसी, नागपुर। महाराष्ट्र के नागपुर में बैंक में लूट का मामला सामने आया है। यहां एक 28 साल के युवक ने कर्मचारियों की आंखों में लाल मिर्च पाउडर डालकर उनसे 4.53 लाख रुपए लेकर भाग गया। इसके बाद आरोपी मौके से भागने लगा, लेकिन बैंक कर्मचारियों ने उसका पीछा किया। पुलिस की मदद से उसे करीब एक किमी दूर पकड़ लिया गया। पुलिस ने आरोपी के पास से लूटी गई पूरी 4.53 लाख रुपए की रकम बरामद कर ली है। घटना नागपुर के भांडे प्लॉट इलाके में हुई। बैंक कर्मचारी एटीएम से कैश लेकर एसबीआई ब्रांच लौट रहे थे। पूरी घटना बैंक के सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई।

प्रधानमंत्री मोदी व रूसी राष्ट्रपति पुतिन समेत ब्रिक्स लीडर्स ने ब्रिक्स बिजनेस फोरम में ग्लोबल ट्रेड पर की बातचीत

ब्रिक्स देशों में दुनिया की 50% आबादी, 40% जीडीपी : मोदी

एजेंसी, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत ब्रिक्स लीडर्स ने शुक्रवार को ब्रिक्स बिजनेस फोरम में ग्लोबल ट्रेड पर बात की। इसमें सबसे अहम बयान पुतिन का रहा। उन्होंने अमेरिका और यूरोप पर तंज कसते हुए कहा, पश्चिम अब कमजोर हो रहा है, पता नहीं ये देश खुद को जी-7 क्यों कहते हैं। दुनिया की 40% से ज्यादा जीडीपी ब्रिक्स देशों से आई, जी-7 की हिस्सेदारी सिर्फ 29% रही। इसके बाद पीएम मोदी ने भी बिजनेस फोरम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों में दुनिया की आधी आबादी रहती है। ये दुनिया की 40% जीडीपी में हिस्सा रखते हैं। भारत व्यापार बढ़ाना चाहता है और इसके लिए सुरक्षित समुद्री रास्ते जरूरी हैं।

भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता शानदार : ब्राजील

ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो विएरा ने भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि भारत की अध्यक्षता शानदार और बेहद सफल रही और इस दौरान काफी काम हुआ।

ईरानी राष्ट्रपति बोले- अपनी करेंसी में कारोबार बढ़ाएं

ब्रिक्स बिजनेस फोरम में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजशकियान ने कहा कि ब्रिक्स देशों को आपसी कारोबार में अपनी-अपनी करेंसी का इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मौजूदा व्यवस्था कुछ गिनी-चुनी करेंसी पर ज्यादा निर्भर है, इसलिए यह राजनीतिक संकट से प्रभावित हो सकती है।

दुनिया में बड़ा बदलाव हो रहा : पुतिन

ब्रिक्स बिजनेस फोरम के लीडर्स सेशन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि दुनिया में इस समय बड़े और गहरे बदलाव हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि 20वीं सदी के दूसरे हिस्से में दुनिया की आर्थिक तरक्की को आगे बढ़ाने वाले पुराने आर्थिक केंद्रों की जगह अब नए देश और नई अर्थव्यवस्थाएं विकास को आगे बढ़ा रही हैं। पुतिन ने कहा कि पुराने आर्थिक केंद्रों के पास आज भी मजबूत बुनियादी ढांचा, बेहतर टेक्नोलॉजी, वैज्ञानिक क्षमता और मजबूत रिसर्च संस्थान हैं, लेकिन दुनिया और अर्थव्यवस्था हमेशा बदलती रहती है। इसलिए नए देशों का आर्थिक ताकत के तौर पर आगे आना स्वाभाविक है।

रामाफोसा बोले- खनिज के बदले हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए

दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने कहा कि अफ्रीका सिर्फ दुनिया को अपने खनिज देता रहे और बदले में उसे अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए निवेश न मिले, ऐसा नहीं चल सकता। दिल्ली में ब्रिक्स बिजनेस फोरम में बोलते हुए उन्होंने अफ्रीकी देशों में ज्यादा निवेश और ब्रिक्स देशों के बीच मजबूत आर्थिक साझेदारी की जरूरत बताई।

4 से बढ़कर 21 देशों का हुआ ब्रिक्स परिवार : मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स बिजनेस फोरम में सभी देशों के प्रतिनिधियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इस साल ब्रिक्स की शुरुआत के 20 साल पूरे हो रहे हैं। मोदी ने कहा कि 2006 में जब ब्रिक्स की शुरुआत हुई थी, तब इसमें सिर्फ 4 देश थे। आज सदस्य और पार्टनर देशों को मिलाकर ब्रिक्स परिवार 21 देशों तक पहुंच गया है।

पुतिन ने मोदी को रूस आने का दिया न्योता

प्रधानमंत्री मोदी व रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच भारत मंडपम में 45 मिनट बैठक हुई। इसके बाद दोनों नेता एक ही कार से इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन पहुंचे। बैठक में भारत-रूस रिश्तों के साथ मिडिल ईस्ट और ब्लैक सी के हालात पर चर्चा हुई। पुतिन ने मोदी को 24वें भारत-रूस समिट के लिए रूस आने का न्योता दिया, जिसे पीएम ने स्वीकार कर लिया।

ब्रिक्स की अर्थव्यवस्था बढ़ी, लेकिन जी 7 का दबदबा कायम

रूसी राष्ट्रपति पुतिन के मुताबिक, पीपीपी के आधार पर ब्रिक्स की हिस्सेदारी दुनिया की अर्थव्यवस्था में करीब 40% है, जबकि जी 7 की 18%। यानी आर्थिक आकार में ब्रिक्स आगे है। हालांकि जी 7 को कमजोर नहीं माना जा सकता। डॉलर, बैंकिंग, निवेश और तकनीक में उसका प्रभाव अब भी बड़ा है। दूसरी तरफ ब्रिक्स की ताकत बड़ी आबादी, प्राकृतिक संसाधन और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं हैं।

शिक्षा व्यवस्था से भारतीय युवा निराश : राहुल गांधी

एजेंसी, नई दिल्ली। राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि भारत की शिक्षा व्यवस्था पीढ़ी को निराश कर रही है, जिसे बेहतर भविष्य देने के लिए बनाया गया था। उन्होंने छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से पूछा कि उनका शिक्षा व्यवस्था से भरोसा क्यों उठ गया है। उन्होंने आगे कहा कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार की शुरुआत उन लोगों की बात सुनने से होगी, जो रोजाना इसकी कमियों का सामना कर रहे हैं। राहुल ने छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से अपने अनुभव, सबूत और सुझाव ऑनलाइन साझा करने को कहा।

महिलाओं से जुड़ी ऑनलाइन शिकायत व्यवस्था होगी मजबूत

सीएम ने कहा- किशोरियों तक निशुल्क एचपीवी टीकाकरण पहुंचाना प्राथमिकता

एजेंसी, नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को राज्य महिला आयोग की बैठक में कहा कि आयोग को महिलाओं से जुड़ी ऑनलाइन शिकायत व्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ महिलाओं और बालिकाओं के हितों से जुड़े मुद्दों पर जमीनी स्तर पर सक्रियता बढ़ानी चाहिए।

उन्होंने पॉस्को और साइबर अपराधों के प्रति बालिकाओं को जागरूक करने, पात्र किशोरियों तक एचपीवी टीकाकरण का लाभ पहुंचाने और महिलाओं की शिकायतों के ऑनलाइन निस्तारण की व्यवस्था को और सरल एवं प्रभावी बनाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में आयोजित इस बैठक में आयोग की अध्यक्ष लता गुप्ता, सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉलेजों में पढ़ने वाली छात्राओं को साइबर अपराधों से बचाव के लिए विशेष रूप से जागरूक किया जाना चाहिए। उन्होंने आयोग को कॉलेजों में अभियान चलाकर छात्राओं को ऑनलाइन उत्पीड़न, सोशल मीडिया के दुरुपयोग, साइबर ठगी और अन्य डिजिटल अपराधों से बचने के उपायों की जानकारी देने तथा किसी घटना की स्थिति में शिकायत कहां और किस प्रकार दर्ज कराई जाए, इसकी जानकारी उपलब्ध कराने की सलाह दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बालिकाओं को उनके अधिकारों और यौन अपराधों से सुरक्षा के लिए उपलब्ध कानूनी प्रावधानों की जानकारी होना बेहद जरूरी है। उन्होंने आयोग से पॉस्को अधिनियम के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में अभियान चलाने तथा बालिकाओं को शोषण या उत्पीड़न की स्थिति में उपलब्ध सहायता और शिकायत व्यवस्था के बारे में जानकारी देने को कहा। सीएम ने कहा कि समाज के वंचित और जरूरतमंद वर्गों की पात्र किशोरियों तक निशुल्क एचपीवी टीकाकरण की जानकारी और सुविधा पहुंचाना प्राथमिकता होनी चाहिए।

जूनियर पुरुष एशिया कप

भारत लगातार चौथी बार फाइनल में पहुंचा

एजेंसी, मोक्वी। गत चैंपियन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मलेशिया को 3-1 से हराकर एएचएफ जूनियर पुरुष एशिया कप 2026 के फाइनल में प्रवेश कर लिया। भारत अब लगातार चौथी बार खिताब जीतने से सिर्फ एक जीत दूर है। भारत की जीत में कप्तान और ड्रैग फ्लिकर अनमोल एक्का ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने पेनल्टी कॉर्नर पर दो गोल किए और टूर्नामेंट में अपने गोलों की संख्या 16 तक पहुंचा दी। अनमोल फिलहाल टूर्नामेंट के शीर्ष स्कोरर हैं। गोलकीपर विवेक लाकड़ा भी भारत की जीत के नायक रहे। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने कई शानदार बचाव किए और 53वें मिनट में मलेशिया को मिले पेनल्टी स्ट्रोक को भी बेहतरीन अंदाज में रोककर भारत की बढ़त कायम रखी।

महाराष्ट्र के भंडारा में ट्रक-बोलेरो की टक्कर में नौ लोगों की मौत, 9 घायल

एजेंसी, मुंबई। महाराष्ट्र के भंडारा जिले के लाखनी तहसील में पिंपलगांव के पास नागपुर-रायपुर हाइवे पर ट्रक और बोलेरो के बीच हुई टक्कर में नौ लोगों की मौत हो गई, जबकि नौ अन्य घायल हो गए।

हाइवे पुलिस के मुताबिक घायलों को भंडारा स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेजा गया। वहां से गंभीर रूप से घायलों को नागपुर रेफर किया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि छत्तीसगढ़ की कुछ महिलाएं और अन्य मजदूर बोलेरो से नागपुर की ओर जा रहे थे। लाखनी के पास पिंपलगांव इलाके में पेट्रोल पंप और भाऊचा ढाबा के नजदीक हाइवे के किनारे खड़े ट्रक से अचानक बोलेरो टकरा गई। इस घटना में आठ लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक घायल ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतकों में छह महिलाएं और तीन बच्चे शामिल हैं। इस घटना में घायल नौ लोगों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। घटना की सूचना मिलते ही गड़ेगांव स्थित हाइवे पुलिस रिलीफ सेंटर के प्रमुख रवींद्र रेवतकर अपने सहयोगियों और भंडारा पुलिस अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से पुलिस और बचाव दल ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन में फंसे लोगों को बाहर निकाला और घायलों को अस्पताल पहुंचाया।

बाहर से स्क्रिप्ट लेकर पीएम मोदी को बदनाम कर रही कांग्रेस : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

एजेंसरी, पंचकूला। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को पंचकूला में कांग्रेस पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के पास न कोई नीति है, न मुद्दा और न ही कोई ठोस एजेंडा। इसलिए कांग्रेस के नेता बाहर से लिखी स्क्रिप्ट लेकर प्रधानमंत्री को बदनाम करने का प्रयास करते हैं।

पंचकूला में 'सेवा संकल्प अभियान' को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना रुके और बिना थके देश तथा देशवासियों की सेवा की है। देश की जनता प्रधानमंत्री के 25 वर्षों की निरंतर सेवा, त्याग और तपस्या की साक्षी है। सीएम ने बताया कि 17 सितंबर से 17 अक्तूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा, जिसमें विभिन्न कार्यक्रम होंगे और लाखों दीप जलाकर लोग प्रधानमंत्री मोदी को आशीर्वाद देंगे। नायब सैनी

◆ **कहा- कांग्रेस के पास न नीति, न मुद्दा और न एजेंडा**

ने कहा कि कांग्रेस को प्रधानमंत्री के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करने के बजाय आत्ममंथन करना चाहिए और अपने लंबे शासनकाल के दौरान गरीब, महिला और युवा के लिए किए गए कार्यों पर विचार करना चाहिए। कांग्रेस के शासनकाल में गरीब और गरीब होता गया। कांग्रेस के पास गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के आंकड़े तो थे, लेकिन वह आज भी यह नहीं बता सकती कि उसके शासनकाल में कितने गरीबों को गरीबी से बाहर निकाला गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 55 वर्षों तक देश पर शासन करने वालों को गरीब माताओं, बहनों और बेटियों की पीड़ा दिखाई नहीं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में लगभग 12 करोड़ शौचालय बनवाकर महिलाओं को 'इज्जत घर' देने का काम किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज कांग्रेस के लोग युवाओं की बात करते हैं और सवाल उठाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं के लिए क्या किया। कांग्रेस को पहले यह बताना चाहिए कि जब देश का युवा अवसर मांग रहा था, तब कांग्रेस कहां थी। उसके शासनकाल में युवाओं के लिए क्या नीति थी और देश के युवाओं की स्थिति क्या थी।

मोबाइल सिम की तरह अब पोर्ट करा सकेंगे फास्टैग

एजेंसी, नई दिल्ली। अब फास्टैग यूजर्स को अपना बैंक बदलने के लिए गाड़ी की विंडशील्ड पर लगा पुराना स्टिकर हटाने या नया फिजिकल टैग लगवाने की जरूरत नहीं होगी। फास्टैग भी मोबाइल सिम की तरह पोर्ट हो जाएगा। वनटैग नाम की इस नई सर्विस को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 के दौरान लॉन्च किया। टोल प्लाजा पर टैक्स कटने का तरीका बिलकुल पहले जैसा ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। आपको टोल पर गाड़ी रोकने या कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। बैकएंड में सारा कंप्यूटर सिस्टम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन संभालेगा, जो नए बैंक की जानकारी अपने-आप अपडेट कर देगा। यानी आपके लिए टोल प्लाजा से गुजरने की प्रोसेस बिलकुल नहीं बदलेगी।

ऋषिकुल बनेगा आयुर्वेद, योग और भारतीय ज्ञान परंपरा का विशिष्ट केंद्र : सीएम धामी

एजेंसी, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को हरिद्वार स्थित श्री मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान, ऋषिकुल के समग्र विकास के लिए प्रस्तावित मास्टर प्लान की समीक्षा की। उन्होंने इसे आयुर्वेद, योग और भारतीय ज्ञान परंपरा के विशिष्ट केंद्र के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि ऋषिकुल के विकास में आयुर्वेद, मेडिकल टूरिज्म, योग, ज्योतिष और वैदिक गणित को विशेष प्राथमिकता दी जाए। इन क्षेत्रों में उच्च स्तरीय शैक्षणिक, अध्ययन व शोध की सुविधाएं विकसित की जाएं, ताकि संस्थान भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक शोध के बीच प्रभावी सेतु के रूप में विकसित हो सके।

मुख्यमंत्री आवास में हुई बैठक में प्रस्तुत मास्टर प्लान के तहत ऋषिकुल को योग व ध्यान, आयुर्वेद एवं समग्र स्वास्थ्य, भारतीय दर्शन, वैदिक एवं शास्त्रीय अध्ययन, कला-संस्कृति और शोध गतिविधियों के समन्वित केंद्र के रूप में विकसित करने की परिकल्पना प्रस्तुत की गई। धामी ने कहा कि आयुष, योग और संस्कृत उत्तराखंड की विशिष्ट पहचान हैं और ऋषिकुल के विकास में इन क्षेत्रों को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। संस्थान में भारतीय ज्ञान, प्राच्य विद्याओं, आयुर्वेद और योग से संबंधित उच्च स्तरीय अध्ययन एवं शोध के लिए उत्कृष्ट वातावरण तैयार किया जाए।

उन्होंने परिसर के वास्तुशिल्प को प्राच्य एवं पारंपरिक स्थापत्य शैली के अनुरूप विकसित करने के निर्देश दिए। भवनों के बाहरी स्वरूप और फसाड में प्राचीन स्थापत्य परंपरा की झलक के साथ परिसर में आधुनिकतम सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने कहा कि प्राचीनता और आधुनिकता के संतुलित समन्वय से ऋषिकुल की विशिष्ट पहचान विकसित की जाए।

ऋषिकुल परियोजना में स्पष्ट हो मूल अवधारणा

मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना के प्रत्येक पहलू में इसकी मूल अवधारणा स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। परिसर को इस तरह विकसित किया जाए कि यहां आने वाले लोगों को भारतीय संस्कृति, ज्ञान और अध्यात्म की अनुभूति हो। हरिद्वार के धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व को देखते हुए ऋषिकुल के विकास की अवधारणा में मां गंगा और हरिद्वार की विशिष्ट पहचान को भी केंद्र में रखा जाए।

एनएलयू के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने में सहयोग करेगी प्रदेश सरकार : सीएम सुक्खू

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (एनएलयू), शिमला के मौजूदा बुनियादी ढांचे के विस्तार व सुदृढ़ीकरण में सहयोग करेगी।

मुख्यमंत्री ने वीरवार देर सायं विश्वविद्यालय से जुड़े विभिन्न विषयों की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे को और सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा उन्होंने विश्वविद्यालय को अपने संसाधन स्वयं सृजित करने पर भी बल दिया। सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार छात्राओं और छात्रों के लिए छात्रावासों के निर्माण में सहयोग करेगी। उन्होंने छात्राओं के छात्रावास

◆ **मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय से जुड़े विभिन्न विषयों की समीक्षा की**

की सीमा के साथ कंटीले तारों की बाड़ लगाने के निर्देश भी दिए, ताकि सुरक्षा को बढ़ाया जा सके।

उन्होंने कहा कि परिसर में कम वोल्टेज की समस्या के समाधान के लिए नया ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाएगा तथा छात्रावास के ऊपर से गुजर रही एचटी लाइन को स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्यार्थियों और अन्य कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परिसर के भीतर ओवरहेड बिजली तारों को भूमिगत करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाने का भी आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने जल शक्ति विभाग को सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने के लिए उपयुक्त स्थल चिन्हित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पेयजल की कमी की समस्या के समाधान के लिए प्रदेश सरकार पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाएगी।

निर्देश मुख्यमंत्री योगी बोले- बारिश से खराब सड़कों को तत्काल मोटरेबल बनाएं, बरसात के बाद नवीनीकरण भी हो

त्योहारों से पहले प्रमुख मार्गों को प्राथमिकता से गड्ढामुक्त करें

एजेंसी, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बारिश और बाढ़ से खराब हुई सड़कों की तत्काल मरम्मत कर उन्हें आवागमन के योग्य बनाने और बरसात के बाद जरूरत के अनुसार उनका नवीनीकरण कराने के निर्देश दिए हैं।

शुक्रवार को लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि बारिश अभी जारी है, इसलिए सड़कों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जाए और बारिश से नए क्षतिग्रस्त मार्गों का भी सर्वे कराया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी पर्व-त्योहारों में बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन होगा। ऐसे में प्रमुख मार्गों पर आवागमन में किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने पर्वों से पहले

आवश्यक मरम्मत और नवीनीकरण के काम पूरे करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि गड्ढामुक्ति का काम केवल पैचवर्क तक सीमित न रहे, जहां सड़क तत्काल खराब स्थिति में है, वहां उसे अभी मोटरेबल बनाया जाए और बरसात समाप्त होने के बाद जरूरत के अनुसार स्थायी नवीनीकरण कराया जाए। बैठक में बताया गया कि अतिवृष्टि के साथ ही एक्सप्रेस-वे, राष्ट्रीय मार्ग, रेलवे आदि की निर्माणाधीन परियोजनाओं के कारण भारी वाहनों की आवाजाही से भी कई सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं।

इन मार्गों का विभागवार सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे के आधार पर क्षतिग्रस्त सड़कों को चिन्हित कर गड्ढामुक्ति के विभागवार लक्ष्य तय किए जाएंगे। आगामी पर्वों को देखते हुए प्रदेश में 681 महत्वपूर्ण मार्ग चिन्हित किए गए हैं। इनमें गणेश चतुर्थी, विश्वकर्मा पूजा, नवरात्रि, दीपावली, छठ पूजा और कार्तिक पूर्णिमा जैसे प्रमुख पर्वों के दौरान अधिक आवागमन वाले मार्ग शामिल हैं। इन मार्गों को प्राथमिकता के आधार पर बेहतर स्थिति में रखने की तैयारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क आम आदमी के रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ी है। शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों, मुख्य बाजारों, सरकारी कार्यालयों और ऐसे अन्य स्थानों, जहां आमजन का आवागमन अधिक रहता है, वहां की सड़कों को प्राथमिकता पर लिया जाए।

मुख्यमंत्री ने विभागों की कार्ययोजनाओं की समीक्षा

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों से भी उनकी कार्ययोजना की जानकारी ली। साथ ही मंडी परिषद, पंचायतीराज, सिंचाई, ग्राम्य विकास, नगर विकास, आवास व शहरी नियोजन तथा अवस्थापना व औद्योगिक विकास विभाग की कार्ययोजनाओं की समीक्षा की गई। उन्होंने सभी संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय के साथ काम करने पर जोर दिया। विभाग के प्रस्तुतिकरण में बताया गया कि गड्ढामुक्ति अभियान में 09 विभागों के मार्ग शामिल हैं। इन विभागों के अधीन करीब 4.36 लाख किलोमीटर सड़कें हैं। वर्तमान लक्ष्य के तहत करीब 50 हजार किलोमीटर मार्गों को गड्ढामुक्त किया जाना है, जिसमें अब तक करीब 5,751 किलोमीटर पर काम पूरा किया जा चुका है। क्षतिग्रस्त मार्गों के सर्वे के बाद विभागवार लक्ष्य को अंतिम रूप दिया जाएगा।

17 सितंबर को हिमाचल के आठ हजार बूथों पर जलेगा आशीर्वाद का दीया

बूथ स्तर पर व्यापक भागीदारी के साथ महीनेभर चलेगा भाजपा का सेवा संकल्प अभियान

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक एवं संवैधानिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी की ओर से देशभर में आयोजित किए जा रहे 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत हिमाचल प्रदेश में भी व्यापक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर होगी। इस अवसर पर प्रदेश के लगभग आठ हजार बूथों पर 'आशीर्वाद का दीया' कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 'आशीर्वाद का दीया' कार्यक्रम के प्रदेश संयोजक, जिला कांगड़ा प्रभारी, पूर्व उद्योग मंत्री एवं विधायक बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 25 वर्षों का सार्वजनिक जीवन सेवा, समर्पण, सुशासन और राष्ट्र निर्माण को समर्पित रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री वर्ष 2047 तक भारत को विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस लक्ष्य को हासिल करने में देश के प्रत्येक नागरिक की भूमिका महत्वपूर्ण है।

प्रत्येक बूथ पर जलेंगे करीब 100 दीप : बिक्रम सिंह ठाकुर ने बताया कि 17 सितंबर को हिमाचल के करीब आठ हजार बूथों पर 'आशीर्वाद का दीया' कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक बूथ पर लगभग 100 दीप प्रज्वलित करने की योजना है। माताएं-बहनें, युवा, बच्चे और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग दीप प्रज्वलित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु एवं यशस्वी जीवन की कामना करेंगे।

उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम केवल दीप प्रज्वलन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि प्रधानमंत्री के प्रति जनता के विश्वास और विकसित भारत के

संकल्प में जनभागीदारी का प्रतीक बनेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सार्वजनिक जीवन में देश को विकास, सुशासन, आत्मनिर्भरता और वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाने की दिशा में काम किया है।

17 संगठनात्मक जिलों में पूरी हुई कार्यशालाएं : बिक्रम सिंह ठाकुर ने बताया कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरी कार्ययोजना तैयार कर ली गई है। प्रदेश के सभी 17 संगठनात्मक जिलों में कार्यशालाएं पूरी हो चुकी हैं। बूथ स्तर तक कार्यक्रम को पहुंचाने के लिए टीमें गठित कर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। कार्यकर्ता समाज के विभिन्न वर्गों से संपर्क कर अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने में जुटे हैं।

लाभार्थियों के अनुभव भी किए जाएंगे साझा : उन्होंने कहा कि 'सेवा संकल्प अभियान' के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों से लाभान्वित लोगों के अनुभव भी सामने लाए जाएंगे। इसके लिए सेल्फी वीडियो और वीडियो संदेश तैयार किए जाएंगे। खिलाड़ी, युवा, महिलाएं, किसान और अन्य वर्गों के लोग अपने अनुभव साझा करेंगे तथा बताएंगे कि उन्हें विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किस प्रकार लाभ मिला।

कांग्रेस पर भी साधा निशाना : बिक्रम सिंह ठाकुर ने कांग्रेस की ओर से भाजपा के कार्यक्रमों को लेकर की जा रही टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनभागीदारी और राष्ट्र प्रथम की कार्यशैली को समझ नहीं सकती। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जब भी राष्ट्रहित में कोई आह्वान करते हैं, तो देशभर के लोग उसमें भागीदारी करते हैं। स्वच्छता अभियान, आत्मनिर्भर भारत और कोरोना काल में एकजुटता जैसे अभियानों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यही व्यापक जनभागीदारी भाजपा की कार्यशैली की पहचान है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य किसी एक वर्ग या परिवार तक सीमित नहीं, बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक के हित और भारत के उज्ज्वल भविष्य से जुड़ा है। 'आशीर्वाद का दीया' के माध्यम से हिमाचल की जनता भी उनके प्रति अपना विश्वास और समर्थन व्यक्त करेगी तथा 2047 तक विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगी।

पेंशनरों ने आत्माराम शर्मा के प्रतिनिधिमंडल संबंधी दावे को बताया भ्रामक और तथ्यहीन

अनीश सूद, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश ठाकुर और अतिरिक्त महासचिव भूपराम वर्मा ने कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित उस खबर का खंडन किया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश ज्वाइंट फ्रंट के स्वयंभू नेता आत्माराम शर्मा द्वारा मुख्यमंत्री से प्रतिनिधिमंडल के रूप में मुलाकात कर पेंशनरों की लंबित मांगों पर चर्चा करने का दावा किया गया है। समिति ने इस दावे को भ्रामक और तथ्यहीन बताते हुए इसका कड़ा विरोध किया है।

भूपराम वर्मा ने कहा कि 18 अगस्त 2026 की अधिसूचना को लेकर आत्माराम शर्मा द्वारा किया गया दावा तथ्यों के विपरीत है। उन्होंने कहा कि वित्त विभाग ने इस अधिसूचना के संबंध में 21 अगस्त 2026 को शुद्धि पत्र जारी कर दिया था। शुद्धि पत्र क्रमांक स्ब्ह्ड्-(ब्ह्ड्)(3)-1/2021-ब्ह्ड्ह्-2 के तहत प्रदेश के क्लास-3 श्रेणी के पेंशनरों को पिछले माह ही करीब 12 से 13 हजार रुपये की राशि उनके खातों में प्राप्त हो चुकी है।

समिति ने 18 सितंबर की बैठक में आंदोलन की रणनीति तय करने की बात कही।

उन्होंने कहा कि जब संबंधित राशि पेंशनरों को पहले ही जारी की जा चुकी है तो मुख्यमंत्री द्वारा इस मांग पर तत्काल प्रभाव से आदेश जारी किए जाने का दावा करना सही नहीं है। समिति का कहना है कि इस तरह की जानकारी सार्वजनिक किए जाने से पेंशनरों में भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है।

स्वयंभू नेतृत्व पर उठाए सवाल: वर्मा ने कहा कि प्रदेश के करीब 1.90 लाख पेंशनरों ने किसी भी स्वयंभू नेता को मुख्यमंत्री के साथ बैठक या वार्ता के लिए अधिकृत नहीं किया है। उन्होंने दावा किया कि एक सितंबर 2026 को शिमला में भी ऐसे नेतृत्व का विरोध किया गया था। समिति ने 14 सितंबर को सचिवालय में प्रस्तावित बैठक को लेकर भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि पेंशनरों की ओर से वार्ता के लिए अधिकृत प्रतिनिधित्व स्पष्ट होना चाहिए।

डीए मामले में अपील की आशंका : भूपराम वर्मा ने आशंका जताई कि प्रदेश उच्च न्यायालय के हालिया फैसले में महंगाई भत्ते की अदायगी से जुड़े मामले में सरकार आगे अपील कर सकती है। यदि ऐसा होता है तो डीए का मामला न्यायालय में लंबित रह सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में आम जनता से प्राप्त कर राशि का एक हिस्सा लंबी कानूनी प्रक्रिया में खर्च होगा, जबकि पेंशनर अपने लंबित वित्तीय लाभों की प्रतीक्षा करते रहेंगे।

हिमाचली संस्कृति की कहानी कहेगी फिल्म 'खूंटा', 18 सितंबर को देशभर में होगी रिलीज

अनीश सूद, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश की संस्कृति, लोक परंपराओं, आस्था और पहाड़ी जीवन को बड़े पर्दे के माध्यम से देश-दुनिया तक पहुंचाने वाली फिल्म 'खूंटा' 18 सितंबर को पूरे भारत में रिलीज होने जा रही है। फिल्म की रिलीज से पहले शुक्रवार को कलाकारों और टीम ने प्रेस वार्ता कर फिल्म की कहानी, उद्देश्य और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिली पहचान की जानकारी साझा की।

फिल्म की टीम के अनुसार 'खूंटा' हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की लोक संस्कृति, परंपराओं, गीत-संगीत और पहाड़ के जीवन को केंद्र में रखकर बनाई गई है। फिल्म में प्रकृति, आस्था और बदलते समय के बीच अपनी सांस्कृतिक पहचान को बचाए रखने की कहानी दिखाई गई है। इसमें पहाड़, नदियां और जंगल केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि स्थानीय लोगों के जीवन और भावनाओं से जुड़े अभिन्न हिस्से के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं।

महासू महाराज के प्रति आस्था को प्रमुखता : फिल्म में महासू महाराज के प्रति लोगों की आस्था को भी प्रमुख स्थान दिया गया है। कहानी के माध्यम से पहाड़ी समाज की धार्मिक मान्यताओं, लोक परंपराओं और प्रकृति के साथ उसके गहरे संबंध को सामने लाने का प्रयास किया गया है। टीम का कहना है कि फिल्म का उद्देश्य दर्शकों को पहाड़ की संस्कृति से परिचित कराने के साथ युवा पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ना भी है। 'खूंटा' को हिमाचल प्रदेश की पहली ऐसी फीचर फिल्म बताया गया है, जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली है।

सड़क चौड़ीकरण की राह में अतिक्रमण बना बाधा, विभाग सख्त

भारतेन्दु संवाददाता, कुनिहार। पेट्रोल पंप से कोठी चौक तक प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण को लेकर लोक निर्माण विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। विभाग ने सड़क की निर्धारित सीमा में किए गए अतिक्रमण और अन्य अवरोधों को स्वयं हटाने की अपील की है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि समय रहते अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। लोक निर्माण विभाग अर्की के अधिशासी अभियंता केके चौहान के निर्देश पर कुनिहार के सहायक अभियंता मनसा राम ने क्षेत्रवासियों से सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि सड़क की जमीन पर सामान, निर्माण सामग्री अथवा अन्य वस्तुएं रखने वाले लोग इन्हें जल्द हटा लें। इसके अलावा सड़क सीमा में किए गए किसी भी प्रकार के निर्माण या अवरोध को भी स्वयं हटाने के निर्देश दिए गए हैं।

शिमला में बैंक कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल, जोरदार प्रदर्शन

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) के आह्वान पर शुक्रवार को आयोजित देशव्यापी बैंक हड़ताल का शिमला में भी व्यापक असर देखने को मिला। डीसी ऑफिस चौक में आयोजित धरने में 300 से अधिक बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों ने भाग लेकर अपनी विभिन्न लंबित मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की। कर्मचारियों ने सरकार और बैंक प्रबंधन से लंबित मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने की मांग की।

पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करने की मांग : यूनियन नेताओं ने कहा कि पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करने को लेकर इंडियन बैंक्स एसोसिएशन और बैंक यूनियनों के बीच मार्च 2024 में समझौता हो चुका है। इसके बावजूद लंबे समय से इस व्यवस्था को लागू नहीं किया गया है।

नेताओं के अनुसार, कई बार आश्वासन मिलने के बाद भी मांग पर ठोस निर्णय नहीं होने से बैंक कर्मचारियों में रोष है।

प्रदर्शन मूल्यांकन व्यवस्था पर आपत्ति : यूएफबीयू ने एकतरफा और भेदभावपूर्ण प्रदर्शन मूल्यांकन व्यवस्था पर भी आपत्ति जताई। यूनियन नेताओं ने कहा कि कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रदर्शन का आकलन पारदर्शी, निष्पक्ष और समान मानकों के आधार पर किया जाना चाहिए। उन्होंने बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े अन्य लंबित मुद्दों के समाधान के लिए द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से सार्थक चर्चा शुरू करने की मांग भी उठाई।

नेताओं ने कहा कि पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू होने से ग्राहकों को बड़ी परेशानी नहीं होगी। वर्तमान समय में एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और यूपीआई जैसी डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध हैं। कर्मचारियों ने मांगों के समर्थन में एक दिन का वेतन त्याग कर हड़ताल में भाग लिया।

जिला परिषद नतीजों पर कांग्रेस करे आत्ममंथन : रोहित ठाकुर

विधानसभा चुनाव से पहले संगठन की कमियों को दूर कर, संगठन को तैयार करेगी कांग्रेस

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। शिमला जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर भारतीय जनता पार्टी की जीत को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कांग्रेस के लिए निराशाजनक बताया है। उन्होंने कहा कि शिमला जिला लंबे समय से कांग्रेस का मजबूत क्षेत्र रहा है। ऐसे में पंचायतीराज चुनावों के परिणाम पार्टी के लिए आत्ममंथन का विषय हैं। कांग्रेस को गंभीरता से समीक्षा करनी होगी कि किन क्षेत्रों में संगठन कमजोर रहा और किन कारणों से पार्टी अपेक्षित परिणाम हासिल नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि कमियों की पहचान कर उन्हें दूर करने के साथ संगठन को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

जिला परिषद के परिणामों पर होगा मंथन : रोहित ठाकुर ने शुक्रवार को कहा कि शिमला जिले में कांग्रेस की मजबूत राजनीतिक पकड़ और नेतृत्व रहा है। जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि यहां से सभी जिला परिषद सदस्य कांग्रेस के जीतकर आए हैं। हालांकि जिले के अन्य विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी को उम्मीद के अनुरूप परिणाम नहीं मिल सकी। इसका परिणाम जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में भी देखने को मिला। उन्होंने कहा कि पार्टी परिणामों का विश्लेषण करेगी और यह पता लगाया जाएगा कि कहां कमी रही।

संगठन को मजबूत करने पर जोर : शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिला परिषद के चुनाव परिणामों को कांग्रेस ने स्वीकार किया है। पार्टी आगामी समय में अपनी कमियों को दूर कर संगठन को और मजबूत करेगी। इस संबंध में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के साथ भी चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में अब करीब एक वर्ष का समय शेष है। इसलिए पार्टी के पास अपनी तैयारियों को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर संगठन को सक्रिय करने का पर्याप्त अवसर है। उन्होंने कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच बेहतर समन्वय को भी जरूरी बताया।

दिल्ली में सरकार और संगठन पर चर्चा : अपने दिल्ली दौरे के संबंध में रोहित ठाकुर ने कहा कि शिक्षा विभाग से संबंधित उनका कार्यक्रम पहले से निर्धारित था। इसी सिलसिले में वह दिल्ली गए थे। उन्होंने कहा कि दिल्ली जाने के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और अन्य नेताओं से मुलाकात होना स्वाभाविक है। इस दौरान हिमाचल प्रदेश में सरकार और संगठन से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि कुछ अन्य मंत्री भी दिल्ली में मौजूद थे और सरकार के चार साल के कार्यकाल को लेकर भी बातचीत हुई।

आंतरिक विषय सार्वजनिक नहीं किए जा सकते : रोहित ठाकुर ने कहा कि पार्टी और सरकार से जुड़े कुछ विषय आंतरिक होते हैं और उन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। उन्होंने दिल्ली में हुई चर्चाओं को लेकर किसी तरह की अटकलों पर टिप्पणी करने से भी इनकार किया। उन्होंने कहा कि संगठन और सरकार से संबंधित विषयों पर पार्टी के स्तर पर लगातार विचार-विमर्श होता रहता है। इसका उद्देश्य आगामी समय में सरकार और संगठन के कामकाज को बेहतर बनाना है।

कैबिनेट बैठक स्थगित होने पर सफाई : कैबिनेट बैठक के अचानक स्थगित होने को लेकर रोहित ठाकुर ने मंत्रियों के बीच किसी तरह के मतभेद या मनमुटाव से साफ इनकार किया। उन्होंने कहा कि सभी मंत्री कैबिनेट बैठक में हिस्सा लेने के लिए शिमला पहुंचे थे। बाद में बैठक स्थगित कर दी गई।

शिमला में टीबी उन्मूलन अभियान को मिली बड़ी सफलता, 141 पंचायतें हुई मुक्त

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। जिला स्तरीय टीबी मुक्त अभियान समिति की बैठक उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में हुई। बैठक में बताया गया कि जनवरी से अगस्त 2026 तक जिले में टीबी की पहचान, जांच, उपचार और मरीजों को सहायता उपलब्ध कराने के क्षेत्र में बेहतर प्रगति दर्ज की गई है।

लक्ष्य से अधिक लोगों की हुई जांच : प्रिजम्प्टिव टीबी जांच के निर्धारित 24,408 के लक्ष्य के मुकाबले 28,008 लोगों की जांच की गई, जो 115 प्रतिशत उपलब्धि है। टीबी मरीजों की पहचान के लिए निर्धारित 1,387 के लक्ष्य के मुकाबले 1,393 मरीजों को अधिसूचित किया गया। एचआईवी और रक्त शर्करा जांच में 98-98 प्रतिशत उपलब्धि रही। वहीं रिफैम्पिसिन प्रतिरोध जांच में 96 प्रतिशत, उपचार सफलता दर में 92 प्रतिशत और डीआरटीबी उपचार शुरू करने में 95 प्रतिशत उपलब्धि दर्ज की गई।

पंचायत प्रतिनिधियों और विद्यार्थियों को जोड़ा जाएगा : उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि नए पंचायत प्रतिनिधियों को टीबी मुक्त अभियान के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाएगा। राष्ट्रीय कैडेट कोर और राष्ट्रीय सेवा योजना के विद्यार्थियों को भी अभियान से जोड़ा जाएगा, ताकि वे लोगों को टीबी के लक्षण, जांच और उपचार के प्रति जागरूक कर सकें। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों की जांच सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

पांच माह में 28 मरीजों की मृत्यु : अप्रैल से अगस्त 2026 के बीच जिले में 674 टीबी मरीजों में से 28 की मृत्यु हुई। शिमला शहरी क्षेत्र में 145 मरीजों में 11 मौतें दर्ज हुईं। मशोबरा में 153 मरीजों में पांच, रामपुर में 112 में चार और मतियाना में 47 में तीन मरीजों की मृत्यु हुई। प्रशासन ने समय पर जांच, नियमित उपचार और पोषण सहायता पर विशेष जोर दिया है।

शिमला में 14 सितंबर को कैंपस इंटरव्यू, युवाओं को मिलेगा रोजगार

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। जिला रोजगार कार्यालय शिमला की ओर से युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए 14 सितंबर 2026 को कैंपस इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। साक्षात्कार शिवा इंटरनेशनल, गांव एवं डाकघर मंझोली, तहसील नालागढ़, जिला सोलन में सुबह 11 बजे होगा। जिला रोजगार अधिकारी प्रवीन नगराईक ने बताया कि कैंपस इंटरव्यू के माध्यम से हेल्पर के पांच, ऑपरेटर के दो और फोरमैन के तीन पदों पर भर्ती की जाएगी। हेल्पर पद के लिए 10+2 तथा ऑपरेटर और फोरमैन पदों के लिए आईटीआई या डिप्लोमा आवश्यक है। हेल्पर को 12,750 रुपये, ऑपरेटर को 13,560 रुपये और फोरमैन को 15,390 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलेगा। सभी पदों के लिए आयु सीमा 20 से 28 वर्ष निर्धारित है तथा पुरुष और महिला दोनों अभ्यर्थी पात्र होंगे। इच्छुक उम्मीदवारों का जिला रोजगार कार्यालय में ऑनलाइन पंजीकरण होना अनिवार्य है।

सवाल शिवानी ठाकुर ने 26 पंचायतों के जनादेश की अनदेखी पर सरकार से मांगा जवाब

एचआईवी संक्रमितों से भेदभाव खत्म करना सामूहिक जिम्मेदारी : कश्यप

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में एड्स जागरूकता एवं रोकथाम को लेकर जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में एड्स सुरक्षा, जिला एड्स रोकथाम एवं नियंत्रण समिति तथा जिला सामुदायिक संसाधन समूह की गतिविधियों की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने कहा कि एचआईवी/एड्स की रोकथाम, जागरूकता बढ़ाने और समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित विभागों एवं संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है।

संक्रमित व्यक्तियों को मिले सामाजिक सहयोग : अनुपम कश्यप ने कहा कि एचआईवी/एड्स की रोकथाम के लिए जागरूकता सबसे प्रभावी माध्यम है। लोगों तक सही और वैज्ञानिक जानकारी पहुंचाकर बीमारी से जुड़ी भ्रांतियों को दूर किया जा सकता है। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि जागरूकता कार्यक्रमों को व्यापक स्तर पर संचालित किया जाए और समाज के सभी वर्गों तक आवश्यक जानकारी पहुंचाई जाए। उन्होंने कहा कि एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों के प्रति भेदभाव और सामाजिक कलंक को समाप्त करना भी सामूहिक जिम्मेदारी है। लोगों को संक्रमित

व्यक्तियों के साथ संवेदनशील और सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए।

जांच और उपचार सेवाओं पर जोर : बैठक में जोखिम वाले समूहों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने, परामर्श एवं जांच सेवाओं को प्रभावी बनाने तथा एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों को आवश्यक स्वास्थ्य एवं सामाजिक सहयोग उपलब्ध कराने पर चर्चा हुई। उपायुक्त ने लोगों से अपील की कि एचआईवी/एड्स से संबंधित किसी भी प्रकार की भ्रांति पर विश्वास न करें और आवश्यकता होने पर समय पर जांच एवं उपचार सेवाओं का लाभ उठाएं। बैठक में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिले में संचालित गतिविधियों की भी समीक्षा की गई।

2.15 लाख बच्चों को दी जाएगी दवा

अभियान के तहत एक से 19 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को कृमिनाशक दवा एल्बेंडाजोल दी जाएगी। वहीं एक से पांच वर्ष तक के बच्चों को विटामिन-ए की खुराक भी दी जाएगी। पांच से 19 वर्ष तक के बच्चों को स्कूलों के माध्यम से अभियान में शामिल किया जाएगा, जबकि एक से पांच वर्ष के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से कवर किया जाएगा। स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास तथा शिक्षा विभाग संयुक्त रूप से अभियान का संचालन करेंगे।

जिले में व्यापक तैयारी : जिला शिमला में अभियान के लिए 2,105 सरकारी और 450 निजी स्कूलों के साथ 2,154 आंगनबाड़ी केंद्र तथा 997 आशा कार्यकर्ताओं को जोड़ा गया है। एक से 19 वर्ष आयु वर्ग के 2,15,738 बच्चों को एल्बेंडाजोल देने का लक्ष्य रखा गया है।

विकासनगर हिमुडा परिसर से बेहतर कनेक्टिविटी की उठी मांग

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। विकासनगर में निर्माणाधीन हिमुडा वाणिज्यिक परिसर को आसपास के क्षेत्रों से बेहतर तरीके से जोड़ने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग उठी है। प्रबुद्ध नागरिक मंच विकासनगर ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर परियोजना की मुख्य योजना में वैकल्पिक संपर्क मार्ग, आपातकालीन निकास और निचले क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़क को शामिल करने का आग्रह किया है। मंच के पदाधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग-5 के किनारे विकसित किया जा रहा यह महत्वाकांक्षी परिसर 17 और 14 मंजिला इमारतों के साथ तैयार हो रहा है। परिसर में छत पर हेलीकॉप्टर उतरने की सुविधा भी प्रस्तावित है। भविष्य में यहां बड़ी संख्या में लोगों और वाहनों की आवाजाही बढ़ने की संभावना है। ऐसे में केवल राष्ट्रीय राजमार्ग की ओर से एक प्रवेश मार्ग रखना सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं होगा। नागरिक मंच ने परियोजना स्थल से नीचे पहाड़ी क्षेत्र की ओर मौजूद अधूरे सड़क मार्ग को विकसित कर विधिवत सड़क से जोड़ने की मांग की है। इससे निचला विकासनगर, आंजी और आसपास के क्षेत्रों को सीधा संपर्क मिल सकेगा। मंच का कहना है कि निर्माण कार्य के दौरान इस रास्ते को बंद करने के बजाय इसे परियोजना का हिस्सा बनाकर विकसित किया जाना चाहिए।

◆ परिसर के लिए वैकल्पिक मार्ग और आपात निकास बनाने पर जोर

रिज मैदान में सवारी को लेकर टैक्सी चालकों में मारपीट, सात गिरफ्तार

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। राजधानी शिमला के प्रसिद्ध रिज मैदान में एक व्यक्ति के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सात लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस थाना सदर शिमला ने सभी आरोपियों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम की निवारक धाराओं के तहत कार्रवाई की है।

पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मारपीट की घटना में शामिल दोनों पक्ष टैक्सी चालक हैं। दोनों पक्षों के बीच सवारी को लेकर पहले से विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते शुक्रवार को रिज मैदान में दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और उनके बीच मारपीट हो गई। इस दौरान एक व्यक्ति के साथ मारपीट की गई, जिसका किसी

व्यक्ति ने वीडियो बना लिया। बाद में यह वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो गया और तेजी से वायरल होने लगा।

◆ वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी को पकड़ा

वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। पुलिस थाना सदर की टीम ने घटना में शामिल लोगों की पहचान कर सभी सात लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस का कहना है कि इन लोगों के कारण कानून-व्यवस्था और लोक शांति भंग होने की आशंका को देखते हुए निवारक कार्रवाई की गई है।

पुलिस मामले में मारपीट की वजह और दोनों पक्षों के बीच चल रहे पुराने विवाद की भी जांच कर रही है। सवारी को लेकर विवाद कब से चल रहा था और घटना के दौरान वास्तव में क्या परिस्थितियां बनीं, इसे लेकर पुलिस संबंधित लोगों से पूछताछ कर रही है। घटना से जुड़े अन्य तथ्यों को भी जांच में शामिल किया गया है।

पौड़ी परिसर में छात्रसंघ चुनाव में एनएसयूआई का दबदबा

भारतेंदु संवाददाता, पौड़ी गढ़वाल। बीजीआर परिसर में हुए छात्रसंघ चुनाव के परिणामों में एनएसयूआई का दबदबा देखने को मिला। एनएसयूआई ने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, कोषाध्यक्ष के साथ ही तीन कार्यकारिणी सदस्यों के पदों पर जीत हासिल की। मुख्य चुनाव अधिकारी प्रो.पियूष सिंहा ने बताया कि अध्यक्ष पद पर एनएसयूआई के आयुष थापलियाल ने 382 मत हासिल कर जीत दर्ज की, जबकि एबीवीपी की अनीषा को 166 मत मिले। आयुष ने 216 मतों से जीत हासिल की। सचिव पद पर एनएसयूआई के ऋषभ कुमार को 317 तो आर्यन के करन कुमार को 223 मत मिले। ऋषभ ने 94 मतों से जीत दर्ज की। कोषाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई की अमीषा नेगी को 343 व एबीवीपी की सृष्टि रावत को 188 वोट मिले। अमीषा ने 155 मतों से जीत हासिल की। वहीं, उपाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई के रविंद्र नेगी, सहसचिव पद पर एनएसयूआई की सोनम, विवि प्रतिनिधि पद पर सारदुल गुसांई ने निर्विरोध जीत हासिल की। इसके साथ ही कार्यकारिणी सदस्य में एबीवीपी की अक्षरा नेगी, एनएसयूआई की आयुषी, मानसी डंगवाल व सोनी ने बाजी मारी।

17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा सेवा संकल्प अभियान : सीएम धामी

युवाओं, महिलाओं और आम नागरिकों को जोड़ेगा सेवा संकल्प अभियान

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून

उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में पत्रकार वार्ता में कहा कि अभियान के माध्यम से सेवा, जनभागीदारी, संवाद और नवाचार को केंद्र में रखते हुए प्रदेशवासियों को 'विकसित भारत 2047' के संकल्प से जोड़ा जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान के तहत 11 प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें विद्यार्थी, युवा, महिलाएं, लाभार्थी, अभिभावक, जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन और आम नागरिक भाग लेंगे। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से लोगों के जीवन में आए बदलाव तथा लाभार्थियों की कहानियों को भी प्रमुखता से सामने लाया जाएगा।

उन्होंने बताया कि 'आशीर्वाद का दीया' कार्यक्रम के तहत सरकारी योजनाओं के केंद्र, गैस वितरण केंद्रों, राशन दुकानों, धार्मिक स्थलों और गंगा तट सहित विभिन्न स्थानों पर दीप प्रज्वलन एवं सामूहिक कार्यक्रम होंगे।

विशेषज्ञ करेंगे नवाचारों का मूल्यांकन

मुख्यमंत्री ने बताया कि 'सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज' के तहत विभागों से वास्तविक जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए नवाचार आमंत्रित किए जाएंगे। विशेषज्ञों को ज्यूरी एवं मेंटर के रूप में जोड़ा जाएगा। वहीं 'सुशासन सेवा संवाद' के तहत जनप्रतिनिधियों के साथ सेवा और सुशासन के विषय पर संवाद किया जाएगा।

अभियान में होंगे कार्यक्रम

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बताया है। इस संकल्प को जनभागीदारी से आगे बढ़ाया जाएगा। विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी।

स्वास्थ्य और बहुउद्देशीय शिविरों का होगा आयोजन

'मेरे सपनों का भारत-चित्र सेवा' के तहत शैक्षणिक संस्थानों में चित्रकला, निबंध और भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। 'नमो सेवा-अनकही कहानियां' के माध्यम से विद्यालयों में देश की उपलब्धियों पर आधारित नाटकों का मंचन होगा। 'आंगन मिलन सेवा' के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों, अभिभावकों, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं की सहभागिता से गतिविधियां आयोजित होंगी तथा मातृ-बाल स्वास्थ्य और पोषण पर जोर दिया जाएगा। धामी ने कहा कि 'सेवा की कहानियों' के माध्यम से सरकारी योजनाओं से हुए वास्तविक बदलावों को जनता तक पहुंचाया जाएगा। 'सेवा ज्योति कलश यात्रा' में 'विकसित भारत 2047' से संबंधित कलश की स्थापना के साथ साइकिल और बाइक यात्रा भी प्रस्तावित है। 'सेवा : मेरा योगदान' कार्यक्रम के जरिए नागरिकों को वृक्षारोपण, स्वच्छता, शिक्षण और अन्य समाजोपयोगी गतिविधियों से जोड़ा जाएगा। 'सेवा सेतु' के तहत 'जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' कार्यक्रम में शिविर लगाकर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। स्वास्थ्य और बहुउद्देशीय शिविर भी लगाए जाएंगे।

पीएमकेएसवाई में करोड़ों खर्च फिर भी किसानों के खेत सूखे

करोड़ों खर्च के बावजूद कई जिलों में बंद पड़े ड्रिप सिस्टम

अनिल थपलियाल

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप' का उद्देश्य कम पानी में अधिक उत्पादन हासिल करना और किसानों के खेतों तक सिंचाई की सुविधा पहुंचाना है। ड्रिप सिंचाई जैसी आधुनिक तकनीक से पानी की हर बूंद का बेहतर उपयोग हो सकता है, लेकिन उत्तराखंड में इस योजना के क्रियान्वयन को लेकर सामने आ रही शिकायतें गंभीर चिंता पैदा करती हैं। आरोप है कि योजना पर करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद कई क्षेत्रों में किसानों को इसका वास्तविक लाभ नहीं मिल पाया। देहरादून सहित विभिन्न जिलों में सामने आई शिकायतों के बाद अब इस व्यवस्था की जमीनी स्थिति पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

आरटीआई से प्राप्त दस्तावेजों का हवाला देते हुए अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं। बताया गया है कि कई जगह किसानों को ड्रिप सिंचाई के उपकरण तो उपलब्ध कराए गए, लेकिन उनकी उचित स्थापना, परीक्षण और संचालन का प्रशिक्षण नहीं दिया गया। पौड़ी गढ़वाल में कुछ पुराने सिस्टम तकनीकी सहायता और रखरखाव के अभाव में बंद हो गए। कहीं खेतों में केवल ड्रिप पाइप के अवशेष दिखाई देते हैं तो कहीं सामग्री पहुंचने के बावजूद पूरी व्यवस्था स्थापित नहीं की गई। रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ में भी किसानों को पाइप, फिल्टर और ड्रिपर जैसी सामग्री मिलने की बात सामने आई, लेकिन स्थापना और प्रशिक्षण के अभाव में किसान उसका प्रभावी उपयोग नहीं कर सके।

सरकारी खर्च का जमीनी लाभ दिखना जरूरी

सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि किसी किसान को आधुनिक सिंचाई उपकरण उपलब्ध कराने के बाद उसके संचालन और रखरखाव की जानकारी ही नहीं दी जाएगी, तो उस पर किया गया सरकारी खर्च किस हद तक उद्देश्यपूर्ण माना जाएगा। किसी योजना की सफलता केवल धनराशि खर्च करने या उपकरण वितरित करने से तय नहीं हो सकती।

मजिस्ट्रेटी जांच से सच आएगा सामने

देहरादून के जिलाधिकारी द्वारा मजिस्ट्रियल जांच के आदेश इस मामले की सच्चाई सामने लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। जांच में यह स्पष्ट होना चाहिए कि धन कहां खर्च हुआ, उपकरण कहां लगाए गए, कितने किसान वास्तव में लाभान्वित हुए और किन कारणों से व्यवस्थाएं बंद पड़ी हैं। दोषी पाए जाने वालों की जवाबदेही तय करने के साथ यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि भविष्य में योजनाएं कागजों पर नहीं, बल्कि खेतों में परिणाम देती दिखाई दें।

रतूड़ा पुलिस लाइन में साप्ताहिक परेड, एसपी ने किया निरीक्षण

अनिल थपलियाल, रुद्रप्रयाग। रिजर्व पुलिस लाइन रतूड़ा में शुक्रवार को साप्ताहिक पुलिस परेड आयोजित हुई। पुलिस अधीक्षक नीहारिका तोमर ने परेड का निरीक्षण कर जवानों का उत्साहवर्धन किया। इस दौरान जवानों ने दौड़, शारीरिक व्यायाम, टोलीवार ड्रिल और मार्च पास्ट का अभ्यास किया। आपात परिस्थितियों में तत्परता बनाए रखने के लिए शस्त्र संचालन, हैंडलिंग और सुरक्षा मानकों पर आधारित आर्म्स-ड्रिल भी कराई गई। परेड के बाद एसपी ने पुलिस लाइन की विभिन्न शाखाओं और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने शस्त्रागार में हथियारों व गोला-बारूद की सुरक्षा और रखरखाव की स्थिति देखी। परिवहन शाखा में वाहनों के रखरखाव, ईंधन व्यवस्था व अभिलेखों की जांच की। मेस और बैरकों में भोजन, पेयजल व स्वच्छता व्यवस्था की समीक्षा करते हुए बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नियमित परेड से जवानों की शारीरिक दक्षता, अनुशासन, टीम भावना और कार्य तत्परता मजबूत होती है।

यूपीईएस में साइबर सुरक्षा पर हुआ मंथन

साइबर खतरों से निपटने को यूपीईएस में जुटे देश-विदेश के विशेषज्ञ

विशेषज्ञों की समीक्षा में खरे उतरे 186 शोधपत्र, प्रस्तुति के लिए चयनित

अनिल थपलियाल

देहरादून। यूपीईएस में अंतरराष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और डिजिटल फॉरेंसिक्स सम्मेलन-2026 का आयोजन किया गया। इसमें देश-विदेश के प्रमुख शोधकर्ताओं, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों, उद्योग प्रतिनिधियों और छात्रों ने हिस्सा लेकर उभरते साइबर खतरों और डिजिटल अपराधों से निपटने के उपायों पर चर्चा की। स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस, यूपीईएस की ओर से आयोजित सम्मेलन को आईईईई उत्तर प्रदेश सेक्शन ने प्रायोजित किया।

सम्मेलन का उद्देश्य मौलिक शोध को बढ़ावा देने, तकनीकी ज्ञान साझा करने और शिक्षा जगत तथा उद्योग के बीच सहयोग मजबूत करना रहा। सम्मेलन के लिए 892 शोधपत्र प्राप्त हुए, जिनमें से दुनिया भर के विशेषज्ञों की समीक्षा के बाद 186 शोधपत्रों को प्रस्तुति के लिए स्वीकार किया गया।

सम्मेलन में साइबर सुरक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग, साइबर खतरा खुफिया, डिजिटल फॉरेंसिक्स, क्वांटम और पोस्ट-क्वांटम कूटलेखन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स सुरक्षा, ब्लॉकचेन, सॉफ्टवेयर एवं वेब सुरक्षा, घटना प्रतिक्रिया तथा शासन, जोखिम और अनुपालन जैसे विषयों पर मंथन हुआ।

साइबर सुरक्षा डिजिटल युग की मजबूत नींव : राज्यपाल

सम्मेलन के मुख्य अतिथि उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने साइबर सुरक्षा को देश के विकास, तकनीकी प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय बताया। उन्होंने सम्मेलन के आयोजन के लिए यूपीईएस को बधाई दी। यूपीईएस के कुलपति डॉ. सुनील राय ने कहा कि तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर मजबूती भरोसेमंद भविष्य की बुनियाद है। सम्मेलन में ऑकलैंड विश्वविद्यालय, बॉयसी स्टेट विश्वविद्यालय, आईआईटी खड़गपुर, आईआईईएसटी शिबपुर, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता और आईआईटी रुड़की समेत कई प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञ शामिल हुए।

बैंक कर्मचारियों ने फाइव-डे बैंकिंग और पीएलआई में समानता की मांग उठाई

2012 से लंबित फाइव-डे बैंकिंग की मांग पर बैंक कर्मचारियों का प्रदर्शन

अनिल थपलियाल

देहरादून। फाइव-डे बैंकिंग लागू करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर बैंक कर्मचारियों ने शुक्रवार को एक दिवसीय हड़ताल कर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने कहा कि वे हड़ताल और प्रदर्शन के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन लंबे समय से उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने के कारण आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। कर्मचारियों ने सरकार से फाइव-डे बैंकिंग लागू करने और परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) से जुड़ी विसंगतियों को दूर करने की मांग की।

कहा- स्केल-1 और 2 कर्मचारियों को कम लाभ

कर्मचारियों के अनुसार फाइव-डे बैंकिंग की मांग वर्ष 2012 से चली आ रही है। वर्ष 2015 में महीने के दो शनिवार को अवकाश घोषित किया गया था। उस समय आगे सभी शनिवार को छुट्टी देने का आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन करीब एक दशक बीतने के बाद भी यह मांग पूरी नहीं हुई। कर्मचारियों का कहना है कि वर्ष 2024 के वेतन समझौते के दौरान भी फाइव-डे बैंकिंग जल्द लागू करने की बात कही गई थी। इसके बावजूद इस दिशा में अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। इससे बैंक कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा है। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने पीएलआई की व्यवस्था में असमानता का मुद्दा भी उठाया। उनका कहना था कि बैंक के निचले स्तर पर कार्यरत कर्मचारी और अधिकारी ग्राहकों को लगातार सेवाएं देने के साथ देर शाम तक काम करते हैं, लेकिन उन्हें पीएलआई का अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा है। कर्मचारियों के मुताबिक स्केल-3 और उससे ऊपर के अधिकारियों के लिए पीएलआई की व्यवस्था की गई है, जबकि स्केल-1 और 2 के अधिकारियों, क्लर्क तथा अन्य कर्मचारियों को अपेक्षाकृत कम लाभ दिया गया है।

सातताल में स्टर्लिंग का नया रिसोर्ट लॉन्च, प्रदेश में कंपनी के 12 रिसोर्ट हुए

अनिल थपलियाल, नैनीताल। स्टर्लिंग हॉलीडे रिसोर्ट्स ने उत्तराखंड में अपना नया स्टर्लिंग लेक व्यू सातताल रिसोर्ट शुरू किया है। इसके साथ राज्य में कंपनी के रिसोर्ट्स की संख्या 12 और देशभर में 80 हो गई है। सातताल अपनी सात मीठे पानी की झीलों और वन क्षेत्र से घिरी पहाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। रिसोर्ट से भीमताल, नैनीताल, कैंची धाम और नौकुचियाताल आसानी से पहुंचा जा सकता है। कंपनी के प्रबंध निदेशक विक्रम लालवानी ने कहा कि सातताल में झील और जंगल का संगम स्टर्लिंग के उत्तराखंड नेटवर्क को नया आयाम देगा। साझेदार अभिजीत अग्रवाल और समर्थ अग्रवाल ने कहा कि रिसोर्ट की झील किनारे की विशेष स्थिति के साथ ब्रांड की आतिथ्य सुविधाओं का लाभ पर्यटकों को मिलेगा।

देवराड़ा में 25 सितंबर को होगा मां नंदा देवी की डोली का भव्य स्वागत

अनिल थपलियाल

थराली/देवराड़ा। मां नंदा देवी की डोली के 25 सितंबर 2026 को देवराड़ा पहुंचने को लेकर मंदिर समिति और स्थानीय लोगों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। शुक्रवार को देवराड़ा मंदिर परिसर में बैठक आयोजित कर डोली के भव्य स्वागत और प्रस्तावित धार्मिक कार्यक्रमों की व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में मंदिर परिसर की आकर्षक सजावट, फूलों की व्यवस्था, श्रद्धालुओं के लिए भंडारा और सुरक्षा इंतजामों को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

डोली के आगमन पर मंदिर परिसर को फूलों से सजाने के साथ टेंट और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं करने पर सहमति बनी। समिति की ओर से अलग-अलग व्यवस्थाओं की जिम्मेदारियां तय करने का निर्णय लिया गया, ताकि कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। भंडारे के आयोजन को लेकर भी आवश्यक तैयारियां करने पर सहमति बनी।

बैठक में सुरक्षा व्यवस्था को विशेष प्राथमिकता दी गई। डोली के स्वागत के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने और कार्यक्रम को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग से आवश्यक सहयोग लेने पर चर्चा हुई। समिति पदाधिकारियों ने कहा कि मां नंदा देवी की डोली का स्वागत भव्य और धार्मिक परंपराओं के अनुरूप किया जाएगा। इसके लिए मंदिर समिति, स्थानीय लोग और अन्य संबंधित लोग मिलकर सभी तैयारियों को समय पर पूरा करेंगे। बैठक में मौजूद लोगों ने आयोजन को सफल बनाने के लिए आपसी सहयोग और समन्वय के साथ कार्य करने पर जोर दिया।

भाजपा की कथनी और करनी में अंतर : धस्माना

भारतेंदु संवाददाता, कोटद्वार

कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं एआईसीसी सदस्य सूर्यकांत धस्माना ने भाजपा पर विकास, सुशासन और सामाजिक समरसता के मुद्दों पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है।

कोटद्वार में पत्रकार वार्ता में धस्माना ने कहा कि प्रदेश में पिछले 10 वर्षों से भाजपा की सरकार है, लेकिन विकास के विभिन्न मानकों पर स्थिति संतोषजनक नहीं है। उन्होंने हरिद्वार मेडिकल कॉलेज को पीपीपी मोड पर संचालित किए जाने को लेकर भी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।

कानून-व्यवस्था को लेकर उन्होंने आरोप लगाया कि महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं और देहरादून में हत्या, लूट व डकैती की घटनाएं चिंता का विषय हैं। उन्होंने प्रदेश में सड़कों, पुलों और यातायात व्यवस्था की स्थिति पर भी सवाल उठाए।

सामाजिक समरसता के मुद्दे पर धस्माना ने हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद रामलीला मैदान के शुद्धिकरण की घटना का उल्लेख करते हुए भाजपा पर धार्मिक ध्रुवीकरण का आरोप लगाया।

हरिद्वार में नशे पर अंकुश लगाने की मांग एसएसपी को ज्ञापन

भारतेंदु संवाददाता, हरिद्वार। राष्ट्रीय सावक मंच के संयोजक चंद्रमोहन कौशिक के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर से भेंट कर गली-मोहल्लों में बिक रहे अवैध नशे, जुए-सट्टे पर रोक लगाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। एसएसपी ने ज्ञापन पर संज्ञान लेकर प्रभावी कार्रवाई का आश्वासन दिया। कौशिक ने कहा कि हरिद्वार विश्व प्रसिद्ध तीर्थनगरी है, जहां कुंभ और अर्धकुंभ जैसे भव्य मेले होते हैं। यहां जन्म लेकर कार्य करना सौभाग्य है, लेकिन वर्तमान में गली-गली में अवैध नशे का कारोबार मां गंगा की नगरी को कलंकित कर रहा है और युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहा है। उन्होंने कहा कि गलत को देखकर मौन रहना भी अन्याय को बढ़ावा देना है।

एसआरटी परिसर टिहरी में विद्यार्थी परिषद का पांच पदों पर कब्जा

राजन सजवाण अध्यक्ष बने, नैतिक कुमार ने दो वोट से सचिव पद जीता

भारतेंदु संवाददाता, नई टिहरी

एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के एसआरटी परिसर बादशाहीथौल में शुक्रवार को छात्रसंघ चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। चुनाव में विद्यार्थी परिषद का दबदबा रहा और सात में से पांच पदों पर उसके प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। अध्यक्ष पद पर अभाविप के राजन सजवाण ने सानिया उनियाल को 165 मतों से हराकर जीत हासिल की। उपाध्यक्ष पद पर हर्ष प्रियांशु ने सुमित को 202 मतों से पराजित किया। सचिव पद पर विद्यार्थी परिषद के राज सिंह और निर्दलीय नैतिक कुमार के बीच कांटे का मुकाबला हुआ।

पुनर्मतगणना के बाद नैतिक कुमार ने महज दो वोट के अंतर से जीत दर्ज की। सह-सचिव पद पर अभाविप के रमन पाल कुमार ने आंचल को 100 मतों से, जबकि कोषाध्यक्ष पद पर वंश कुमार ने अंशिका को 145 मतों से हराया। छात्रा प्रतिनिधि पद पर सानिया नेगी ने अभाविप की सिमरन को 130 मतों से तथा विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पद पर अभाविप के मृदुल मखलोगा ने देवांश को 175 मतों से पराजित किया। परिसर में कुल 1181 छात्र-छात्राएं मतदान के लिए पंजीकृत थे, जिनमें से 779 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

मतदान सुबह आठ बजे शुरू होकर दोपहर एक बजे तक चला। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रो. केके वर्मा ने परिणाम घोषित किए। इसके बाद परिसर निदेशक प्रो. एए बौड़ाई और मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने विजयी प्रत्याशियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

जीत के बाद परिसर में जश्न

जीत के बाद विजयी प्रत्याशियों और समर्थकों ने परिसर में जुलूस निकालकर खुशी जताई। परिसर निदेशक ने शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने में सहयोग के लिए छात्र-छात्राओं, शिक्षकों, कर्मचारियों, प्रशासन और पुलिस का आभार जताया।

नैनी झील में आ रही जमा मलबा हटाने का काम शुरू

मलबा हटाने के बाद व जलस्तर सामान्य होने पर तल का होगा गहरीकरण

भारतेंदु संवाददाता, नैनीताल

मानसून के दौरान हुई अत्यधिक वर्षा के कारण नैनी झील के विभिन्न हिस्सों में जमा हुए मलबे और अन्य सामग्री को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने बताया कि झील में जमा मलबे के पानी में घुलने से पहले ही उसके निस्तारण की कार्रवाई की जा रही है। झील के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए काम शुरू करने से पहले विशेषज्ञ भू-वैज्ञानिकों की रिपोर्ट ली गई। रिपोर्ट के आधार पर सिंचाई विभाग ने वैज्ञानिक तरीके से मलबा हटाने की प्रक्रिया शुरू की है, ताकि झील की पारिस्थितिकी और प्राकृतिक संरचना पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

अधिकारियों के अनुसार मानसून के दौरान भारी बारिश के चलते झील में विभिन्न स्थानों पर मलबा और अन्य सामग्री पहुंची है। समय रहते इसे हटाना जरूरी है, जिससे पानी की गुणवत्ता और झील की प्राकृतिक स्थिति प्रभावित न हो। जिलाधिकारी ने बताया कि झील का जलस्तर सामान्य होने के बाद इसके तल को उठाने और गहरीकरण का कार्य भी किया जाएगा।

इसके लिए आवश्यक तकनीकी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। गहरीकरण का मुख्य उद्देश्य झील की जलधारण क्षमता को बनाए रखना और भविष्य में वर्षा के दौरान जल संचय की क्षमता को बेहतर करना है।

वैज्ञानिक मानकों पर जोर

प्रशासन का कहना है कि झील की पारिस्थितिकी को सुरक्षित रखते हुए संरक्षण कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। मलबा हटाने के साथ झील की स्थिति पर भी लगातार निगरानी रखी जाएगी। विशेषज्ञों की सलाह और निर्धारित मानकों के अनुरूप होने वाले इन कार्यों से नैनी झील के संरक्षण में मदद मिलने की उम्मीद है। प्रशासन ने संबंधित विभागों को कार्य में गुणवत्ता और वैज्ञानिक मानकों का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं।

ज्योलीकोट में जलजनित रोगों पर प्रशासन अलर्ट

दूषित पेयजल संकट के बीच 110 परिवारों को मिला 15,500 लीटर शुद्ध पानी

भारतेंदु संवाददाता, नैनीताल

जनपद मुख्यालय के निकट ज्योलीकोट और आसपास के क्षेत्रों में दूषित पेयजल से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए शुक्रवार को भी प्रशासन और पेयजल विभाग की ओर से राहत एवं निगरानी का काम जारी रहा। उत्तराखंड जल संस्थान ने टैंकरों के माध्यम से प्रभावित परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया। वहीं जल संस्थान और पेयजल निगम के अधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों के साथ विभिन्न पेयजल टैंकों, जल स्रोतों और पाइपलाइनों का निरीक्षण किया। प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल टैंकों की सफाई, क्लोरीनीकरण, फ्लैशिंग और मरम्मत का काम तेजी से कराया जा रहा है। क्षेत्र में दूषित जल से जुड़ी बीमारियों के कारण कम से कम दो लोगों की मौत हो चुकी है। स्थिति को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने पेयजल विभाग को निर्देश दिए कि स्थिति सामान्य होने तक प्रतिदिन टैंकरों के माध्यम से शुद्ध पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सभी जल स्रोतों, टैंकों और वितरण लाइनों का नियमित क्लोरीनीकरण कराने तथा पानी के नमूनों की जांच कर रिपोर्ट प्रतिदिन जिला प्रशासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। पाइपलाइन में लीकेज और क्रॉस-कनेक्शन की शिकायतों का तत्काल निस्तारण करने को भी कहा गया है। स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर घर-घर सर्वे और जलजनित रोगों की निगरानी जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं।

अधिकारियों के अनुसार पिछले दो दिनों में चार टैंकरों के माध्यम से 110 परिवारों को 15,500 लीटर से अधिक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया गया। देवलदुंगा लाइन की 500 मीटर फ्लैशिंग कराई गई, जबकि 14 शिकायतों का निस्तारण और आठ पेयजल नमूने लिए गए। ग्रामीणों को दूषित पानी से बचाव के उपायों के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि व्यवस्थाओं में किसी भी स्तर पर लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उधर, पीलिया नियंत्रण के लिए चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने नौ सूत्रीय कार्ययोजना तैयार की है।

सितंबर में सजी चंडीगढ़ की हसीन वादियां, पर्यटन स्थलों पर उमड़ा आकर्षण

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

मानसून की विदाई के साथ सितंबर में चंडीगढ़ का मौसम सुहावना हो जाता है और शहर के पर्यटन स्थल हरियाली से निखर उठते हैं। इस दौरान तापमान सामान्यत: 23 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने से लोगों को घूमने-फिरने और बाहरी गतिविधियों का आनंद लेने का बेहतर अवसर मिलता है। बारिश के बाद सड़कों के किनारे पेड़-पौधे और शहर के खुले क्षेत्र ताजगी से भर जाते हैं।

पर्यटकों के लिए सुखना झील इस मौसम में प्रमुख आकर्षण बनी रहती है। मानसून के बाद झील पानी से भर जाती है। सुबह और शाम के समय ठंडी हवाओं के बीच बोटिंग और शिवालिक की पहाड़ियों का मनोरम दृश्य लोगों को खासा आकर्षित करता है। परिवार और पर्यटक यहां शांत वातावरण में समय बिताना पसंद करते हैं।

रॉक गार्डन भी सितंबर में घूमने के लिए बेहतरीन स्थान है। नेकचंद द्वारा बेकार सामग्री से तैयार किया गया यह अनूठा उद्यान अपनी कलात्मक संरचनाओं, मूर्तियों और मानव निर्मित झरनों के लिए प्रसिद्ध है। बारिश के बाद यहां हरियाली बढ़ जाती है और झरनों में पानी का प्रवाह भी आकर्षक नजर आता है। हल्की धूप में यहां फोटोग्राफी का आनंद लिया जा सकता है।

इसी तरह जाकिर हुसैन रोज गार्डन और लेजर वैली बारिश के बाद हरियाली से भर जाते हैं। यहां सुबह-शाम टहलने, प्रकृति का आनंद लेने और परिवार के साथ पिकनिक मनाने के लिए अनुकूल वातावरण रहता है। खुले मैदान और हरियाली शहर की भागदौड़ से दूर सुकून का अनुभव कराते हैं।

सितंबर में सेक्टर-17 की ओपन-एयर मार्केट में शाम बिताना भी लोगों को पसंद आता है। यहां खरीदारी के साथ स्ट्रीट फूड का स्वाद लिया जा सकता है और लाइव म्यूजिकल फाउंटेन का आनंद भी लिया जा सकता है। वहीं, इनडोर खरीदारी और मनोरंजन के लिए एलांते मॉल एक विकल्प है।

भाजपा की चार यात्राओं से गूंजेगा नशामुक्ति का संकल्प

18 सितंबर से शुरू होने वाली यात्राएं पंजाब के 117 विधानसभा क्षेत्रों में चलाएंगी नशे के खिलाफ जनजागरूकता अभियान

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

भारतीय जनता पार्टी पंजाब ने नशे के खिलाफ व्यापक जनजागरण अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने बताया कि भाजपा 18 सितंबर से चार राज्यव्यापी 'नशा मुक्त पंजाब यात्राएं' निकालेगी। इन यात्राओं के माध्यम से प्रदेश के सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचकर लोगों को नशे के खिलाफ लामबंद किया जाएगा। पार्टी का उद्देश्य अभियान को केवल जागरूकता कार्यक्रम तक सीमित न रखकर इसे व्यापक जनआंदोलन का रूप देना है।

ढिल्लों ने कहा कि 'भाजपा दा नारा, नशा मुकाना सारा' के संकल्प के साथ निकाली जा रही यात्राएं पंजाब के सामने मौजूद तीन प्रमुख चुनौतियों—नशा, बिगड़ती कानून-व्यवस्था और भ्रष्टाचार—पर केंद्रित रहेंगी। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की समस्या तहसील और थाने से लेकर शासन के उच्च स्तर तक दिखाई दे रही है। यात्रा के दौरान इन मुद्दों को जनता के बीच उठाया जाएगा और लोगों को इनके खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि नशे का संकट केवल स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या नहीं है, बल्कि इससे पंजाब की सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान भी प्रभावित हो रही है। नशे की वजह से अनेक परिवारों में आर्थिक और सामाजिक संकट पैदा हो रहा है। विशेष रूप से माताओं और बहनों को अपने परिवारों में नशे की समस्या का भारी दर्द झेलना पड़ रहा है। पार्टी का मानना है कि युवाओं को नशे से बचाने के लिए समाज के हर वर्ग की भागीदारी जरूरी है।

भाजपा के अनुसार नशे की बढ़ती समस्या का असर अपराध, हिंसा और गिरोह से जुड़ी गतिविधियों पर भी पड़ रहा है। कई परिवार उपचार के खर्च का बोझ उठाने के लिए कर्ज लेने या अपनी जमीन और संपत्ति बेचने तक को मजबूर हो रहे हैं। ऐसे में यात्राओं के माध्यम से नशे के सामाजिक और आर्थिक दुष्प्रभावों को भी जनता के सामने रखा जाएगा।

18 सितंबर को पहली यात्रा पठानकोट से : चार यात्राओं में पहली यात्रा 18 सितंबर को जिला पठानकोट के माधोपुर स्थित एकता स्थल से शुरू होगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन इसे हरी झंडी दिखाएंगे। यह यात्रा जालंधर में समाप्त होने से पहले पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर और कपूरथला समेत कई विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। यात्रा के दौरान स्थानीय लोगों से संवाद कर नशे और कानून-व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

19 सितंबर को फतेहगढ़ साहिब से दूसरी यात्रा : दूसरी यात्रा 19 सितंबर को गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब में नतमस्तक होने के बाद शुरू होगी। यह यात्रा समराला, खन्ना, फतेहगढ़ साहिब, डेराबस्सी, मोहाली, खरड़, रोपड़, आनंदपुर साहिब, होशियारपुर, नवांशहर, बंगा और फगवाड़ा सहित विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से होकर जालंधर पहुंचेगी।

20 सितंबर को फाजिल्का से तीसरी यात्रा : तीसरी यात्रा 20 सितंबर को फाजिल्का के सादिकी बॉर्डर स्थित आसफवाला 1971 युद्ध स्मारक से शुरू होगी। यह यात्रा अबोहर, श्री मुक्तसर साहिब, मलोट, फरीदकोट, मोगा, जगरांव, मलेरकोटला और लुधियाना सहित विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी।

21 सितंबर को चौथी यात्रा : चौथी यात्रा 21 सितंबर को तलवंडी साबो स्थित गुरुद्वारा श्री दमदमा साहिब से शुरू होगी। यह बठिंडा, मानसा, बरनाला, संगरूर, पटियाला और राजपुरा समेत विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से होकर जालंधर में समाप्त होगी। भाजपा नेताओं ने कहा कि चारों यात्राओं के जरिए प्रदेशभर में नशे के खिलाफ सामाजिक चेतना मजबूत करने और लोगों को अभियान से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।

न्यूज ब्रीफ

कनाडा में वर्क परमिट धारकों को पढ़ाई की छूट

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़। कनाडा में वर्क परमिट पर नौकरी कर रहे पात्र लोगों के लिए राहत की खबर है। इमिग्रेशन विभाग ने 9 सितंबर 2026 को नई अस्थायी नीति घोषित की है। इसके तहत पात्र वर्क परमिट धारक छह महीने या उससे कम अवधि के शॉर्ट-टर्म कोर्स, प्रशिक्षण और लाइसेंसिंग कार्यक्रम बिना अलग स्टडी परमिट के कर सकेंगे। हालांकि, यदि उनका वर्क परमिट छह महीने से पहले समाप्त हो जाता है तो पढ़ाई की अनुमति भी उसी समय खत्म हो जाएगी। नई व्यवस्था से नौकरी करते हुए कौशल और योग्यता बढ़ाने का अवसर मिलेगा। इसका लाभ विशेष रूप से ट्रेड्सपर्सन, नर्स और प्रयोगशाला तकनीशियनों जैसे कामगारों को मिल सकता है। भारतीय कामगार भी इसका फायदा उठा सकेंगे। हालांकि, इस सुविधा से सीधे स्थायी निवास नहीं मिलेगा और न ही अतिरिक्त अंक या स्नातकोत्तर कार्य परमिट का अधिकार मिलेगा। यह अस्थायी नीति 31 दिसंबर 2027 तक लागू रहेगी।

विधानसभा भवन को मिली बम धमकी से मचा हड़कंप

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा विधानसभा भवन को बम से उड़ाने की धमकी वाली ई-मेल मिलने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही ऑपरेशन सेल, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड की टीमें विधानसभा भवन पहुंचीं। सुरक्षा टीमों ने पूरे परिसर और आसपास के क्षेत्रों की गहन जांच की, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। उधर, साइबर सेल ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ई-मेल भेजने वाले की पहचान और उसके ठिकाने का पता लगाने के लिए ई-मेल के स्रोत सहित अन्य तकनीकी जानकारी जुटा रही है। इससे पहले भी चंडीगढ़ के कई सरकारी कार्यालयों को इस तरह की धमकी भरी ई-मेल मिल चुकी हैं। हालांकि, जांच में अब तक किसी मामले में संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

नशा तस्करों के घरों पर पुलिस की बड़ी छापेमारी

भारतेन्दु संवाददाता, लुधियाना। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना सलेम टाबरी पुलिस ने इलाके में संदिग्ध नशा तस्करों के घरों पर छापेमारी की। पुलिस टीमों ने करीब आधा दर्जन संदिग्धों के घरों में तलाशी ली। इस दौरान कई स्थानों से नशीला पदार्थ बरामद होने की जानकारी सामने आई है। कार्रवाई के दौरान एसीपी नॉर्थ कीकर सिंह भुल्लर और थाना प्रभारी जसबीर सिंह गिल भारी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, नशे के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। जिन घरों में तलाशी ली गई, उनमें से कई स्थानों पर नशीला पदार्थ बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक संबंधित आरोपियों के खिलाफ पहले भी कई संगीन मामलों में केस दर्ज हैं। बरामद नशीले पदार्थ के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने और आगे की कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

कोयले की कमी से पंजाब में गहराया बिजली संकट

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब में कोयले की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने से बिजली संकट गहराता जा रहा है। प्रदेश के थर्मल प्लांट पूरी क्षमता से बिजली उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, जिससे कई इलाकों में बिजली कटौती की समस्या बढ़ गई है। बिजली की बढ़ती मांग के बीच लोगों को कई घंटों तक कट का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार तलवंडी साबो थर्मल प्लांट की तीन में से एक इकाई बंद है। राजपुरा थर्मल प्लांट की भी एक इकाई में बिजली उत्पादन प्रभावित है। उत्पादन घटने के कारण पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड को केंद्रीय पूल से अधिक बिजली खरीदनी पड़ रही है। वीरवार रात 12 बजे प्रदेश में बिजली की मांग 11,655 मेगावाट थी, जो शुक्रवार सुबह 8:30 बजे बढ़कर 14,195 मेगावाट पहुंच गई। दिन में मांग 16,500 मेगावाट से अधिक रही। रात से सुबह तक पंजाब में करीब 4,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ, जबकि लगभग 7,100 मेगावाट बिजली केंद्रीय पूल से खरीदी गई। दिन में सौर ऊर्जा से करीब 400 मेगावाट बिजली मिलती है, लेकिन रात में इसका उत्पादन बंद हो जाता है, जिससे संकट और बढ़ जाता है। बिजली मंत्री पहले ही थर्मल प्लांटों में कम कोयला स्टॉक को लेकर चिंता जता चुके हैं। अधिकारियों के अनुसार आपूर्ति हो रही है, लेकिन जरूरत के मुकाबले पर्याप्त नहीं है। ऐसे में आने वाले दिनों में बिजली कटौती की समस्या बढ़ने की आशंका है।

रंधावा ने बॉर्डर रेंज पुलिस पर गैंगस्टरों से सांठगांठ के लगाए गंभीर आरोप, जांच की मांग

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री और गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक से सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बॉर्डर रेंज के पुलिस अधिकारियों पर गैंगस्टरों से कथित सांठगांठ के गंभीर आरोप लगाए हैं। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में रंधावा ने कहा कि डेरा बाबा नानक और बटाला से स्थानांतरित किए गए डीएसपी समेत संबंधित पुलिस अधिकारियों के मोबाइल फोन और कॉल डिटेल की गहन जांच होनी चाहिए। इससे अधिकारियों के संपर्कों की वास्तविक स्थिति सामने आ सकती है।

रंधावा ने कहा कि वह पूरी जिम्मेदारी के साथ ये आरोप लगा रहे हैं। यदि उनके आरोप गलत साबित होते हैं तो पंजाब के डीजीपी उनके खिलाफ भी मामला दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह राजनीतिक बयानबाजी का विषय नहीं है, बल्कि पंजाब की कानून-व्यवस्था से जुड़ा गंभीर मामला है। आरोप सही पाए जाने पर संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर कार्रवाई की जानी चाहिए।

रंधावा ने पुलिस महानिदेशक गौरव यादव पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस की ओर से गैंगस्टरों के परिवारों को सुरक्षा दी जा रही है, जबकि धमकियों और फिरौती की कॉल का सामना कर रहे आम लोगों को पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिल रही। उन्होंने कहा कि पुलिस की प्राथमिकता आम नागरिकों की सुरक्षा होनी चाहिए और अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।

उन्होंने पंजाब में स्थायी डीजीपी की नियुक्ति की आवश्यकता भी उठाई। रंधावा के अनुसार, राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति को मजबूत करने के लिए पुलिस नेतृत्व में स्थायित्व जरूरी है। गुरदासपुर नगर कौंसिल चुनाव का उल्लेख करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि गैंगस्टरों ने फोन के माध्यम से मतदाताओं को धमकाया था, लेकिन प्रशासन प्रभावी कार्रवाई करने में नाकाम रहा।

चंडीगढ़ में नए किरायेदारी नियम लागू विवाद निपटारे की होगी त्रिस्तरीय व्यवस्था

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

चंडीगढ़ प्रशासन के संपदा विभाग ने 'यूटी चंडीगढ़ टेनेंसी रूल्स, 2026' अधिसूचित कर दिए हैं। नए नियम 10 सितंबर से पूरे चंडीगढ़ में प्रभावी हो गए हैं। इनका उद्देश्य मकान मालिकों और किरायेदारों के बीच किरायेदारी संबंधी मामलों में पारदर्शिता, निश्चितता और समयबद्ध विवाद निपटारा सुनिश्चित करना है। नए नियमों के तहत किरायेदारी समझौते की जानकारी ऑनलाइन देना अनिवार्य किया गया है। मकान मालिक और किरायेदार को समझौता होने के दो महीने के भीतर संयुक्त रूप से या अलग-अलग किराया प्राधिकरण को इसकी सूचना देनी होगी। सूचना मिलने के सात दिन के भीतर प्राधिकरण ई-रसीद के रूप में विशिष्ट पहचान संख्या जारी करेगा, जो पंजीकृत मोबाइल नंबर या ई-मेल पर भेजी जाएगी।

नियमों के तहत किराया, बिजली, पानी, रखरखाव शुल्क और सुरक्षा राशि से जुड़े विवादों के समाधान की प्रक्रिया भी तय की गई है। इसके लिए किराया प्राधिकरण, किराया न्यायालय और किराया अधिकरण की त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाई गई है। यदि मकान मालिक किराया लेने से इनकार करता है या रसीद जारी नहीं करता तो किरायेदार लगातार दो महीने तक आरटीजीएस, एनईएफटी, चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान का प्रयास कर सकेगा। इसके बाद भी भुगतान स्वीकार नहीं होने पर राशि किराया प्राधिकरण के पास जमा कराई जा सकेगी।

किराये या अन्य शुल्क को लेकर विवाद होने पर संबंधित पक्ष किराया प्राधिकरण में आवेदन कर सकेंगे। निर्णय लेते समय आसपास के क्षेत्र में प्रचलित किराये को भी ध्यान में रखा जाएगा। किराया प्राधिकरण के गठन के तीन महीने के भीतर स्थानीय भाषा समेत प्रशासन द्वारा निर्धारित भाषाओं में डिजिटल मंच तैयार किया जाएगा।

सुखबीर बादल ने पेशी टाली, पार्टी ने लिखित सवालों के जवाब देने की कही बात

बहबल कलां गोलीकांड में सुखबीर बादल ने एसआइटी को दिया टालने का संकेत, 30 सितंबर बाद होंगे पेश

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

चंडीगढ़। बहबल कलां गोलीकांड मामले में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल शुक्रवार को विशेष जांच दल (एसआइटी) के सामने पेश नहीं हुए। उन्हें चंडीगढ़ के सेक्टर-32 स्थित पंजाब पुलिस अधिकारी संस्थान में पूछताछ के लिए पहुंचना था। उनकी जगह पार्टी के वरिष्ठ नेता अर्शदीप सिंह कलेर और परमिंदर सिंह रोमाणा एसआइटी के सामने पहुंचे। दोनों नेताओं ने एसआइटी को सुखबीर बादल की अनुपलब्धता की जानकारी दी और कहा कि वह 30 सितंबर के बाद पूछताछ के लिए उपलब्ध होंगे।

अर्शदीप सिंह कलेर और परमिंदर सिंह रोमाणा ने बताया कि सुखबीर बादल के पहले से निर्धारित राजनीतिक कार्यक्रम हैं, जिसके कारण वह शुक्रवार को एसआइटी के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके। कलेर ने यह भी बताया कि पिछले दिनों सुखबीर बादल को चोट लगी थी और शुक्रवार को उनका चिकित्सकीय परीक्षण भी होना था। पार्टी की ओर से एसआइटी के समक्ष यह मांग भी रखी गई कि सुखबीर बादल से पूछे जाने वाले सवाल उन्हें लिखित रूप में दिए जाएं। कलेर के अनुसार, सुखबीर बादल प्रत्येक सवाल का जवाब लिखित रूप में देने और हर उत्तर पर अपने हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हैं।

30 सितंबर के बाद उपलब्ध होंगे बादल : कलेर ने कहा कि सुखबीर बादल 30 सितंबर तक पहले से तय राजनीतिक कार्यक्रमों में व्यस्त हैं। इसके बाद वह एसआइटी के सामने पेश हो सकते हैं। हालांकि, उनकी अगली पेशी की तारीख अभी एसआइटी की ओर से तय की जानी है। पार्टी नेताओं ने स्पष्ट किया कि सुखबीर बादल जांच से बच नहीं रहे हैं और वह मामले की जांच में सहयोग कर रहे हैं।

कलेर ने आम आदमी पार्टी सरकार पर बहबल कलां और बरगाड़ी घटनाओं को राजनीतिक मुद्दा बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव नजदीक आने के कारण पुराने मामलों को दोबारा चर्चा में लाया जा रहा है। उनका दावा है कि सरकार के खिलाफ लोगों में बढ़ रहे आक्रोश से ध्यान हटाने के लिए इन मामलों को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। कलेर ने कहा कि बहबल कलां और बरगाड़ी की घटनाओं को करीब 11 वर्ष हो चुके हैं और इस दौरान पंजाब में तीन मुख्यमंत्री तक बदल चुके हैं।

अर्शदीप सिंह कलेर और परमिंदर सिंह रोमाणा ने सुखबीर बादल पर एसआइटी की जांच में सहयोग नहीं करने के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि सुखबीर बादल पहले भी जांच में शामिल हो चुके हैं और एसआइटी के सवालों का जवाब दे चुके हैं।

पांच दिन काम की मांग पर बैंक कर्मियों का जोरदार प्रदर्शन

बैंकिंग व्यवस्था ठप, लंबित मांगों पर कर्मचारियों का प्रदर्शन

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़। पांच दिवसीय कार्य सप्ताह सहित लंबित मांगों को लेकर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स (यूएफबीयू) के आह्वान पर देशभर में बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों ने हड़ताल की। चंडीगढ़ में सेक्टर-17 स्थित बैंक स्क्वायर में विभिन्न बैंकों के कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की। हड़ताल के कारण बैंक शाखाओं में नियमित कामकाज प्रभावित रहा।

यूनियन नेताओं ने बताया कि बैंक कर्मचारी लंबे समय से पांच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करने की मांग कर रहे हैं। 2024 में हुए समझौते के बावजूद अब तक इस व्यवस्था को लागू नहीं किया गया है। उनका कहना है कि बैंक ग्राहक एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और यूपीआई जैसी डिजिटल सेवाओं के माध्यम से चौबीसों घंटे और सप्ताह के सातों दिन सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे में कर्मचारियों को भी पांच दिवसीय कार्य सप्ताह दिया जाना चाहिए।

यूनियनों ने 28, 29 और 30 सितंबर को भी हड़ताल का आह्वान किया है। यदि इन तिथियों तक मांगों पर समाधान नहीं हुआ तो 26 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने की चेतावनी दी गई है। नेताओं ने कहा कि मौजूदा हड़ताल की सफलता से स्पष्ट है कि कर्मचारी और अधिकारी अपनी मांगों को लेकर एकजुट हैं।

यूनियन नेताओं ने सरकार और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन से आग्रह किया कि वे कर्मचारियों की मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए सार्थक वार्ता करें। उन्होंने कहा कि समय रहते समाधान निकालकर आगे होने वाली औद्योगिक कार्रवाई को टाला जा सकता है। साथ ही चेतावनी दी कि लंबित मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं होने की स्थिति में आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।

गिरफ्तारी नियमों पर हाईकोर्ट सख्त, तीनों प्रशासनों से जवाब मांगा

अदालत ने गिरफ्तारी के दौरान नागरिक अधिकारों की सुरक्षा और पुलिस की जवाबदेही सुनिश्चित करने पर मांगी रिपोर्ट

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी से जुड़े कानूनी सुरक्षा उपायों के पालन को लेकर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ प्रशासन से जवाब मांगा है। अदालत ने तीनों से हलफनामा दाखिल कर स्पष्ट करने को कहा है कि पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय सुप्रीम कोर्ट और कानून में निर्धारित सुरक्षा प्रविधानों का किस तरह पालन किया जा रहा है। अदालत ने यह भी जानना चाहा है कि इन प्रावधानों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए पुलिस विभागों में क्या व्यवस्था की गई है।

हाईकोर्ट ने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और पुलिस कार्रवाई में पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। अदालत के समक्ष यह विषय इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि गिरफ्तारी किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाली गंभीर कानूनी कार्रवाई है। ऐसे में पुलिस को गिरफ्तारी की प्रक्रिया में निर्धारित नियमों और सुरक्षा उपायों का पालन करना अनिवार्य है। अदालत ने संबंधित प्रशासन से इस संबंध में मौजूदा व्यवस्था और अनुपालन की स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।

अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी के दौरान संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताना, आवश्यक जानकारी को उचित तरीके से दर्ज करना और उसके कानूनी अधिकारों से अवगत कराना जरूरी है। इसके अलावा पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तारी की प्रक्रिया से जुड़े निर्धारित नियमों की जानकारी और उनके अनुपालन के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए जाने चाहिए। हाईकोर्ट यह जानना चाहता है कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में पुलिस अधिकारियों को इन कानूनी प्रावधानों के बारे में किस प्रकार प्रशिक्षित और निर्देशित किया गया है।

जमीनी स्तर पर पालन की व्यवस्था पर जवाब : हाईकोर्ट ने तीनों प्रशासन से यह भी स्पष्ट करने को कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गिरफ्तारी के संबंध में दिए गए दिशा-निर्देशों को लागू करने के लिए पुलिस विभाग में कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं। अदालत यह जानना चाहती है कि गिरफ्तारी के समय आवश्यक दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी करने, गिरफ्तारी का कारण दर्ज करने और गिरफ्तार व्यक्ति को उसके अधिकारों की जानकारी देने के लिए क्या निर्धारित व्यवस्था लागू है।

अदालत ने अनुपालन की स्थिति पर भी रिपोर्ट मांगी है। इसके तहत प्रशासन को यह बताना होगा कि पुलिस अधिकारियों को नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए किस स्तर पर निर्देश जारी किए गए हैं और इन निर्देशों की निगरानी कैसे की जाती है। हाईकोर्ट यह भी देखेगा कि यदि गिरफ्तारी की प्रक्रिया में निर्धारित सुरक्षा उपायों का उल्लंघन होता है तो संबंधित पुलिस अधिकारी की जवाबदेही तय करने के लिए क्या व्यवस्था मौजूद है।

अधिकारों की रक्षा पर जोर: अदालत का रुख इस बात को रेखांकित करता है कि पुलिस को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ नागरिकों के मौलिक और कानूनी अधिकारों की रक्षा भी सुनिश्चित करनी होगी। गिरफ्तारी की शक्ति का इस्तेमाल निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत ही किया जाना चाहिए। किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर असर डालने वाली कार्रवाई में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखना आवश्यक है।

हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ प्रशासन से हलफनामे के माध्यम से पूरी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। प्रशासन को यह बताना होगा कि गिरफ्तारी से संबंधित सुरक्षा उपायों को लागू करने के लिए पुलिस विभागों में क्या तंत्र विकसित किया गया है और अधिकारियों द्वारा उसका कितना पालन किया जा रहा है। साथ ही, नियमों के उल्लंघन की स्थिति में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी देनी होगी।

अदालत के निर्देश के बाद अब तीनों क्षेत्रों के पुलिस प्रशासन को गिरफ्तारी की मौजूदा प्रक्रिया, अधिकारियों को दिए गए निर्देश और सुरक्षा प्रावधानों के अनुपालन से संबंधित जानकारी अदालत के समक्ष रखनी होगी।

गुलजार सिंह मामले में पंजाब कांग्रेस का राज्यभर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

गुलजार सिंह मामले को लेकर पंजाब कांग्रेस शुक्रवार को पूरे राज्य में सरकार के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने सभी जिला कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों को अपने-अपने जिलों में प्रदर्शन आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। पार्टी के कार्यकर्ता संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालयों का घेराव कर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपेंगे। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस की ओर से वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग प्रमुखता से उठाई जाएगी।

कांग्रेस का आरोप है कि गुलजार सिंह मामले में राज्य सरकार ने गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई नहीं की। पार्टी नेताओं का कहना है कि मामले में जो भी लोग जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। कांग्रेस का दावा है कि पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के बजाय सरकार मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। इसी के विरोध में पार्टी ने राज्यव्यापी आंदोलन का निर्णय लिया है।

पार्टी के कार्यक्रम के अनुसार जिला स्तर पर कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एकत्र होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। कई स्थानों पर सरकार और वित्त मंत्री के खिलाफ नारेबाजी के साथ पुतला फूंकने का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। जिला कांग्रेस अध्यक्षों को अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने और प्रदर्शन को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि आंदोलन के माध्यम से सरकार पर मामले में निष्पक्ष और त्वरित कार्रवाई के लिए दबाव बनाया जाएगा।

गुलजार सिंह मामले को लेकर पंजाब कांग्रेस इससे पहले भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर चुकी है। आठ सितंबर को प्रदेश कांग्रेस की ओर से इसी मुद्दे पर प्रदर्शन किया गया था। अब पार्टी ने आंदोलन को जिला स्तर तक विस्तार देते हुए एक साथ पूरे पंजाब में प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। राजा वड़िंग ने कहा है कि गुलजार सिंह को न्याय और उनके परिवार को इंसाफ मिलने तक कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा।

उमर ने ठुकराई कांग्रेस की वंदे मातरम सलाह

कांग्रेस की सलाह पर उमर ने जताई असहमति, कहा- सरकारी कार्यक्रमों में नियमों का करना होगा पालन

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर

वंदे मातरम के पूरे छंद गाने को लेकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल की ओर से नेशनल कॉन्फ्रेंस को वंदे मातरम के केवल दो छंद गाने की सलाह दिए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के सभी पद गाने को लेकर देशभर में लागू व्यवस्था का पालन करना होगा और इसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई हो सकती है।

गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि राष्ट्रीय गीत को लेकर कानून और प्रोटोकॉल बनाया गया है, जो केवल जम्मू-कश्मीर तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम का पूरा गायन अब निर्धारित प्रक्रिया का हिस्सा है। ऐसे में किसी व्यक्ति या संगठन को इससे अलग रहने पर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राजनीतिक दल के तौर पर कभी वंदे मातरम को नहीं अपनाया है और भविष्य में भी इसे पार्टी के कार्यक्रमों का हिस्सा बनाने का कोई निर्णय नहीं है। हालांकि, जहां सरकारी प्रोटोकॉल लागू होता है, वहां उसका पालन करना जरूरी है।

उमर अब्दुल्ला ने अपनी सहयोगी पार्टी कांग्रेस पर भी सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या कांग्रेस चाहती है कि इस मुद्दे पर कश्मीरियों को जेल भेज दिया जाए। उनके बयान से विपक्षी गठबंधन के भीतर इस मुद्दे पर मतभेद और स्पष्ट हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने एक तरफ पार्टी के रुख को स्पष्ट किया, वहीं दूसरी तरफ सरकारी कार्यक्रमों में लागू नियमों का पालन करने की बात कही।

दरअसल, कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने आठ सितंबर को सोशल मीडिया मंच के माध्यम से नेशनल कॉन्फ्रेंस को वंदे मातरम के दो छंद गाने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा था कि वंदे मातरम का पूरा संस्करण स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल लोगों की विविध और समावेशी सोच के अनुरूप नहीं है। उन्होंने सहयोगी दलों से 1937 में कांग्रेस द्वारा स्वीकार किए गए राष्ट्रीय गीत के संस्करण का सम्मान करने का आग्रह किया था।

यह बयान ऐसे समय आया जब श्रीनगर में अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला वंदे मातरम के पूरे गायन के दौरान खड़े रहे थे। दोनों नेताओं के पूरे गीत के दौरान खड़े रहने से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच मतभेद की चर्चा तेज हो गई।

उमर अब्दुल्ला के बयान ने इस विवाद को एक नया राजनीतिक मोड़ दे दिया है। उन्होंने साफ किया कि पार्टी की राजनीतिक मान्यता और सरकारी कार्यक्रमों में लागू प्रोटोकॉल दो अलग-अलग विषय हैं। उनका कहना है कि पार्टी की ओर से वंदे मातरम को अपनाने का सवाल अलग है, लेकिन सरकारी कार्यक्रमों में निर्धारित नियमों का पालन करना आवश्यक है।

इस पूरे घटनाक्रम से विपक्षी गठबंधन के भीतर राष्ट्रीय गीत को लेकर अलग-अलग राजनीतिक दृष्टिकोण सामने आए हैं। कांग्रेस जहां ऐतिहासिक और बहुलतावादी दृष्टिकोण का हवाला दे रही है, वहीं उमर अब्दुल्ला ने कानूनी व्यवस्था और सरकारी प्रोटोकॉल के पालन को प्राथमिकता दी है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर दोनों दलों के बीच राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने की संभावना है। वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच सामने आया यह मतभेद विपक्षी गठबंधन की एकजुटता पर भी सवाल खड़े कर रहा है।

उमर अब्दुल्ला ने स्पष्ट किया कि पार्टी के विचार अपनी जगह हैं, लेकिन सरकारी कार्यक्रमों में लागू नियमों का पालन करना उनकी जिम्मेदारी है। वहीं कांग्रेस की ओर से ऐतिहासिक संदर्भ और गीत के चयनित संस्करण को लेकर दिए गए सुझाव ने राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है।

एलओसी पर बढ़ा तनाव, जैश-लश्कर आतंकियों को पाक सेना दे रही प्रशिक्षण

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। गुलाम जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ बढ़ते जनाक्रोश के बीच नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर तनाव बढ़ने की आशंका है। सुरक्षा एजेंसियों को मिले इनपुट के अनुसार, जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े करीब 50 से 60 आतंकियों को पाकिस्तानी सेना के विशेष सेवा समूह (एसएसजी) के साथ प्रशिक्षण दिए जाने की जानकारी सामने आई है। हालांकि, सुरक्षा एजेंसियों ने अभी इन सूचनाओं की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है।

सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तानी सेना उड़ी और केरन सेक्टर के आसपास गतिविधियां बढ़ाने की तैयारी में है। एलओसी के नजदीक आतंकियों की मौजूदगी को देखते हुए सीमा कार्रवाई दल (बैट) के हमले और घुसपैठ की आशंका भी जताई जा रही है। राजौरी-पुंछ, गुरेज-टंगडार, उड़ी और केरन सेक्टर को संभावित घुसपैठ के लिहाज से संवेदनशील माना जा रहा है।

सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक, पिछले करीब तीन महीनों से जैश और लश्कर के आतंकियों को पाकिस्तानी सेना के एसएसजी कमांडो के साथ विशेष प्रशिक्षण दिए जाने की सूचना है। मनशेरा क्षेत्र में एक अस्थायी प्रशिक्षण शिविर बनाए जाने का भी इनपुट है, जहां करीब 80 लोगों की मौजूदगी बताई जा रही है। इनमें 50 से 60 आतंकी और लगभग 20 एसएसजी कमांडो शामिल होने की जानकारी है।

पाकिस्तान के भीतर भर्ती पर जोर : सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान विरोधी गतिविधियों के असर के कारण आतंकी संगठनों के पारंपरिक नेटवर्क पर दबाव बढ़ा है। इसी वजह से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पाकिस्तानी पंजाब और अन्य क्षेत्रों से नए युवाओं की भर्ती और प्रशिक्षण पर जोर दे रही है। बहावलपुर में जैश के पुराने ढांचे को फिर सक्रिय करने और पाकिस्तान में लश्कर के प्रशिक्षण नेटवर्क के विस्तार की भी सूचना है।

बताया जा रहा है कि आतंकी संगठन अब बड़े समूहों के बजाय छोटे मॉड्यूल और सीमित संख्या में प्रशिक्षित कैडर तैयार करने पर ध्यान दे रहे हैं। ऑनलाइन माध्यमों के जरिए युवाओं को प्रभावित करने तथा निष्क्रिय समर्थक नेटवर्क को दोबारा सक्रिय करने की कोशिशों की भी जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को मिली है।

सीमित हमले की आशंका : सुरक्षा एजेंसियां एलओसी पर किसी भी संभावित घुसपैठ या बैट कार्रवाई को लेकर सतर्क हैं। प्रशिक्षित आतंकियों की मौजूदगी, एसएसजी की संभावित भूमिका और संवेदनशील सेक्टरों में गतिविधियों को देखते हुए सीमित आतंकी या सैन्य उकसावे की आशंका से इनकार नहीं किया जा रहा है। गुलाम जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान विरोधी असंतोष के बीच एलओसी पर तनाव बढ़ाने की कोशिश का उद्देश्य लोगों का ध्यान आंतरिक हालात से हटाना भी हो सकता है। आने वाले सप्ताह सीमा सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।

एसीबी में एआई की राह में गोपनीय डेटा सुरक्षा बनी सबसे बड़ी चुनौती

भ्रष्टाचार जांच में तकनीकी छलांग पर ब्रेक, डेटा सुरक्षा को लेकर सरकार चिंतित

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। भ्रष्टाचार की जांच को आधुनिक तकनीक से तेज और प्रभावी बनाने के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की जांच में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के इस्तेमाल का प्रस्ताव तैयार किया गया है। हालांकि, गोपनीय जांच सामग्री की सुरक्षा को लेकर यह प्रस्ताव फिलहाल अंतिम मंजूरी की प्रतीक्षा में है। तकनीकी मूल्यांकन समिति प्रस्ताव की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के साथ तकनीकी, वित्तीय, प्रशासनिक, कानूनी और संचालन संबंधी पहलुओं की समीक्षा कर रही है।

सबसे बड़ी चिंता एसीबी की संवेदनशील जांच सामग्री को एआई प्रणाली में डालने के बाद उसकी सुरक्षा को लेकर है। जांच रिकॉर्ड में सरकारी कर्मचारियों की सेवा संबंधी जानकारी, संपत्ति और बैंक खातों का विवरण, वित्तीय लेन-देन, बयान, सरकारी पत्राचार तथा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य शामिल होते हैं। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि इन जानकारियों तक अनधिकृत पहुंच न हो और उनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल न किया जा सके।

प्रस्ताव की समीक्षा में क्लाउड पर डेटा रखने से जुड़े जोखिमों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यह देखा जा रहा है कि डेटा किस सर्वर पर रहेगा, उस तक किसकी पहुंच होगी, कितने समय तक सुरक्षित रखा जाएगा और उसे स्थायी रूप से हटाने की व्यवस्था क्या होगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने पर जोर है कि एआई सेवा प्रदाता जांच सामग्री का इस्तेमाल अपने मॉडल के प्रशिक्षण या किसी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए न कर सके।

इसके बावजूद एसीबी के लिए एआई को उपयोगी तकनीक माना जा रहा है। बड़ी जांच फाइलों में दस्तावेजों की छंटाई, रिकॉर्ड की तुलना, महत्वपूर्ण जानकारी तलाशने, संक्षिप्त विवरण तैयार करने, अनुवाद और लिप्यंतरण जैसे कार्य तेजी से किए जा सकते हैं। वित्तीय लेन-देन और विभिन्न व्यक्तियों या संस्थाओं के बीच संबंधों की पहचान में भी एआई जांच अधिकारियों की मदद कर सकता है।

कश्मीर एक्सपो से कारीगरों को बड़े बाजारों से जोड़ने पर जोर

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त-सचिव विक्रमजीत सिंह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर सरकार कारीगरों, स्वयं सहायता समूहों और उद्यमियों को बड़े घरेलू व अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने के लिए प्रदर्शनियों और व्यापार प्रोत्साहन कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। कश्मीर एक्सपो जैसे आयोजन स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी, बिक्री और प्रचार के साथ कारीगरों को सीधे ग्राहकों से जुड़ने का अवसर देते हैं। सिंह ने बताया कि जम्मू-कश्मीर व्यापार प्रोत्साहन संगठन विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। 18 सितंबर से जम्मू में भी कार्यक्रम होगा, जिसमें स्थानीय कारीगर, स्वयं सहायता समूह और नए उद्यमी अपने उत्पाद प्रदर्शित कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि ग्राहकों से मिलने वाले सुझावों से उत्पादों में सुधार, नए डिजाइन और नवाचार को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने बताया कि हस्तशिल्प विभाग ने उत्पादों की प्रमाणिकता सुनिश्चित करने के लिए क्यूआर कोड व्यवस्था शुरू की है। हस्तशिल्प और हस्तनिर्मित उत्पादों के लिए 18 भौगोलिक संकेतक टैग हासिल किए जा चुके हैं, जबकि 17 अन्य टैग की प्रक्रिया जारी है।

लद्दाख को राज्य दर्जा नहीं, विशेष ढांचे पर बनी सहमति

निर्वाचित निकाय को विधायी, कार्यकारी और वित्तीय अधिकार देने पर केंद्र की पहल

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। केंद्र सरकार ने लद्दाख को फिलहाल राज्य का दर्जा देने या विधायिका वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाने से इनकार किया है। हालांकि, लद्दाख के लिए एक विशेष और 'अद्वितीय' राजनीतिक ढांचे पर सहमति बनाने की दिशा में बातचीत आगे बढ़ी है। प्रस्तावित व्यवस्था में केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर एक निर्वाचित निकाय को विधायी, कार्यकारी और वित्तीय अधिकार दिए जाने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि, यह व्यवस्था राज्य का दर्जा बहाल करने के समान नहीं होगी।

नई दिल्ली में गृह मंत्रालय की उपसमिति की बैठक में केंद्र और लद्दाख के प्रतिनिधियों ने राजनीतिक ढांचे से जुड़े आठ से दस प्रमुख मुद्दों पर पहले आम सहमति बनाने का निर्णय लिया। इसके बाद प्रस्तावित संवैधानिक व्यवस्था का कानूनी मसौदा तैयार किया जाएगा। केंद्र और लद्दाख के प्रतिनिधियों की अगली बैठक अक्टूबर के पहले पखवाड़े में होने की संभावना है।

लद्दाख के मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा के अनुसार, विशेष संवैधानिक ढांचे के तहत केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर निर्वाचित संस्था बनाने के प्रस्ताव पर चर्चा आगे बढ़ी है। लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के प्रतिनिधियों ने इस बात पर सहमति जताई कि इस निकाय के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन क्षेत्रों के माध्यम से होने चाहिए। इसके अलावा लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों और प्रस्तावित केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय निकाय के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट करना भी जरूरी होगा।

केंद्र ने स्पष्ट किया कि वह लद्दाख पर ऐसा कोई मॉडल नहीं थोपना चाहता, जिसे स्थानीय लोग स्वीकार न करें। छठी अनुसूची में लद्दाख को शामिल करने की पुरानी मांग पर चर्चा के बाद वर्तमान प्रस्ताव सामने आया है। हालांकि, केंद्र के इस प्रस्ताव से लद्दाख के स्थानीय संगठनों में निराशा है। लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के नेताओं ने बैठक को लेकर असंतोष जताते हुए कहा कि उनकी ओर से गृह मंत्रालय को भेजी गई मांगों पर पर्याप्त चर्चा नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि बैठक का उद्देश्य प्रस्तावित लेह-कारगिल पदयात्रा से लोगों का ध्यान हटाना हो सकता है। संवाददाता सम्मेलन में सोनम वांगचुक, छेरिंग दोरजे, असगर अली करबलई, सज्जाद कारगिली और सांसद मोहम्मद हनीफा जान मौजूद रहे।

लद्दाख के स्थानीय संगठनों ने केंद्र के प्रस्ताव पर निराशा जताई है। लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का कहना है कि उनकी प्रमुख मांगों पर बैठक में पर्याप्त चर्चा नहीं हुई। संगठनों ने राज्य का दर्जा, संवैधानिक संरक्षण और स्थानीय अधिकारों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है। उनका कहना है कि लद्दाख के लोगों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए व्यापक सहमति के बाद ही कोई अंतिम व्यवस्था तय होनी चाहिए। प्रस्तावित निर्वाचित निकाय की शक्तियों और लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों के अधिकार क्षेत्र को लेकर भी स्थिति स्पष्ट करने की मांग की गई है।

17,618 फुट ऊंचाई पर लद्दाखी धावकों ने रचा जीत का इतिहास

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। लद्दाख में 17,618 फुट की ऊंचाई पर आयोजित 122 किलोमीटर की सिल्क रूट अल्ट्रा मैराथन और 72 किलोमीटर के खारदूंगला चैलेंज में स्थानीय धावकों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किए। लद्दाख पुलिस के नवांग सेरिंग ने 122 किलोमीटर की सिल्क रूट अल्ट्रा मैराथन 12 घंटे 12 मिनट में पूरी कर पहला स्थान हासिल किया। वहीं लद्दाख स्काउट्स के जिगमित स्टोब्दान ने 72 किलोमीटर के खारदूंगला चैलेंज को छह घंटे में पूरा कर जीत दर्ज की।

122 किलोमीटर की दौड़ में राजस्थान के सूरज मीना 12 घंटे 35 मिनट के समय के साथ दूसरे और लद्दाख के रिगजिन गुरमथ तीसरे स्थान पर रहे। महिला वर्ग में लद्दाख की तेंजिन डोल्मा ने 14 घंटे 29 मिनट में दौड़ पूरी कर खिताब जीता। इन धावकों ने बर्फीली हवाओं, बेहद कम तापमान, कम आक्सीजन और दुर्गम पहाड़ी रास्तों के बीच अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया।

सिल्क रूट अल्ट्रा मैराथन वीरवार शाम क्यागर गांव से शुरू हुई और शुक्रवार सुबह विजेताओं का लेह के एनडीएस स्टेडियम में स्वागत किया गया। दौड़ को लेह के नुब्रा क्षेत्र के क्यागर गांव से रवाना किया गया था। इस दौरान स्थानीय लोगों ने पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से देश-विदेश से आए धावकों का स्वागत किया। आयोजकों ने निर्धारित समय में दौड़ पूरी करने वाले प्रतिभागियों को अलग-अलग रंग की जैकेट और विशेष टोपी प्रदान की।

फ्लाईओवर की राह में उजड़ीं 39 दुकानें, पुनर्वास को लेकर घिरा प्रशासन

पुनर्वास से पहले उजड़ीं 39 दुकानें, दुकानदारों के सामने रोजी-रोटी का गहराया संकट

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। कुंजवानी-गांधी नगर फ्लाईओवर निर्माण के लिए सतवारी चौक और नई बस्ती की 39 दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के बाद प्रभावित दुकानदारों में रोजी-रोटी को लेकर चिंता बढ़ गई है। दुकानदारों का कहना है कि सरकार ने गोल गुजराल में वंडरलैंड पार्क के पास उनके पुनर्वास के लिए जमीन चिन्हित की है, लेकिन नई दुकानें तैयार और आवंटित होने से पहले ही पुरानी दुकानें तोड़ दी गईं।

प्रशासन ने बुधवार को बिजली कनेक्शन काटने के साथ दुकानें खाली करने के निर्देश दिए थे। अधिकांश दुकानदारों ने अपना सामान निकाल लिया था। प्रभावित दुकानदारों ने आरोप लगाया कि पिछले छह महीनों से नई दुकानें उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया जा रहा था, लेकिन अब तक आवंटन पत्र नहीं दिए गए। उनका कहना है कि दुकानें बनने में चार से छह महीने लगेंगे, तब तक परिवार का पालन-पोषण कैसे होगा।

नई बस्ती बाजार एसोसिएशन के प्रधान नवीन गुप्ता सहित दुकानदारों ने मांग की कि नई दुकानें बनने तक उन्हें अस्थायी स्थान उपलब्ध कराया जाए। पूर्व कारपोरेटर पवन सिंह ने प्रशासन पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री जम्मू के पूर्व वरिष्ठ उपप्रधान दीपक अग्रवाल ने भी पुनर्वास से पहले दुकानों को तोड़े जाने पर सवाल उठाते हुए जम्मू हाट की खाली दुकानों में अस्थायी व्यवस्था करने का सुझाव दिया। फ्लाईओवर परियोजना के पूरा होने से सतवारी, बिक्रम चौक और कुंजवानी के बीच यातायात सुगम होने तथा जाम से राहत मिलने की उम्मीद है।

मंडी में एलपीजी विस्फोट से चिनार कैफे जलकर खाक

भारतेंदु संवाददाता, पुंछ। पुंछ जिले के मंडी कस्बे में नवनिर्मित चिनार कैफे शुक्रवार तड़के दो एलपीजी सिलेंडरों में हुए विस्फोट के बाद लगी भीषण आग में पूरी तरह जलकर खाक हो गया। अधिकारियों के अनुसार घटना सुबह करीब तीन से चार बजे के बीच हुई। उस समय कैफे बंद था, इसलिए हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। बताया गया कि कैफे के अंदर रखे दोनों गैस सिलेंडरों में अचानक जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद आग तेजी से फैल गई। आग की लपटों ने कुछ ही समय में पूरे कैफे को अपनी चपेट में ले लिया। इससे कैफे का ढांचा, फर्नीचर और अन्य सामान पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया। विस्फोटों की तेज आवाज सुनकर आसपास के स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस तथा अग्निशमन विभाग को घटना की सूचना दी।

रामगढ़ में पाकिस्तान का झंडा लगा संदिग्ध गुब्बारा मिलने से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे सांबा जिले के रामगढ़ क्षेत्र में पाकिस्तान की ओर से आया संदिग्ध गुब्बारा मिलने से सुरक्षा एजेंसियों में हलचल मच गई। नंगा गांव के पास एक स्थानीय व्यक्ति को पालीथिन का गुब्बारा मिला। उस पर पाकिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज छपा था और उर्दू में स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं लिखी हुई थीं। संदिग्ध वस्तु मिलने की सूचना तुरंत सीमा पुलिस पोस्ट कामोर को दी गई।

सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और गुब्बारे को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने उसकी प्रारंभिक जांच की और सुरक्षा कारणों से उसे जब्त कर आगे की जांच शुरू कर दी। अधिकारियों की ओर से यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि गुब्बारा हवा के साथ पाकिस्तान की ओर से भारतीय क्षेत्र में पहुंचा या इसके पीछे कोई अन्य कारण था।

सीमा क्षेत्र में पहले भी पाकिस्तान की ओर से ड्रोन और अन्य संदिग्ध वस्तुओं के भारतीय क्षेत्र में पहुंचने की घटनाएं सामने आती रही हैं। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां इस घटना को गंभीरता से लेते हुए सभी पहलुओं की जांच कर रही हैं। गुब्बारा मिलने की जानकारी संबंधित सुरक्षा एजेंसियों को भी दी गई है।

पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां नंगा गांव तथा आसपास के इलाकों में किसी अन्य संदिग्ध गतिविधि की संभावना को देखते हुए निगरानी कर रही हैं। फिलहाल गुब्बारे की प्रकृति और उसके भारतीय क्षेत्र में पहुंचने के कारणों की जांच जारी है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी।

सिंहपोरा-वैलू सुरंग से चिनाब घाटी और कश्मीर के बीच बनेगा नया ऑल-वेदर मार्ग

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में चिनाब घाटी को दक्षिण कश्मीर से जोड़ने वाली बहुप्रतीक्षित सिंहपोरा-वैलू टनल के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनएचआइडीसीएल) ने 3567.51 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाले इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए टेंडर आमंत्रित किए हैं। नेशनल हाईवे-244 के किश्तवाड़-वैलू-खानाबल खंड पर बनने वाली यह परियोजना 60 महीने यानी पांच साल में पूरी की जाएगी।

इस परियोजना में सिन्थन पास के नीचे करीब 20.7 किलोमीटर लंबी ट्विन-ट्यूब सुरंग का निर्माण प्रमुख हिस्सा होगा। दोनों ट्यूब किश्तवाड़ जिले के छात्रू को अनंतनाग जिले के वैलू से जोड़ेंगी। बर्फबारी के दौरान सिन्थन टॉप मार्ग बंद होने से प्रभावित रहने वाली कश्मीर-चिनाब घाटी आवाजाही को इससे हर मौसम में बेहतर संपर्क मिलेगा। इससे यात्रा आसान होने के साथ पर्यटन, व्यापार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

परियोजना के तहत कुल 38.611 किलोमीटर लंबा हाईवे पैकेज इपीसी मोड में विकसित किया जाएगा। सुरंग की बाईं ट्यूब 10.331 और दाईं ट्यूब 10.363 किलोमीटर लंबी होगी। दोनों ट्यूबों को हर 500 मीटर पर क्रॉस-पैसेज से जोड़ा जाएगा। सुरंग में आपातकालीन निकासी, अग्निशमन, सीसीटीवी, संचार, यातायात नियंत्रण और आधुनिक प्रकाश व्यवस्था जैसी सुविधाएं होंगी। एप्रोच रोड पर 21 पुल, वायाडक्ट और कल्वर्ट भी बनाए जाएंगे।

परियोजना के पूर्वी पोर्टल की ऊंचाई करीब 2243 मीटर और पश्चिमी पोर्टल की ऊंचाई करीब 2404 मीटर होगी। निर्माण पूरा होने के बाद 120 महीने तक रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित कंपनी की रहेगी। इस परियोजना को 2017 में मंजूरी मिली थी और 2021 में इसे फिर से दोहराया गया था, लेकिन तकनीकी कारणों से निर्माण आगे नहीं बढ़ पाया था। अब टेंडर जारी होने से इसके धरातल पर उतरने की उम्मीद बढ़ गई है। सुरंग बनने से कश्मीर और चिनाब घाटी के बीच संपर्क मजबूत होने के साथ सामरिक दृष्टि से भी क्षेत्र को महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा।

सियासत चिनाब वैली में पार्टी का जनाधार बढ़ने की उम्मीद, महबूबा मुफ्ती ने किया अनुभवी नेता का स्वागत

पूर्व एमएलसी असगर अली के पीडीपी में शामिल होने से बढ़ी ताकत

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर की सियासत में महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत किश्तवाड़ के वरिष्ठ राजनीतिक नेता और पूर्व विधान परिषद सदस्य सैयद असगर अली पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) में शामिल हो गए। पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की मौजूदगी में उन्होंने पीडीपी की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी ने उनके शामिल होने को चिनाब वैली में संगठन को मजबूती देने वाला महत्वपूर्ण कदम बताया है। इस मौके पर पीडीपी के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे।

पीडीपी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि असगर अली का पार्टी में शामिल होना चिनाब वैली में संगठन के लिए मजबूत राजनीतिक संदेश है। उनके अनुभव और क्षेत्र में जनसंपर्क से पार्टी को किश्तवाड़ के साथ-साथ डोडा और रामबन क्षेत्रों में भी अपनी गतिविधियां मजबूत करने में मदद मिल सकती है। पार्टी ने कहा कि यह कदम लोगों की आकांक्षाओं को साहस, गरिमा और दृढ़ विश्वास के साथ उठाने के उसके संकल्प को और मजबूती देता है।

प्रशासनिक सेवा से राजनीति तक का सफर : सैयद असगर अली लंबे प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव वाले नेता हैं। वह 1977 बैच के जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे हैं। प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रखा और पीडीपी के टिकट पर विधान परिषद सदस्य भी चुने गए। क्षेत्र की राजनीति और प्रशासनिक मामलों की गहरी समझ के कारण उन्हें चिनाब वैली में प्रभावशाली नेताओं में गिना जाता है।

असगर अली का परिवार भी प्रशासनिक क्षेत्र में अपनी पहचान रखता है। उनकी बेटी सैयद सहरिश असगर प्रशासनिक सेवा की अधिकारी हैं। सहरिश असगर ने वर्ष 2011 में जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में शीर्ष स्थान हासिल किया था। बाद में उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में भी बेहतर प्रदर्शन किया।

महबूबा मुफ्ती ने किया स्वागत : पीडीपी में शामिल होने के दौरान पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने असगर अली का स्वागत किया। कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेता अब्दुल रहमान वीरी, अब्दुल हक खान, खुर्शीद आलम, त्राल के विधायक रफीक नाइक और राजेंद्र मनहास समेत कई नेता मौजूद रहे। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि असगर अली जैसे अनुभवी नेता के पार्टी से जुड़ने से संगठन को उनके राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव का लाभ मिलेगा।

पीडीपी नेतृत्व का मानना है कि असगर अली के आने से पार्टी की जमीनी पहुंच को बढ़ाने में मदद मिलेगी। खासकर किश्तवाड़ और आसपास के इलाकों में उनके पुराने राजनीतिक संपर्क पार्टी के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं।

चिनाब वैली पर पार्टी की नजर : चिनाब वैली में लंबे समय से विभिन्न राजनीतिक दल अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। किश्तवाड़, डोडा और रामबन क्षेत्र राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं।

महिलाओं की गरिमा शरीर में नहीं विचारों और कर्मों में बसती है

डॉ अंकिता चौधरी
(सह-प्राध्यापक) अभिलाषी विश्वविद्यालय, मंडी (हि .प्र .)

यह शीर्षक असहज कर सकता है। कुछ लोगों को यह कठोर लगेगा, कुछ इसे साहसिक कहेंगे, तो कुछ इसे अनावश्यक रूप से उत्तेजक मानेंगे। लेकिन कभी-कभी समाज को आईना दिखाने के लिए ऐसे शब्दों की आवश्यकता होती है जो हमारी सुविधा के घेरे को तोड़ दें। प्रश्न यह नहीं है कि शीर्षक असहज क्यों है; प्रश्न यह है कि वह यथार्थ, जिसकी ओर यह संकेत करता है, आज भी हमारे बीच क्यों मौजूद है। जब तक समाज अपनी असुविधाजनक सच्चाइयों का सामना करने का साहस नहीं जुटाता, तब तक परिवर्तन केवल नारों और अभियानों तक सीमित रहता है। वास्तविक बदलाव तब आता है जब हम अपने व्यवहार, अपनी भाषा और अपनी सोच का ईमानदारी से मूल्यांकन करते हैं।

हम अक्सर कहते हैं कि भारत महिलाओं का सम्मान करने वाला देश है। हम देवी की पूजा करते हैं, नारी को शक्ति का स्वरूप मानते हैं और माँ को सर्वोच्च स्थान देते हैं। लेकिन यदि इन आदर्शों के पीछे छिपे व्यवहार को देखें तो एक गहरी विडंबना सामने आती है। वही समाज, जो नारी को पूजनीय बताता है, उसकी पहचान को बार-बार उसके शरीर तक सीमित कर देता है। उसकी बुद्धि, संवेदनशीलता, संघर्ष, श्रम, उपलब्धियाँ और व्यक्तित्व पीछे छूट जाते हैं, जबकि उसके शरीर को लेकर बहस कभी समाप्त नहीं होती। यही विरोधाभास हमारी सामाजिक चेतना के सामने सबसे बड़ा प्रश्न बनकर खड़ा है।

आज भी किसी महिला की योग्यता से पहले उसके पहनावे पर चर्चा होती है। किसी छात्रा की उपलब्धि से अधिक उसकी तस्वीर पर टिप्पणियाँ की जाती हैं। किसी महिला अधिकारी, पत्रकार, प्रोफेसर, कलाकार, खिलाड़ी या राजनेता के विचारों की बजाय उसके चेहरे, रंग, उम्र या शरीर को विश्लेषण का विषय बना दिया जाता है। यह केवल कुछ व्यक्तियों का व्यवहार नहीं, बल्कि उस मानसिक संरचना का परिणाम है जिसे हमने पीढ़ियों से सामान्य मान लिया है। धीरे-धीरे यह सोच सामाजिक संस्कृति का हिस्सा बन जाती है और हमें इसका अहसास भी नहीं होता।

समस्या यह नहीं कि स्त्री सुंदर है। समस्या यह है कि समाज उसकी सुंदरता को उसकी सबसे बड़ी पहचान बना देता है। उसकी प्रतिभा को गौण और उसके शरीर को प्रधान बना देना ही वस्तुकरण है। जब किसी व्यक्ति को उसकी संपूर्ण मानवता के बजाय उसके शरीर के किसी हिस्से तक सीमित कर दिया जाए, तब उसके अधिकार, उसकी गरिमा और उसकी स्वतंत्रता भी धीरे-धीरे सीमित होने लगती है। किसी भी सभ्य समाज के लिए यह स्थिति चिंता का विषय होनी चाहिए, क्योंकि इससे समानता का मूल सिद्धांत कमजोर होता है।

यह प्रवृत्ति केवल सड़क या सार्वजनिक जीवन तक सीमित नहीं है। विज्ञापनों में उत्पाद बेचने के लिए स्त्री-शरीर का उपयोग, फिल्मों और मनोरंजन की दुनिया में महिला पात्रों को केवल आकर्षण का माध्यम बनाना, सोशल मीडिया पर महिलाओं को लाइक्स और फॉलोअर्स के पैमाने पर तौलना—ये सब उसी सोच के विस्तार हैं। डिजिटल युग ने अवसरों के साथ-साथ स्त्री के वस्तुकरण के नए मंच भी तैयार किए हैं। एल्गोरिद्म ध्यान आकर्षित करने वाली सामग्री को आगे बढ़ाते हैं और कई बार स्त्री की देह को उपभोग की वस्तु में बदल देते हैं। यह केवल तकनीक की समस्या नहीं, बल्कि उस सामाजिक मानसिकता का प्रतिबिंब है जो दर्शकों की पसंद को आकार देती है।

इसका सबसे दुखद रूप तब दिखाई देता है जब किसी महिला के साथ अपराध होता है। चर्चा अपराधी की मानसिकता पर कम और पीड़िता के कपड़ों, समय, मित्रों या जीवनशैली पर अधिक होने लगती है। यह प्रवृत्ति न्याय के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है। अपराध का उत्तरदायित्व अपराधी का होता है, पीड़ित का नहीं।

(ये लेखिका के निजी विचार हैं)

सही मात्रा और गुणवत्ता वाला संतुलित भोजन बीमारियों से बचाव में सहायक

केशव शर्मा 'रसिक'
स्वतन्त्र लेखक ,गांव-कोटला, घुमारवीं।

स्वस्थ जीवन के लिए केवल भरपेट भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि संतुलित आहार लेना भी उतना ही आवश्यक है। संतुलित आहार वह भोजन है जिसमें शरीर की आवश्यकता के अनुसार सभी पोषक तत्व—कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, रेशा (फाइबर) और पर्याप्त मात्रा में पानी, उचित अनुपात में शामिल हों। यही आहार शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, रोगों से बचाता है और मानसिक व शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन की मात्रा के साथ-साथ उसकी गुणवत्ता पर भी ध्यान देना आवश्यक है।

आज की भागदौड़ भरी जीवनशैली में लोग अक्सर स्वाद और सुविधा को प्राथमिकता देते हैं, जिसके कारण फास्ट फूड, तली-भुनी चीजें और पैकेज्ड खाद्य पदार्थों का सेवन बढ़ गया है। समय की कमी के कारण बहुत से लोग घर के पौष्टिक भोजन के बजाय बाहर का भोजन करना अधिक पसंद करते हैं। इसका परिणाम मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और पाचन संबंधी समस्याओं के रूप में सामने आता है। यदि हम अपने दैनिक भोजन में संतुलित आहार को शामिल करें तो इन बीमारियों से काफी हद तक बचा जा सकता है। स्वस्थ भोजन की आदतें शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ रखने में सहायता करती हैं।

संतुलित आहार शरीर को पूरे दिन कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा देता है। यह मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत बनाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है तथा शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत और नई कोशिकाओं के निर्माण में सहायता करता है। बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास, युवाओं की कार्यक्षमता तथा बुजुर्गों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार अत्यंत आवश्यक है। भोजन में पर्याप्त पोषक तत्व होने से शरीर में कमजोरी और थकान कम होती है तथा व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों को अधिक सक्रियता के साथ कर पाता है।

संतुलित आहार में हमें ताजे फल और हरी पत्तेदार सब्जियां, साबुत अनाज जैसे गेहूं, जौ, बाजरा और ओट्स, दालें, राजमा, चना, सोयाबीन तथा अन्य प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ, दूध, दही, पनीर और अन्य दुग्ध उत्पाद शामिल करने चाहियें। इसके अलावा सीमित मात्रा में स्वस्थ वसा जैसे मेवे, बीज और सरसों या मूंगफली का तेल, पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पानी को रोज़मर्रा के जीवन में नियमित रूप से शामिल करना चाहिये। अलग-अलग प्रकार के खाद्य पदार्थों का सेवन करने से शरीर को विभिन्न पोषक तत्व आसानी से प्राप्त होते हैं। भोजन में मौसमी फल और सब्जियों को प्राथमिकता देना भी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है।

संतुलित आहार अपनाने से जहां हमारे शरीर को भरपूर ऊर्जा मिलती है, वहीं शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। वजन नियंत्रित रहता है तथा पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है। हृदय, मधुमेह और मोटापे जैसी बीमारियों का खतरा कम होता है। मानसिक एकाग्रता और कार्यक्षमता बढ़ती है तथा त्वचा, बाल और हड्डियां स्वस्थ रहती हैं। पर्याप्त पोषण मिलने से व्यक्ति स्वयं को अधिक ऊर्जावान महसूस करता है और उसकी दैनिक गतिविधियों में सक्रियता बनी रहती है। संतुलित भोजन शरीर के साथ-साथ मन को भी स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

बच्चों के लिए संतुलित आहार का विशेष महत्व है, क्योंकि बढ़ती उम्र में शरीर और मस्तिष्क के विकास के लिए पर्याप्त पोषण आवश्यक होता है। बच्चों के भोजन में दूध, दही, फल, सब्जियां, दालें और अनाज जैसे पौष्टिक खाद्य पदार्थ शामिल होने चाहियें। इसी प्रकार युवाओं को अपनी कार्यक्षमता और व्यस्त दिनचर्या के अनुसार पौष्टिक भोजन लेना चाहिए। बुजुर्गों के लिए ऐसा भोजन अधिक उपयोगी होता है जो आसानी से पच सके और शरीर को आवश्यक पोषण भी प्रदान करे।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

संपादकीय

कमजोर होता पाक लोकतंत्र

श्रीराम कालेज आफ कामर्स में पांच सितंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि पाकिस्तान कोई नापाक हरकत करता है तो भारत के जांबाज उसके घर में घुसकर प्रहार करते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और आपरेशन सिंदूर इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। इन सैन्य कार्रवाइयों ने यह संदेश दिया कि भारत अब सीमा पार आतंकवाद का जवाब अपनी शर्तों पर देने में सक्षम है। हालांकि इन अभियानों को लेकर पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व ने अपने देश की जनता के सामने अलग ही कहानी पेश करने का प्रयास किया। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने अपनी सेना की छवि बचाने के लिए यह दावा किया कि उनकी फौज ने भारत को रोक दिया था।

मुनीर की यह रणनीति घरेलू स्तर पर काफी प्रभावी रही। आपरेशन सिंदूर में थलसेना की प्रत्यक्ष भूमिका सीमित होने के बावजूद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उन्हें पदोन्नत कर फील्ड मार्शल की रैंक प्रदान कर दी। इसके बाद मुनीर ने अपने प्रभाव को और बढ़ाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ पाकिस्तान के सैन्य-राजनीतिक नेतृत्व की निकटता ने भी मुनीर की स्थिति मजबूत करने में भूमिका निभाई। भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता को लेकर ट्रंप के दावों का समर्थन कर पाकिस्तान ने अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहां तक कि उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किए जाने का समर्थन भी किया गया।

पाकिस्तान के राजनीतिक इतिहास में सेना हमेशा सत्ता का सबसे शक्तिशाली केंद्र रही है। निर्वाचित सरकारें और प्रधानमंत्री प्राय: सेना के प्रभाव के सामने कमजोर साबित होते रहे हैं। हालांकि मुनीर ने इस अंतर को और बढ़ाते हुए सत्ता के लगभग हर क्षेत्र में सैन्य हस्तक्षेप को मजबूत किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने सेना प्रमुख के पद को संवैधानिक और कानूनी संरक्षण देने की दिशा में ऐसे कदम उठाए हैं, जिनसे भविष्य में निर्वाचित सरकार के लिए सैन्य नेतृत्व पर नियंत्रण रखना और कठिन हो जाएगा।

पाकिस्तानी सेना लंबे समय से स्वयं को देश का वास्तविक संरक्षक और शासक मानती रही है। नौसेना और वायुसेना को भी थलसेना की तुलना में अपेक्षाकृत कमजोर स्थिति में रखा गया है। अब इस असमानता को कानूनी आधार भी मिलने लगा है। 20 अगस्त को पाकिस्तानी संसद ने डिफेंस फोर्सेज आफ पाकिस्तान एक्ट, 2026 को मंजूरी दी। इसके साथ नेशनल कमांड अथारिटी एक्ट में भी संशोधन किया गया। इन बदलावों की नींव पिछले वर्ष नवंबर में संविधान के 27वें संशोधन के जरिए रखी गई थी। इसके परिणामस्वरूप पूरे सैन्य प्रतिष्ठान पर सेना प्रमुख का प्रभाव पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है।

27वें संविधान संशोधन के तहत चीफ आफ डिफेंस फोर्सेज यानी सीडीएफ का पद बनाया गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पद सेना प्रमुख के पास ही रहेगा। सीडीएफ को रणनीतिक मामलों पर व्यापक नियंत्रण दिया गया है। इसके तहत नौसेना और वायुसेना के रणनीतिक, परिचालन और प्रशासनिक मामलों पर भी सेना प्रमुख का प्रभाव बढ़ जाएगा। सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति और तबादलों में निर्वाचित सरकार की भूमिका सीमित होने की आशंका है। इससे पाकिस्तान की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सेना की पकड़ और मजबूत होगी।

परमाणु हथियारों के मामले में यह बदलाव भारत के लिए विशेष चिंता का विषय है। नेशनल कमांड अथारिटी में संशोधन के बाद सीडीएफ को उस व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका मिलेगी, जो पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के संचालन से जुड़े फैसले करती है। परमाणु शस्त्रागार की सुरक्षा से जुड़े सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति में भी सीडीएफ की भूमिका बढ़ जाएगी। इसका अर्थ यह है कि पाकिस्तान की सामरिक शक्ति का नियंत्रण और अधिक केंद्रीकृत हो सकता है।

पाकिस्तान में लोकतांत्रिक व्यवस्था पहले से ही कमजोर रही है। विदेश नीति और सुरक्षा नीति जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सेना का प्रभाव किसी से छिपा नहीं है। अब यदि सेना प्रमुख को कानूनी तौर पर और अधिक अधिकार मिलते हैं तो निर्वाचित सरकार की भूमिका और कमजोर होना स्वाभाविक है। भारत के लिए यह स्थिति इसलिए चिंताजनक है, क्योंकि पड़ोसी देश के साथ किसी भी संवाद या तनाव कम करने की प्रक्रिया में वहां की राजनीतिक सरकार की वास्तविक क्षमता महत्वपूर्ण होती है। यदि अंतिम निर्णय सैन्य नेतृत्व के हाथों में ही रहेगा तो राजनीतिक संवाद की संभावनाएं भी सीमित होंगी।

भारत के प्रति आसिम मुनीर का रुख पहले से ही आक्रामक रहा है। उनकी वैचारिक सोच में पाकिस्तान के द्विराष्ट्र सिद्धांत और भारत विरोध की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी भूमिका को लेकर मिली चर्चा उनके आत्मविश्वास को और बढ़ा सकती है। ऐसे में पाकिस्तान की घरेलू राजनीति में सेना की बढ़ती ताकत भारत के लिए नई चुनौती बन सकती है। हालांकि मुनीर के सामने अफगानिस्तान से बढ़ते मतभेद, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और बलूच विद्रोह जैसी आंतरिक एवं क्षेत्रीय चुनौतियां भी हैं।

- शिवांश धाकड़

कविता

दो कदम साथ ना चल सके ?

संजय एम तराणेकर (कवि, लेखक व समीक्षक)
इन्दौर-452011 (मध्य प्रदेश)

जिसने तुम्हें जीवन दिया,
अपनी हर खुशी तुम पर वार दी,
खुद जागकर रातें काटीं,
तुम्हारे हिस्से नींद उतार दी।
उंगली थामकर चलना सिखाया,
गिरने पर हर बार संभाला,
अपने हिस्से की धूप सहकर,
तुम्हें सदा छांव में पाला।
आज वही चेहरा थका-सा है,
समय की रेखाओं में खोया,
जिस आंगन में जीवन महका,
वह आंगन आंसुओं में रोया।
आज अंतिम यात्रा की बेला है,
हर रिश्ता गहरा हो आया,
कौन अपना, कौन पराया है,
सच ने सबका चेहरा दिखाया।
जिसने तुम्हें जीवन दिया था,
क्या तुम उसके साथ चलोगे ?
उसके अंतिम सफर में क्या,
दो कदम भी साथ चलोगे ?
क्या रिश्ते अब स्क्रीन पर हैं,
संदेशों में निभते जाते हैं ?
पैसे भेजकर फर्ज समझकर,
क्या अहसान जताते जाते हैं ?
एक स्पर्श की कीमत पूछो,
जब हाथ सदा के लिए छूटे,
एक बार गले लगाने को,
कितने रिश्ते पीछे छूटे।

एक ही चट्टान से निर्मित महादेव मंदिर में आज भी जीवंत हैं प्राचीन धार्मिक परंपराओं की झलक

तुलसी राम डोगरा
स्वतंत्र लेखक, पालमपुर

हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के अंतर्गत आता सुंदरनगर वास्तव में सौंदर्य का बेजोड़ नमूना है। एक ओर हरी-भरी घाटियों के नयनाभिराम और विहंगम दृश्य सैलानियों को बरबस अपनी ओर आकर्षित करते हैं, वहीं दूसरी ओर इसके इर्द-गिर्द स्थित पुरातन एवं ऐतिहासिक धार्मिक-पर्यटन स्थल हर किसी को अपनी ओर खींच लेते हैं। अपने अभूतपूर्व सौंदर्य से सैलानियों को मंत्रमुग्ध करने के साथ-साथ यहां के प्राचीन धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के हृदय को भी आनंदित करते हैं। इसी कड़ी में सुंदरनगर में स्थित भगवान भोलेनाथ को समर्पित महादेव मंदिर अपनी दिव्यता, प्राचीनता और अद्भुत शिल्पकला के कारण विशेष आकर्षण का केंद्र है।

किंवदंतियों के अनुसार सभी पांडव शिव भक्त थे और कहा जाता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने सुंदरनगर के इर्द-गिर्द तीन मंदिर स्थापित किए थे, जिनमें यह महादेव मंदिर भी शामिल है। मान्यता है कि पांडव यहां पूजा-अर्चना किया करते थे। जनश्रुति के अनुसार पूजा के दौरान पांडव एक बहुत विशाल ढोल भी बजाया करते थे, जिसे भीम का ढोल कहा जाता है और जो आज भी मंदिर के भीतर प्रत्यक्ष रूप में विद्यमान है। मंदिर की ऐतिहासिकता इसकी शिल्पकला, पत्थरों और दीवारों पर हुई उत्कृष्ट नक्काशी से सहज ही ज्ञात होती है। भित्तियों और गुम्बदों में उकेरी गई चित्रकारी तथा विभिन्न देवी-देवताओं की सुंदर प्रतिमाएं मंदिर की भव्यता में चार चांद लगाती हैं।

मान्यता है कि यह मंदिर एक ही चट्टान से बना हुआ है। मंदिर के अंदर अवस्थित पुरातन शिवलिंग और उसके साथ फन फैलाए नाग देवता की प्रतिमा श्रद्धालुओं का मन मोह लेती है। शिवलिंग पर गागर से अविरल टपकती जलधारा का दृश्य मन को आत्मविभोर कर देता है। यहां अखंड ज्योति भी रात-दिन निर्बाध रूप से जलती रहती है। भोलेशंकर तथा मां पार्वती की अलौकिक प्राचीन मूर्तियों के आगे हर कोई नतमस्तक हुए बिना नहीं रह सकता। मंदिर के प्रवेश द्वार के ऊपर गणेशजी की उत्कृष्ट प्रतिमा विद्यमान है, वहीं शिव-पार्वती, शेर, दुर्गा माता और पंचमुखी हनुमानजी की प्रतिमाएं भक्तजनों का मन मोह लेती हैं।

मंदिर के बाहरी चारों ओर उत्कीर्ण की गई नक्काशी और विभिन्न देवी-देवताओं की उकेरी गई अद्भुत प्रतिमाएं वास्तव में हृदय तल को छू लेती हैं। मंदिर प्रांगण में वटवृक्ष की तरह फैले पीपल के पेड़ के नीचे अवस्थित हनुमानजी की भव्य प्रतिमा भी अलौकिक आनंद प्रदान करती है। भक्तजन हनुमानजी तथा पीपल देवता को धूप-दीप, जल और पुष्प अर्पित कर पूजा-अर्चना करते हुए अक्सर देखे जा सकते हैं। पीपल के इर्द-गिर्द श्रद्धालुओं द्वारा की जाने वाली परिक्रमा का दृश्य मंदिर की दिव्यता को और बढ़ा देता है।

मंदिर में पूर्ण शिव चालीसा भी अंकित की गई है। सुबह-शाम आरती करने की परंपरा अनवरत चली आ रही है। आरती के समय विद्युत चलित नगाड़े की कर्णप्रिय ध्वनि श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर देती है और भक्तजन भक्ति सागर में इस कदर रम जाते हैं जैसे उनका भोलेनाथ से प्रत्यक्ष संवाद हो रहा हो। मंदिर में अनेक प्राचीन मूर्तियों के अतिरिक्त पुरातन पाषाण प्रतिमाएं भी मौजूद हैं। मंदिर की बाहरी दीवारों पर बड़ी बारीकी से उत्कीर्ण विभिन्न देवी-देवताओं की सुंदर प्रतिमाएं इसकी शोभा में और भी इजाफा करती हैं।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

व्यक्तित्व विशेष

अभिनय से समाजसेवा तक अमला

अमला अक्किनेनी भारतीय सिनेमा की उन अभिनेत्रियों में शामिल हैं, जिन्होंने अभिनय के साथ शास्त्रीय नृत्य और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में भी अपनी अलग पहचान बनाई। **12 सितंबर 1967** को पश्चिम बंगाल के कलाइकुंडा में जन्मीं अमला का पूरा नाम अमला मुखर्जी था। उनके पिता बंगाली और मां आयरिश मूल की थीं। बाद में उनका परिवार चेन्नई चला गया, जहां उनका पालन-पोषण हुआ। अमला ने कलाक्षेत्र फाउंडेशन, चेन्नई से भरतनाट्यम में ललित कला स्नातक की शिक्षा प्राप्त की और देश-विदेश में अनेक मंचों पर अपनी नृत्य प्रस्तुतियां दीं।

अमला अक्किनेनी
जन्म : 12 सितंबर 1967

भरतनाट्यम में प्रशिक्षित अमला को फिल्मों में आने का अवसर निर्देशक टी. राजेंद्र के प्रयासों से मिला। वर्ष 1986 में उन्होंने फिल्म 'मिथिली एन्नई काधली' से तमिल सिनेमा में कदम रखा। फिल्म सफल रही और इसके बाद उन्होंने 'मेल्ला थिरंधथु कधवु', 'पन्नीर नधिगल' और 'वेलैक्करन' जैसी फिल्मों में काम किया। 1986 से 1992 के बीच वह तमिल फिल्म उद्योग की प्रमुख अभिनेत्रियों में रहीं। इसके बाद उन्होंने तेलुगु, मलयालम, हिंदी और कन्नड़ फिल्मों में भी अभिनय किया। अभिनेता नागार्जुन के साथ उनकी जोड़ी को भी दर्शकों ने खूब पसंद किया। दोनों ने 'शिवा' और 'निर्णयम' जैसी चर्चित फिल्मों में साथ काम किया।

अमला ने 1991 में मलयालम फिल्म 'उल्लाडक्कम' में अपने अभिनय से विशेष पहचान बनाई और इसके लिए उन्हें फिल्मफेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 1992 में नागार्जुन से विवाह के बाद उन्होंने अभिनय से दूरी बना ली। करीब दो दशक बाद वर्ष 2012 में तेलुगु फिल्म 'लाइफ इज ब्यूटीफुल' से उन्होंने फिल्मों में वापसी की। इस फिल्म में उनके अभिनय को सराहना मिली और उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। इसके बाद उन्होंने मलयालम सिनेमा में भी वापसी की। अमला अक्किनेनी की पहचान केवल अभिनेत्री के रूप में नहीं है। वह पशु कल्याण और पशु अधिकारों के लिए भी सक्रिय रही हैं। वह हैदराबाद स्थित ब्लू क्रॉस ऑफ हैदराबाद की सह-संस्थापक हैं, जो पशुओं के संरक्षण और उनके कल्याण के लिए कार्य करता है।

मणिमहेश की कठिन राह भी नहीं रोकती श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास के कदम

आनंद स्वरूप धीमान
सेवानिवृत्त कोषाधिकारी, पंचरुखी, जिला कांगड़ा

मणिमहेश यात्रा हिमाचल प्रदेश की सबसे प्रमुख धार्मिक यात्राओं में से एक है, जिसका अपना एक विशेष महत्व है। यह यात्रा प्रत्येक वर्ष श्रीकृष्ण जन्माष्टमी से लेकर राधाष्टमी तक लगातार चलती है और प्रकृति आपदाओं के होते हुए भी श्रद्धालु अपनी श्रद्धा एवं आस्था लिए बिना अवरोध अपनी यात्रा जारी रखते हैं। परंतु प्रकृति आपदा को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन द्वारा पंजीकरण करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा की तहसील भरमौर में यह प्रसिद्ध तीर्थ स्थान स्थित है, जो समुद्र तल से लगभग 13,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को कठिन पहाड़ी रास्तों के साथ-साथ प्रकृति के अद्भुत नजारों का भी अनुभव होता है।

मणिमहेश पर्वत पर भोर के समय यानी सुबह चार बजे एक ज्योति रूपी प्रकाश उभरता है। उसी को ही मणि के नाम से जाना जाता है, जिसके दर्शन हो जाना ही यात्रा का सफल होना माना जाता है। कभी-कभी तो यह प्रकाश सीधा पर्वत की गोद में बनी झील पर पड़ता है, जिसको स्थानीय भाषा में डल के नाम से भी जाना जाता है। यह इस बात का भी प्रतीक माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बने आसन पर विराजमान हैं और यह जो अलौकिक प्रकाश है, वह उनके गले में विराजित नाग की मणि का प्रकाश है। इसी कारण इस स्थान को मणिमहेश के नाम से जाना जाता है।

श्रद्धालु अपनी श्रद्धा लिए ऊंचे-ऊंचे पहाड़ी और उबड़-खाबड़ रास्तों को बिना किसी झिझक के बीचों-बीच चलते हुए अपनी यात्रा को संपूर्ण करते हैं। सभी रमणीय घाटियों को पार करते हुए श्रद्धालु मणिमहेश पहुंचते हैं। मणिमहेश पहुंचकर पर्वत की गोद में बनी झील को देखकर हर कोई स्तब्ध रह जाता है। यह झील अपने आप में एक दर्शनीय स्थल है और श्रद्धालुओं के लिए विशेष आस्था का केंद्र भी है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु मणिमहेश में स्नान कर पूजा करते हैं और अपनी इच्छा पूरी होने पर यहां लोहे का त्रिशूल, छड़ी और झंडा चढ़ाते हैं। कई श्रद्धालुओं को यहां जात्रा चढ़ाते हुए भी देखा जा सकता है।

राधाष्टमी वाले दिन जब बड़े नहौण में यात्री यहां स्नान करते हैं तो इस स्नान का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। मान्यता है कि बड़े नहौण में स्नान करने से मनुष्य को कई रोगों से भी मुक्ति मिलती है। यही कारण है कि इस विशेष अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मणिमहेश पहुंचते हैं और पवित्र डल झील में स्नान कर भगवान भोलेनाथ की पूजा-अर्चना करते हैं। इस दौरान पूरा क्षेत्र श्रद्धालुओं के जयकारों से गूंज उठता है और चारों ओर भक्तिमय वातावरण देखने को मिलता है।

मणिमहेश यात्रा का प्रथम पड़ाव चंबा का चौगान है। यहां दूर-दूर से श्रद्धालु आकर चौगान में विश्राम करते हैं तथा उसके बाद अपनी अगली यात्रा प्रारंभ करते हैं। यानी मणिमहेश यात्रा चंबा से शुरू होकर राख, धरबाला जैसी प्रमुख जगहों से होते हुए अन्य कई स्थानों से गुजरते हुए भरमौर पहुंचती है। भरमौर स्थित चौरासी मंदिर में श्रद्धालु विश्राम करते हैं। इसके पश्चात सबसे प्रथम ब्रह्माणी देवी जी के मंदिर जाकर मणिमहेश यात्रा को प्रारंभ करने की अनुमति लेते हैं।

माता ब्रह्माणी के मंदिर की दूरी भरमौर से लगभग 6 किलोमीटर है, जो कि एक पहाड़ी पर स्थित है। मान्यता है कि मणिमहेश यात्रा तभी पूर्ण मानी जाती है, जब यह यात्रा श्री ब्रह्माणी माता के मंदिर से प्रारंभ की जाए। चंबा से भरमौर लगभग 65 से 67 किलोमीटर दूर है। यहां चौरासी एक धार्मिक स्थल है, जो 84 सिद्धों की तपोस्थली माना जाता है। यहां विश्व का एकमात्र धर्मराज मंदिर भी बताया जाता है। श्रद्धालु यहां दर्शन करने के पश्चात अपनी यात्रा सड़क मार्ग से हड़सर तक पूरी करते हैं, जो भरमौर से लगभग 13 किलोमीटर दूर है।

हड़सर के बाद खड़ी चढ़ाई शुरू होती है और लगभग 14 किलोमीटर का सफर पैदल तय करना पड़ता है। श्रद्धालु चाहें तो घोड़ों के ऊपर भी यह सफर तय कर सकते हैं। कठिन चढ़ाई के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं आती। रास्ते में पहला पड़ाव धनछौ आता है। इसके बाद बंदर घाटी से होते हुए आगे का पड़ाव गौरीकुंड आता है। इस पूरे मार्ग में श्रद्धालुओं को पहाड़ों की सुंदरता, ऊंची चोटियों, घाटियों और प्राकृतिक वातावरण का अद्भुत अनुभव होता है।

मणिमहेश की डल झील श्री महादेव जी की तपोस्थली मानी जाती है। इसलिए यात्री मणिमहेश के दर्शन करने के उपरांत यहां झील की परिक्रमा कर पुण्य का फल कमाते हैं। श्रद्धालुओं के लिए यह यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि आस्था, विश्वास और आत्मिक शांति प्राप्त करने का माध्यम भी है। कठिन रास्ते, ऊंची चढ़ाई और प्रकृति की चुनौतियां भी श्रद्धालुओं के कदम नहीं रोक पातीं। भगवान भोलेनाथ के प्रति अटूट श्रद्धा उन्हें हर कठिनाई को पार करने का साहस देती है। मणिमहेश यात्रा के दौरान प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पंजीकरण की व्यवस्था की जाती है। प्रकृति आपदा की आशंका को देखते हुए यह व्यवस्था और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

'भारतेन्दु शिखर'

प्रकाशक, मुद्रक, संपादक एवं स्वामी शिवांश धाकड़ द्वारा शर्मा भवन, न्यू रणजीत नगर, एप्पल फ्रूट मंडी, नजदीक ढली टनल, शिमला (हि.प्र.) 171006 से प्रकाशित एवं बायोसर्ट इंटरनेशनल प्रा. लि. प्लॉट नंबर 8, फेज-2 इंडस्ट्रियल एरिया, नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा (हि.प्र.), पिन नंबर-176047 से मुद्रित। समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन के लिए पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी तथा इनसे उत्पन्न समस्त विवाद शिमला न्यायालय के अधीन होंगे।

आरएनआई संदर्भ संख्या-HPHIN/2000/02437
ई-मेल : bhartendunewsmedia@gmail.com, फोन नंबर : 88946-77702

हमीरपुर में स्वाइन फ्लू का दूसरा मामला, दो वर्षीय बच्चा संक्रमित

एजेंसी, हमीरपुर

हमीरपुर जिले में स्वाइन फ्लू के मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। शुक्रवार को जिला अस्पताल में जांच के दौरान थाना बिवांर क्षेत्र के एक गांव निवासी दो वर्षीय मासूम में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई। बच्चे को सांस लेने में काफी परेशानी हो रही थी। उसकी हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे बेहतर उपचार के लिए कानपुर रेफर कर दिया। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, बच्चे की जांच जिला अस्पताल में कराई गई थी। रिपोर्ट में स्वाइन फ्लू की पुष्टि होने के बाद चिकित्सकों ने तत्काल उपचार की व्यवस्था की। सांस लेने में अधिक दिक्कत होने के कारण उसे कानपुर भेजने का निर्णय लिया गया। परिजनों को भी बच्चे की स्थिति को लेकर आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

इससे पहले भी जिले के एक मासूम में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। उसकी जांच कानपुर रीजेंसी में कराई गई थी, जहां रिपोर्ट में संक्रमण की पुष्टि हुई थी। अब जिला अस्पताल में दूसरे बच्चे के संक्रमित मिलने से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। लगातार सामने आ रहे मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। चिकित्सकों का कहना है कि सांस लेने में परेशानी, बुखार, खांसी या अन्य लक्षण दिखाई देने पर तत्काल चिकित्सकीय परामर्श लेना चाहिए। वहीं, संक्रमित मरीजों के संपर्क में आने से बचने और साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने की अपील भी की जा रही है। जिले में स्वाइन फ्लू के मामलों पर स्वास्थ्य विभाग लगातार नजर बनाए हुए है। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में संदिग्ध मरीजों की निगरानी बढ़ाने के साथ चिकित्सकों को भी आवश्यक सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि समय पर पहचान और उपचार से संक्रमण के गंभीर प्रभावों को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है।

240 करोड़ रुपए से होगा निर्माण, वाहनों की आवाजाही होगी आसान

अयोध्या-सुलतानपुर रोड पर बनेगा अंडरपास

एजेंसी, लखनऊ

अयोध्या और सुलतानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात जाम की समस्या से जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। इस मार्ग पर अंडरपास का निर्माण कराया जाएगा। परियोजना के लिए 240 करोड़ रुपये के बजट को केंद्रीय वित्त मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) को अब अंतिम हरी झंडी मिलने का इंतजार है। माना जा रहा है कि दशहरे से पहले परियोजना को स्वीकृति मिल सकती है और इसके बाद निर्माण प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

अयोध्या-सुलतानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग लखनऊ के प्रमुख व्यस्त मार्गों में शामिल है। इस मार्ग पर वाहनों की संख्या लगातार बढ़ने के कारण कई स्थानों पर यातायात दबाव बना रहता है। व्यस्त चौराहों और संपर्क मार्गों पर वाहनों की आवाजाही बढ़ने से जाम की स्थिति भी उत्पन्न होती है। अंडरपास बनने के बाद मुख्य मार्ग पर यातायात को सुचारु रखने में मदद मिलेगी और वाहन चालकों को बार-बार रुकने की परेशानी से राहत मिल सकेगी। परियोजना के लिए बजट स्वीकृत होने के बाद एनएचएआइ की ओर से निर्माण से जुड़ी तैयारियों को गति दी जाएगी।

इसमें तकनीकी प्रक्रिया, स्थल संबंधी आवश्यकताओं और अन्य औपचारिकताओं को पूरा किया जाना है। अधिकारियों की कोशिश है कि स्वीकृति मिलने के बाद काम में अनावश्यक देरी न हो। परियोजना को वर्ष 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अंडरपास के निर्माण से इस मार्ग पर आने-जाने वाले स्थानीय लोगों के साथ दूसरे शहरों से गुजरने वाले वाहन चालकों को भी सुविधा मिलने की उम्मीद है।

खासकर व्यस्त समय में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने में यह परियोजना महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। मार्ग पर जाम कम होने से वाहनों की गति और आवागमन व्यवस्था में सुधार होगा। वित्त मंत्रालय से 240 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी मिलना परियोजना के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब सभी की निगाहें अंतिम स्वीकृति और निर्माण शुरू होने पर हैं। दशहरे से पहले हरी झंडी मिलने की स्थिति में परियोजना पर जल्द काम शुरू होने की उम्मीद है।

एनएचएआइ का लक्ष्य तय समयसीमा में निर्माण पूरा कराकर मार्ग पर यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाना है। अंडरपास बनने के बाद अयोध्या-सुलतानपुर मार्ग पर यात्रियों को जाम से काफी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। निर्माण पूरा होने के बाद मार्ग पर वाहनों की आवाजाही सुचारु होगी और स्थानीय लोगों को आवागमन में समय की बचत के साथ जाम से राहत मिलेगी।

कानपुर में अधिवक्ताओं का लोक अदालत बहिष्कार, रजिस्ट्री दफ्तर भी कराया बंद

एजेंसी, कानपुर। कानपुर में बार एसोसिएशन और लायर्स एसोसिएशन ने शनिवार को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बहिष्कार का एलान किया है। दोनों संस्थाओं के संयुक्त तत्वावधान में बार एसोसिएशन परिसर में दो दिवसीय प्रदेश स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। शुक्रवार को सम्मेलन के दूसरे दिन विभिन्न जिलों से आए अधिवक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों के सामने राष्ट्रीय लोक अदालत के बहिष्कार का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया।

अधिवक्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश स्तर पर आंदोलन को तेज करने की रणनीति पर भी चर्चा की। सम्मेलन में हर बुधवार को पूरे प्रदेश में अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य से विरत रहने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके चलते शुक्रवार को कानपुर की अदालतों में भी कामकाज प्रभावित रहा और परिसर में सन्नाटा दिखाई दिया। न्यायिक कार्य से अधिवक्ताओं के विरत रहने के कारण ज्यादातर वादकारियों को अपने मुकदमों में अगली तारीख लेकर लौटना पड़ा।

इससे दूर-दराज से अदालत पहुंचे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं, कुछ अधिवक्ताओं ने रजिस्ट्री दफ्तर पहुंचकर नारेबाजी की और वहां का काम बंद करा दिया। रजिस्ट्री दफ्तर में काम प्रभावित होने से संपत्ति की रजिस्ट्री कराने पहुंचे लोगों को भी वापस लौटना पड़ा। विरोध के दौरान स्टांप वेंडरों और फोटोकॉपी की दुकानों पर भी कामकाज बंद रहा। अधिवक्ताओं का कहना है कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार होने तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में शामिल प्रतिनिधियों से भी आंदोलन को समर्थन देने और राष्ट्रीय लोक अदालत के बहिष्कार को सफल बनाने की अपील की गई।

न्यूज ब्रीफ

सपा सरकार में अराजकता और दंगे नहीं भूली जनताः ब्रजेश पाठक

एजेंसी, आजमगढ़। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उसके कार्यकाल में प्रदेश में गुंडागर्दी, अराजकता और दंगों का माहौल था। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता आज भी उस दौर को नहीं भूली है। खासकर आजमगढ़ और जौनपुर के लोग सपा शासन के हालात से परिचित हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय प्लाट और मकानों पर कब्जा करना आम बात थी। खेतों की लूट के साथ बहू-बेटियों की सुरक्षा भी चिंता का विषय बनी हुई थी। पाठक ने कहा कि भाजपा सरकार में कानून का राज स्थापित हुआ है और प्रदेश विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं और बाढ़ राहत कार्यों को लेकर भी अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

आजमगढ़ में सरयू उफान पर, खतरे के निशान से 54 सेमी ऊपर

एजेंसी, आजमगढ़। सगड़ी तहसील के उत्तर में बहने वाली सरयू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी का पानी खतरे के निशान से 54 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में जलस्तर में आठ सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। लगातार बढ़ते पानी से नदी किनारे बसे क्षेत्रों में चिंता बढ़ गई है। प्रशासन की ओर से जलस्तर पर निगरानी रखी जा रही है। स्थानीय लोगों को नदी के आसपास सतर्क रहने की सलाह दी गई है। ग्रामीणों का कहना है कि पानी बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। अधिकारियों द्वारा स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।

कानपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ा 25 मोहल्लों में 12 दिन से जलभराव

एजेंसी, कानपुर। गंगा का जलस्तर बढ़ने से मकड़ीखेड़ा समेत 25 मोहल्लों में 12 दिन से जलभराव है। पानी जमा रहने से गंदगी और मच्छरों की समस्या बढ़ गई है। इससे स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सिंचाई विभाग ने गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण परमियापुरवा नाला बंद कर दिया है। इसके चलते अटल घाट के पीछे खाली मैदान में भी पानी भर रहा है। वहीं, सिंहपुर-मैनावती मार्ग पर जलभराव से बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत हो रही है। गंगा बैराज और शुक्लागंज में जलस्तर चेतावनी बिंदु पार कर चुका है। लगातार बढ़ते पानी से प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की चिंता बढ़ गई है।

कारोबारी की हत्या के बाद तीन आरोपितों ने वीडियो में दी सफाई

एजेंसी, कानपुर। काकादेव थाना क्षेत्र के ओम चौराहे पर कारोबारी अमित कुमार गुप्ता की ईंट से सिर कुचलकर हत्या के मामले में नया मोड़ आया है। शुक्रवार सुबह तीन हत्यारोपितों ने वीडियो जारी कर खुद को निर्दोष बताया। पांच अगस्त की देर रात अमित दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान ओम चौराहे पर कार सवार चार युवकों में से एक सड़क पर पेशाब करने लगा। अमित ने उसे ऐसा करने से रोका तो युवकों ने उनके सिर पर ईंट से हमला कर दिया। गंभीर हालत में उन्हें छोड़कर आरोपित भाग निकले। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने तीनों आरोपितों के वीडियो की जांच शुरू कर दी है और उनके दावों की भी पड़ताल जारी है।

दवा कारोबारी हत्याकांड में नया मोड़ शालू के परिजनों ने बताया बेकसूर

एजेंसी, कानपुर। दवा कारोबारी विनीत मिनोचा हत्याकांड में जेल में बंद शालू के भाई-बहन ने उसे बेकसूर बताया है। गुरुवार को दोनों ने मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष रखा। भाई ने दावा किया कि शालू ने अपने ससुर की हत्या की कोई साजिश नहीं रची थी। उनका कहना था कि इस मामले में कहानी का दूसरा पहलू भी है और असली सच्चाई कुछ और हो सकती है। परिजनों ने कहा कि घटना वाली रात किटी पार्टी की आयोजक शालू थी, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि वह हत्या की साजिश में शामिल थी। उन्होंने उन आरोपों को भी गलत बताया, जिनमें कहा गया कि ससुर की हत्या के दौरान शालू पार्टी में नाच रही थी। इस बीच पुलिस अब दिवंगत के बेटे सुब्रत की भूमिका की भी जांच कर रही है।

सेवानिवृत्त विज्ञानी से 1 .29 करोड़ की ठगी, नौ आरोपितों पर चार्जशीट

एजेंसी, लखनऊ

आइवीआरआइ के सेवानिवृत्त विज्ञानी शुकदेव नंदी से 1.29 करोड़ रुपये की साइबर ठगी के मामले में पुलिस ने नौ आरोपितों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। सभी आरोपित जेल में बंद हैं। हाई कोर्ट की एकल पीठ उनकी जमानत अर्जी खारिज कर चुकी है। अब आरोपितों ने दोहरी पीठ में जमानत के लिए याचिका दायर की है। मामले में ट्रायल शुरू होने की तैयारी है।

पिछले वर्ष 17 से 20 जून के बीच साइबर ठगों ने नंदी को उनके घर में ही डिजिटल अरेस्ट कर लिया था। आरोपितों ने खुद को बेंगलुरु पुलिस और सीबीआई अधिकारी बताया। उन्होंने नंदी को धमकाते हुए कहा कि उनके आधार कार्ड से एक सिम खरीदी गई है, जिसका इस्तेमाल मानव तस्करी और जालसाजी में किया जा रहा है। आरोपितों की बातों और धमकियों से डरकर नंदी ने उनके बताए बैंक खातों में 1.29 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए।

बाद में ठगी का अहसास होने पर उन्होंने साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो धनराशि के लेनदेन से जुड़े कई तथ्य सामने आए। जांच में पता चला कि ठगी की रकम में से सबसे पहले 1.10 करोड़ रुपये लखनऊ स्थित श्री नारायणी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए थे। पुलिस ने लेनदेन और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपितों की पहचान कर कार्रवाई की।

प्रयागराज में गंगा-यमुना का फिर बढ़ा जलस्तर, बाढ़ का खतरा बरकरार

एजेंसी, प्रयागराज

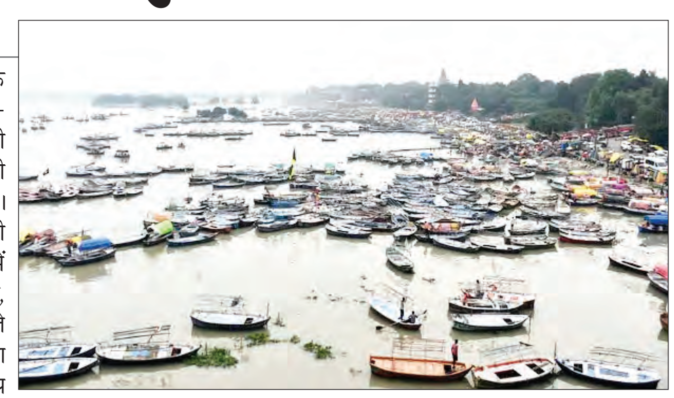

गंगा और यमुना के जलस्तर में लगातार उतार-चढ़ाव से प्रयागराज के नदी तटीय इलाकों में बाढ़ की आशंका अभी बनी हुई है। हालांकि पिछले दिनों की तुलना में कई क्षेत्रों में हालात कुछ सामान्य हुए हैं, लेकिन नदियों के बदलते जलस्तर ने लोगों की चिंता बढ़ा रखी है। तटीय मोहल्लों और गांवों के लोग जलस्तर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।

गुरुवार सुबह तक दोनों नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही थी। इसके बाद यमुना के पानी में कुछ कमी आने लगी। फाफामऊ क्षेत्र में यमुना का जलस्तर घटा है, जबकि छतनाग में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस उतार-चढ़ाव के कारण प्रशासन और नदी किनारे रहने वाले लोगों की निगाहें लगातार जलस्तर पर टिकी हुई हैं। पिछले दिनों गंगा-यमुना और टोंस नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण शहर के राजापुर समेत मेजा और करछना क्षेत्र के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए थे।

कई स्थानों पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। जलस्तर बढ़ने के कारण आवागमन प्रभावित हुआ और तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों के सामने सुरक्षित स्थानों पर जाने की चिंता खड़ी हो गई थी। अब पानी कम होने के बाद कुछ इलाकों में स्थिति सामान्य होने लगी है।

इसी बीच गंगा का पानी फिर बढ़ने से झूंसी स्थित बदरा की पुलिया के डूबने की स्थिति बनी हुई है। इससे आसपास के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जलस्तर में थोड़ी भी बढ़ोतरी होने पर निचले इलाकों में फिर से पानी पहुंचने का खतरा पैदा हो सकता है। यही वजह है कि लोग फिलहाल राहत की स्थिति को स्थायी नहीं मान रहे हैं।

नदी तट से जुड़े क्षेत्रों में लोगों को अभी भी सतर्क रहने की जरूरत महसूस हो रही है। प्रशासनिक स्तर पर भी जलस्तर की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। गंगा और यमुना के साथ टोंस नदी के जलस्तर में होने वाले बदलाव का असर तटीय इलाकों पर पड़ रहा है। पानी घटने के बावजूद बाढ़ का संकट पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। राजापुर, मेजा और करछना सहित प्रभावित क्षेत्रों में लोग अब सामान्य जनजीवन की ओर लौटने की कोशिश कर रहे हैं। कई दिनों तक बाढ़ का पानी रहने के बाद रास्तों और आसपास के क्षेत्रों में भी परेशानी रही।

◆ **इसके** अलावा तटीय क्षेत्रों में प्रशासन की ओर से लोगों को जलस्तर में होने वाले बदलाव की जानकारी दी जा रही है। ग्रामीणों से निचले इलाकों में अनावश्यक आवाजाही से बचने और नदी किनारे सतर्क रहने की अपील की गई है। अधिकारियों का कहना है कि जलस्तर पर लगातार निगरानी रखी जा रही है, ताकि जरूरत पड़ने पर समय रहते आवश्यक कदम उठाए जा सकें।

मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना से सोनम की बदली राह, यूपीपीसीएस में बनीं एसडीएम

एजेंसी, लखनऊ। प्रतिभा, मेहनत और सही मार्गदर्शन के दम पर अयोध्या की सोनम यादव ने यूपीपीसीएस-2024 में उप जिलाधिकारी (एसडीएम) का पद हासिल कर सफलता की नई कहानी लिखी है। आर्थिक चुनौतियों के बावजूद सोनम ने अपने लक्ष्य से समझौता नहीं किया। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के मार्गदर्शन ने उनकी तैयारी को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

उनकी सफलता अब ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों के लिए प्रेरणा बन रही है। सोनम की उपलब्धि इस बात का उदाहरण है कि संसाधनों की कमी प्रतिभा और मेहनत के रास्ते में स्थायी बाधा नहीं बन सकती। उन्होंने लगन और निरंतर प्रयास के साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की और यूपीपीसीएस-2024 में सफलता हासिल की। एसडीएम पद मिलने के बाद उनके परिवार और क्षेत्र में खुशी का माहौल है।

वर्तमान में सोनम लखनऊ स्थित डॉ. राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। यहां वह प्रशासनिक प्रक्रियाओं, कानून-व्यवस्था और जनसेवा से जुड़े व्यावहारिक पहलुओं की जानकारी हासिल कर रही हैं। उनकी इस उपलब्धि से क्षेत्र के युवाओं में भी उत्साह बढ़ा है और बेटियों को उच्च शिक्षा तथा प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी के लिए नई प्रेरणा मिल रही है।

बीईओ के 238 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ, जल्द शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया

एजेंसी, प्रयागराज। बेसिक शिक्षा विभाग में खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) के 238 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। बेसिक शिक्षा निदेशालय ने इन पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) को अधियाचन भेज दिया है। अब आयोग की ओर से जल्द ही भर्ती का विज्ञापन जारी कर आवेदन मांगे जाने की उम्मीद है। इसके बाद चयन प्रक्रिया शुरू होगी। बीईओ भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों में लंबे समय से अर्हता संबंधी स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार था। बेसिक शिक्षा विभाग ने अब इस संबंध में स्थिति स्पष्ट कर दी है। पदों पर आवेदन के लिए बीएड की योग्यता मान्य होगी। इसके समकक्ष अन्य पाठ्यक्रम करने वाले अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। बेसिक शिक्षा निदेशालय की ओर से नई रिक्तियों का सत्यापन पूरा कर लिया गया है। इसके साथ ही आरक्षण व्यवस्था से संबंधित आवश्यक प्रक्रिया भी पूरी की जा चुकी है। विभाग की ओर से 238 पदों का अधियाचन आयोग को भेजे जाने के बाद भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद बढ़ गई है। आयोग की ओर से भर्ती का विज्ञापन जारी होने के बाद अभ्यर्थियों को आवेदन की तिथियों, शुल्क, आयु सीमा और अन्य आवश्यक शर्तों की जानकारी मिलेगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे भर्ती संबंधी आधिकारिक सूचना जारी होने के बाद पात्रता और आवेदन की सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ें। बीईओ के पदों पर भर्ती होने से बेसिक शिक्षा विभाग में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

बीमा राशि के नाम पर वसूली, किसानों ने दो सर्वेयरों को पहनाई जूतों की माला

◆ जूतों की माला पहनाकर सर्वेयरों को गांव में घुमाते किसान

एजेंसी, महोबा

फसल बीमा सर्वे के नाम पर किसानों से अवैध वसूली किए जाने के आरोप में महोबा में ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित किसानों ने दो सर्वेयरों को चूड़ी-पेटीकोट पहनाकर और माथे पर बिंदी लगाकर गांव में घुमाया। इतना ही नहीं, दोनों के गले में जूतों की माला भी डाली गई। घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामला चर्चा में है।

ग्रामीणों का आरोप है कि दोनों सर्वेयर फसल बीमा की राशि दिलाने के नाम पर किसानों से एक से दो हजार रुपये तक की मांग कर रहे थे। किसानों का कहना है कि सर्वे के दौरान उनसे पैसे लिए जा रहे थे, जिससे उनमें काफी नाराजगी थी। इसी के बाद ग्रामीणों ने दोनों सर्वेयरों को पकड़कर उनका विरोध किया और गांव में जुलूस के रूप में घुमाया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों सर्वेयरों को हिरासत में ले लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं, कृषि विभाग ने भी प्रकरण को गंभीरता से लिया है।

उपनिदेशक कृषि रामसजीवन ने बताया कि पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। किसानों द्वारा लगाए गए अवैध वसूली के आरोपों की भी पड़ताल की जा रही है। उन्होंने कहा कि जांच में आरोप सही पाए जाने पर संबंधित सर्वेयरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। विभाग की जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि किसानों से वसूली की गई थी या नहीं। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है और मामले में आगे की कार्रवाई जांच के निष्कर्ष के आधार पर की जाएगी।

अवसरवाद | मायावती ने सपा की पीडीए नीति पर सवाल उठाते हुए उसे जातिवादी और अवसरवादी बताया

नीला कपड़ा पहनने से नहीं बदलेगी सपा की जातिवादी सोच : मायावती

एजेंसी, लखनऊ

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने नीले रंग को लेकर समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि नीला कपड़ा और गमछा पहनने या नीला मंच लगाने से गरीबों और उपेक्षित वर्गों के प्रति वर्षों से चली आ रही जातिवादी और पूंजीवादी सोच नहीं बदल सकती। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग दिल से अंबेडकरवादी होने का दावा नहीं कर सकते।

मायावती ने कहा कि बहुजन समाज के वास्तविक हित और कल्याण के लिए पहले उन्हें अपनी सोच साफ करनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री ने सपा की पीडीए नीति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि इन वर्गों के मामले में सपा और कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर रहा है। मायावती ने कहा कि बहुजन समाज की सच्ची हितैषी और अंबेडकरवादी पार्टी केवल बसपा है। बसपा से निकाले गए नेताओं पर भी मायावती ने निशाना साधा।

उन्होंने कहा कि अनुशासनहीनता समेत विभिन्न कारणों से पार्टी से निकाले गए कई लोग बाद में दूसरी पार्टियों में चले गए। उनके अनुसार ऐसे लोग अवसरवादी और स्वार्थी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग दूसरी पार्टियों के समर्थन से छोटे दल और संगठन भी बना लेते हैं, लेकिन इससे बहुजन समाज का सामूहिक हित पूरा नहीं हो सकता। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मायावती ने उसे डूबता हुआ जहाज बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में शामिल होकर कोई अपने राजनीतिक भविष्य को अंधकार में क्यों डालेगा। उन्होंने बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के कांग्रेस से दूरी बनाए रखने संबंधी पुराने रुख का भी उल्लेख किया।

अशोक सिद्धार्थ के राजनीतिक संन्यास को लेकर मायावती ने कहा कि बसपा द्वारा संन्यास लेने के लिए कहे जाने के बाद उन्होंने तत्काल घोषणा नहीं की थी। उनके अनुसार, इसे रोकने के लिए रातभर कई तरह के प्रयास किए गए, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद अगले दिन उन्हें संन्यास की घोषणा करनी पड़ी। मायावती ने कहा कि सही समय आने पर इस मामले में पार्टी कार्यकर्ताओं को और जानकारी दी जाएगी। मायावती ने कहा कि बसपा से निकले नेताओं का दूसरी पार्टियों में जाना अवसरवाद है।

मायावती ने साधा निशाना

मायावती ने कहा कि बसपा से निकले नेताओं का दूसरी पार्टियों में जाना अवसरवाद है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे नेता अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए दल बदलते हैं और कई बार दूसरी पार्टियों के समर्थन से छोटे संगठन भी खड़े कर लेते हैं। मायावती ने कहा कि इससे बहुजन समाज का सामूहिक हित पूरा नहीं हो सकता। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने पार्टी को डूबता जहाज बताया और कहा कि उसमें शामिल होकर कोई अपना राजनीतिक भविष्य अंधकार में क्यों डालेगा। उन्होंने बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के कांग्रेस से दूरी रखने संबंधी पुराने रुख का भी उल्लेख किया। अशोक सिद्धार्थ के राजनीतिक संन्यास पर मायावती ने कहा कि उन्हें रोकने के लिए रातभर प्रयास किए गए, लेकिन सफलता नहीं मिली।

सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण मामले में हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

एजेंसी, प्रयागराज

सहारनपुर कलेक्ट्रेट स्थित मस्जिद के ध्वस्तीकरण मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने मामले में हर्जाना वसूली के आदेश पर भी रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकलपीठ ने यह आदेश मोहम्मद तनवीर की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी।

याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले से जुड़े सरकारी पक्ष को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट के आदेश के बाद फिलहाल संबंधित पक्ष से हर्जाना वसूलने की कार्रवाई पर रोक रहेगी। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से ध्वस्तीकरण और उसके बाद जारी किए गए हर्जाना वसूली संबंधी आदेश को चुनौती दी गई है। सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद के ध्वस्तीकरण को लेकर मामला हाई कोर्ट पहुंचा है। याचिका में संबंधित कार्रवाई और हर्जाना वसूली के आदेश पर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ता की दलीलों और उपलब्ध तथ्यों पर सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।

हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद अब सरकार को अगली सुनवाई से पहले अपना पक्ष अदालत के समक्ष रखना होगा। इसके बाद मामले में आगे की सुनवाई और आदेश की दिशा तय होगी। फिलहाल हर्जाना वसूली पर रोक लगने से याचिकाकर्ता को राहत मिली है। मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। अदालत के अगले आदेश पर सभी पक्षों की निगाहें टिकी हैं। इसके बाद सरकार का जवाब और याचिकाकर्ता की दलीलें सुनने के बाद अदालत मामले में आगे की कार्रवाई तय करेगी।

यमुनानगर में सिंचाई के गड्ढे में गिरा एक वर्षीय बच्चा, डूबने से मौत

भारतेन्दु संवाददाता, यमुनानगर

यमुनानगर गांव अराइयांवाला में सिंचाई के लिए बनाए गए पानी से भरे गड्ढे में डूबने से एक वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। हादसा वीरवार को हुआ। मृतक की पहचान सिद्धू के रूप में हुई है, जो तीन भाई-बहनों में सबसे छोटा था। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। जानकारी के अनुसार, मूलरूप से उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले के गांव धोरावाला निवासी शिव बालक पिछले करीब 10 वर्षों से अराइयांवाला गांव में रह रहा है।

वीरवार को वह अपनी पत्नी महिमा के साथ गांव में स्थित एक नर्सरी में काम कर रहा था। इसी दौरान उनका एक वर्षीय बेटा सिद्धू खेलते-खेलते नर्सरी के पास सिंचाई के लिए बनाए गए पानी से भरे गड्ढे में गिर गया। गड्ढा करीब डेढ़ फीट गहरा था। बच्चे के गड्ढे में गिरने का पता चलते ही पिता शिव बालक ने उसे तुरंत बाहर निकाला, लेकिन तब तक बच्चा बेहोश हो चुका था। परिजन उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद बच्चे को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। बताया गया कि हादसे के समय माता-पिता पास ही नर्सरी में काम कर रहे थे। अचानक हुए इस हादसे से गांव में भी शोक का माहौल है।

अराइयांवाला गांव में सिंचाई के लिए बनाए गए पानी से भरे गड्ढे में डूबने से एक वर्षीय बच्चे सिद्धू की मौत हो गई। हादसे के समय उसके माता-पिता पास की नर्सरी में काम कर रहे थे। खेलते हुए बच्चा करीब डेढ़ फीट गहरे गड्ढे में गिर गया। पिता ने उसे तुरंत बाहर निकाला, लेकिन वह बेहोश हो चुका था। परिजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

दुकान में घुसकर युवक पर रॉड से हमला, नौ वार में उतारा मौत के घाट

भारतेन्दु संवाददाता, करनाल। घरौंडा में शुक्रवार सुबह एक युवक की लोहे की रॉड से हमला कर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान तेजबीर सिंह के रूप में हुई है। वारदात उस समय हुई, जब तेजबीर एक दुकान पर सफाई कर रहा था। इसी दौरान आरोपित उत्तम कुमार हाथ में लोहे की रॉड लेकर दुकान में घुसा और तेजबीर पर हमला कर दिया। आरोपित ने युवक के सिर पर लगातार नौ वार किए। हमले में तेजबीर गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर ही गिर गया। कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। अचानक हुई इस वारदात से आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वारदात के बाद आरोपित मौके से भागने की कोशिश करने लगा। दुकान के बाहर मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद लोगों ने आरोपित की पिटाई कर दी और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी जुटाई।

पुलिस ने आरोपित को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। हत्या के पीछे क्या कारण रहा, इसका अभी स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। पुलिस आरोपित से पूछताछ कर वारदात के कारणों का पता लगाने में जुटी है। सीसीटीवी फुटेज में पूरी घटना रिकॉर्ड हुई है, जिसके आधार पर पुलिस वारदात की परिस्थितियों की जांच कर रही है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद हत्या से जुड़े अन्य तथ्यों का खुलासा किया जाएगा। पुलिस के अनुसार आरोपित से पूछताछ के आधार पर हत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी को जांच में शामिल किया है। वहीं, आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। शव का पोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

मेफील्ड गार्डन के 100 मकानों पर कार्रवाई की तैयारी, अवैध निर्माण पर चलेगा बुलडोजर

सर्वे में पीजी, गेस्ट हाउस और शोरूम समेत कई तरह की व्यावसायिक गतिविधियां आईं सामने

भारतेन्दु संवाददाता, गुरुग्राम

मेफील्ड गार्डन कॉलोनी में स्वीकृत नक्शे और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के नियमों का उल्लंघन कर किए गए निर्माण और रिहायशी मकानों में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है।

विभागीय सर्वे में करीब 100 मकानों में नियमों के विपरीत निर्माण या उपयोग किए जाने की जानकारी सामने आई है। इन मकानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। जिला नगर योजनाकार इन्फोर्समेंट (डीटीपी) अमित मधोलिया के निर्देश पर गठित टीम ने मेफील्ड गार्डन कॉलोनी में मकानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई ऐसे मकान मिले, जिनमें स्वीकृत

आवासीय उपयोग के बजाय अलग-अलग तरह की व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही थीं।

विभाग की जांच में पीजी, गेस्ट हाउस और शोरूम जैसी गतिविधियां सामने आई हैं। विभाग की ओर से किए गए सर्वे में यह भी देखा गया कि मकानों में निर्माण स्वीकृत नक्शे और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट में निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप है या नहीं।

कई मामलों में स्वीकृत व्यवस्था के विपरीत निर्माण किए जाने की जानकारी मिली है। विभाग अब ऐसे निर्माण और व्यावसायिक उपयोग करने वाले मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। मेफील्ड गार्डन में रिहायशी मकानों का व्यावसायिक इस्तेमाल किए जाने को लेकर विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। अधिकारियों के अनुसार, कॉलोनी में नियमों के उल्लंघन की शिकायतों और सामने आए मामलों की जांच के बाद कार्रवाई की जा रही है। विभाग का उद्देश्य स्वीकृत नक्शे और तय उपयोग के अनुरूप ही संपत्तियों का इस्तेमाल सुनिश्चित करना है।

जांच के दौरान जिन मकानों में नियमों का उल्लंघन मिला है, उनके संबंध में विभागीय स्तर पर नोटिस जारी करने और आगे की कार्रवाई की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। नियमों का पालन नहीं करने वाले निर्माणों और गतिविधियों पर सीलिंग तथा तोड़फोड़ जैसी कार्रवाई की जा सकती है। विभाग की कार्रवाई की तैयारी से मेफील्ड गार्डन में ऐसे मकान मालिकों की चिंता बढ़ गई है, जिनकी संपत्तियों में आवासीय उपयोग के अलावा अन्य गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।

मानसून की बेरुखी से धान पर दोहरी मार, अगेती फसल बचाने में जुटे किसान

भारतेन्दु संवाददाता, बहादुरगढ़

इस बार मानसून की बेरुखी ने धान उत्पादक किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। समय पर रोपाई की गई अगेती धान की फसल को बचाने के लिए, किसान लगातार ट्यूबवेल चला रहे हैं। बारिश नहीं होने से खेतों में नमी बनाए रखना चुनौती बन गया है। इससे किसानों को सिंचाई पर डीजल और बिजली का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा है।

वहीं, पिछेती रोपाई वाली धान की फसल सूखे की चपेट में आ गई है। कई खेतों में फसल खराब होने के बाद किसानों ने उसकी जुताई कर दी है। कुछ किसान फसल को पशु चारे के लिए काटने को मजबूर हैं। इससे किसानों को उत्पादन लागत निकलने की चिंता सताने लगी है। बहादुरगढ़ क्षेत्र में इस बार करीब 20 हजार हेक्टेयर भूमि पर धान की फसल लगाई गई है। किसानों के मुताबिक, मानसून कमजोर रहने के कारण लंबे समय से पर्याप्त बारिश नहीं हुई है। सामान्य तौर पर बारिश से खेतों में नमी बनी रहती है और सिंचाई का खर्च कम होता है, लेकिन इस बार स्थिति इसके विपरीत है।

अगेती फसल को किसान किसी तरह बचाने में जुटे हैं, जबकि पिछेती फसल में नुकसान की स्थिति गंभीर होती जा रही है। किसानों का कहना है कि यदि जल्द बारिश नहीं हुई तो अगेती फसल पर भी संकट गहरा सकता है। बारिश न होने से अगेती धान बचाना भी किसानों के लिए लगातार चुनौती बनता जा रहा है।

अगरतला-फिरोजपुर और बीकानेर-हरिद्वार एक्सप्रेस का हांसी स्टेशन पर ठहराव मंजूर

भारतेन्दु संवाददाता, हांसी

हरियाणा के हांसी के रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर है। रेलवे ने हांसी रेलवे स्टेशन पर दो एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव को मंजूरी दी है। इनमें अगरतला-फिरोजपुर एक्सप्रेस और बीकानेर-हरिद्वार एक्सप्रेस शामिल हैं। दोनों ट्रेनों का हांसी स्टेशन पर ठहराव फिलहाल प्रायोगिक तौर पर किया जाएगा। इससे हांसी और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को इन ट्रेनों में सफर करने के लिए अब हिसार स्टेशन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

रेलवे के इस निर्णय से यात्रियों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। लंबे समय से हांसी स्टेशन पर प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव की मांग की जा रही थी। अब दो महत्वपूर्ण ट्रेनों के यहां रुकने से यात्रियों के लिए रेल यात्रा अधिक सुविधाजनक होगी। हांसी स्टेशन पर अगरतला-फिरोजपुर एक्सप्रेस के ठहराव से

यात्रियों को पंजाब और देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र की ओर जाने के लिए बेहतर रेल सुविधा मिलेगी।

वहीं बीकानेर-हरिद्वार एक्सप्रेस के ठहराव से राजस्थान और हरिद्वार की ओर यात्रा करने वाले यात्रियों को सुविधा होगी। अब तक इन ट्रेनों में सफर करने के लिए कई यात्रियों को हिसार जाकर ट्रेन पकड़नी पड़ती थी। इससे उन्हें अतिरिक्त समय और किराया खर्च करना पड़ता था। हांसी में ठहराव शुरू होने के बाद यह परेशानी कम होगी। दोनों ट्रेनों का हांसी स्टेशन पर ठहराव फिलहाल प्रायोगिक आधार पर किया जा रहा है।

इसके तहत रेलवे यात्रियों की संख्या और सुविधा के लिहाज से इस ठहराव का आकलन कर सकता है। यात्रियों को उम्मीद है कि प्रायोगिक अवधि के बाद भी इन ट्रेनों का ठहराव नियमित रूप से जारी रखा जाएगा। रेलवे के इस फैसले से स्थानीय यात्रियों में खुशी है। यात्रियों का कहना है कि हांसी में एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव से न केवल यात्रा आसान होगी, बल्कि स्टेशन से जुड़े आसपास के क्षेत्रों के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा।

सिरसा: नशा तस्कर की एक करोड़ 29 लाख की संपत्ति फ्रीज

भारतेन्दु संवाददाता, सिरसा। डबवाली पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आरोपी कुलवंत सिंह की करीब 1.29 करोड़ रुपये की संपत्ति फ्रीज की है। इसमें जमीन, मकान, दुकान, चार वाहन और छह बैंक खाते शामिल हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ विभिन्न राज्यों में 13 मामले दर्ज हैं, जिनमें नौ नशा तस्करी से जुड़े हैं। पुलिस के अनुसार डबवाली और लंबी थानों में दर्ज मामलों में आरोपी से संबंधित बड़ी मात्रा में चूरापोस्त बरामद हुआ था। एक मामले में 300 किलोग्राम चूरापोस्त की बरामदगी भी दर्ज है। वर्ष 2010 में लंबी थाने में दर्ज मामले में 160 किलोग्राम चूरापोस्त बरामद होने पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए दस साल कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।

सोनीपत में दो करोड़ रंगदारी के बाद फायरिंग, मुठभेड़ में दो बदमाश काबू

भारतेन्दु संवाददाता, सोनीपत

सोनीपत के खरखौदा में दो करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने के बाद कार्यालय पर फायरिंग करने वाले दो युवकों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। हरसाना गांव की सीमा में राष्ट्रीय राजमार्ग-334बी पर हुई मुठभेड़ में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी। घायल आरोपियों की पहचान भटाना निवासी, हाल सोनीपत निवासी अंकित और लहराड़ा निवासी हर्ष के रूप में हुई है। दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खरखौदा में भर्ती कराया गया।

एसीपी राजपाल सिंह के अनुसार, खरखौदा वार्ड नंबर-1 निवासी दीपक के मोबाइल पर कॉल कर दो करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई थी। रकम नहीं देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। इसके करीब आधे घंटे बाद खांडा रोड स्थित दीपक के कार्यालय पर फायरिंग कर दी गई। कार्यालय में मौजूद अजय ने फोन कर दीपक को घटना की जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार, दोनों युवक बिना नंबर प्लेट की काले रंग की बजाज सिटी-100 बाइक पर सवार होकर आए थे। बाइक पर लाल पट्टी लगी थी। मौके से गेट और दीवार पर गोलियों के निशान तथा एक खाली खोल बरामद हुआ। एफएसएल टीम ने साक्ष्य जुटाए।

बहादुरगढ़ अस्पताल में एसएमओ से मारपीट रेडियोग्राफर पर पहले भी विवादों के आरोप

भारतेन्दु संवाददाता, बहादुरगढ़

सिविल अस्पताल के ट्रामा सेंटर में एसएमओ एवं कार्यवाहक पीएमओ के साथ मारपीट के मामले में आरोपित रेडियोग्राफर संदीप को लेकर अस्पताल में पहले भी विवादों की शिकायतें सामने आती रही हैं। डॉक्टरों और अस्पताल प्रबंधन के अनुसार, संदीप का व्यवहार पहले भी कई बार विवाद का कारण बन चुका है। चिकित्सकों से उलझने और काम में लापरवाही के आरोपों को लेकर उसके खिलाफ विभागीय अधिकारियों तक पहुंचती रही हैं।

अस्पताल सूत्रों के मुताबिक, रेडियोग्राफर संदीप पर पहले भी चिकित्सकों के साथ बहस करने और उनसे अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगते रहे हैं। कई मौकों पर उसके व्यवहार को लेकर अस्पताल के डॉक्टरों ने नाराजगी जताई थी। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश भी की गई थी। हालांकि, इसके बावजूद विवाद पूरी तरह समाप्त नहीं हुए।

इसी बीच ट्रामा सेंटर में एसएमओ के साथ मारपीट की घटना सामने आने से अस्पताल के चिकित्सकों में रोष और बढ़ गया।

घटना के विरोध में डॉक्टरों ने कार्य बहिष्कार किया, जिससे अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुईं। चिकित्सकों ने अस्पताल परिसर में कर्मचारियों की सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने की मांग उठाई। डॉक्टरों का कहना है कि अस्पताल में मरीजों के उपचार के दौरान कर्मचारियों के बीच समन्वय और अनुशासन बेहद जरूरी है। यदि किसी अधिकारी या चिकित्सक के साथ मारपीट जैसी घटना होती है तो इससे पूरे स्वास्थ्य तंत्र की कार्यप्रणाली प्रभावित होती है। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। मारपीट की घटना के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है।

अस्पताल प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी आरोपित कर्मचारी के पुराने व्यवहार तथा उसके खिलाफ आई शिकायतों को जांच के दायरे में शामिल किए जाने की संभावना है। फिलहाल घटना को लेकर अस्पताल में तनाव का माहौल बना हुआ है। घटना के बाद अस्पताल में सुरक्षा और अनुशासन को लेकर डॉक्टरों ने सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस जांच के साथ स्वास्थ्य विभाग भी कर्मचारी के पुराने विवादों और शिकायतों की समीक्षा कर सकता है।

बकरे की नहीं अहंकार की दें बलि करनाल में बोले अनिरुद्धाचार्य

भारतेन्दु संवाददाता, करनाल

तरावड़ी में चल रही श्रीमद्भागवत कथा के दौरान कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज ने श्रद्धालुओं के सवालों के जवाब देते हुए सनातन धर्म, बलि प्रथा, अंधविश्वास और पारिवारिक जीवन से जुड़े विषयों पर अपनी बात रखी। कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और उन्होंने बीमारी, प्रेतबाधा, वैवाहिक विवाद तथा संतान नहीं होने जैसी समस्याओं को लेकर सवाल किए।

हरियाणा के एक कथित संत द्वारा सनातन धर्म पर सवाल उठाए जाने से संबंधित प्रश्न पर अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि कुछ लोगों को फंडिंग दी जाती है, ताकि वे सनातनियों को ही सनातन के खिलाफ खड़ा कर सकें। उन्होंने ऐसे लोगों को सनातन का शत्रु बताया। उन्होंने श्रद्धालुओं से धर्म के प्रति जागरूक रहने और ऐसे मामलों में सोच-समझकर प्रतिक्रिया देने की बात कही। बलि प्रथा से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि बकरे की बलि देने के बजाय व्यक्ति को अपने अहंकार की बलि देनी चाहिए। उन्होंने धार्मिक आस्था के साथ अंधविश्वास से दूर रहने का संदेश दिया और कहा कि जीवन की परेशानियों में भगवान की शरण लेना चाहिए।

वैवाहिक विवाद को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने रिश्तों में प्रेम, विश्वास और आपसी संवाद को महत्वपूर्ण बताया। उनका कहना था कि पति-पत्नी को छोटी-छोटी बातों को लेकर विवाद बढ़ाने के बजाय बातचीत से समस्याओं का समाधान करना चाहिए। संतान नहीं होने को लेकर समाज के तानों से परेशान महिला के सवाल पर भी उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भक्ति को किसी सांसारिक इच्छा की पूर्ति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। श्रद्धालुओं को धैर्य रखने, सकारात्मक सोच अपनाने और भगवान की भक्ति में मन लगाने की सलाह दी।

मासूम शर्मा ने पाखंडवाद के खिलाफ छेड़ी मुहिम, बोले- एक सप्ताह में होगा सफाया

भारतेन्दु संवाददाता, सिरसा। हरियाणवी कलाकार एवं सिंगर मासूम शर्मा ने पाखंडवाद के खिलाफ मुहिम शुरू करने का आह्वान किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर युवाओं से ढोंगी और पाखंड फैलाने वाले लोगों के पोस्टर तथा होर्डिंग हटाने की अपील की। मासूम शर्मा ने कहा कि पाखंडवाद के खिलाफ सभी को मिलकर आवाज उठानी होगी और एक सप्ताह के भीतर इसके खिलाफ अभियान चलाने का प्रयास करना है। वीडियो में मासूम शर्मा ने कहा कि पाखंडियों की दुकान बंद करने का समय आ गया है। उन्होंने युवाओं से इस मुहिम में साथ आने की अपील करते हुए कहा कि जो लोग पाखंडवाद के खिलाफ खड़े होना चाहते हैं, वे अभियान से जुड़ें। उन्होंने युवाओं से ऐसे लोगों के पोस्टर और होर्डिंग हटाने की बात कही। मासूम शर्मा ने युवाओं से यह भी कहा कि अभियान के दौरान किए जाने वाले कार्यों के वीडियो बनाकर उन्हें टैग किया जाए। उनका कहना है कि युवाओं की एकजुटता से समाज में फैले पाखंड के खिलाफ जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। सिंगर ने अपने संदेश में युवाओं से किसी भी तरह के अंधविश्वास और ढोंग को बढ़ावा नहीं देने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक करने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी है। वीडियो जारी होने के बाद उनका यह संदेश सोशल मीडिया पर चर्चा में है। मासूम शर्मा की इस अपील का केंद्र पाखंडवाद के खिलाफ जागरूकता फैलाना और युवाओं को अभियान से जोड़ना है। उन्होंने लोगों से किसी व्यक्ति विशेष के बजाय पाखंड और ढोंग के खिलाफ आवाज उठाने का आह्वान किया।

न्यूज ब्रीफ

पौधों की देखभाल के साथ बच्चों की पढ़ाई, माली तरुण पढ़ा रहे केमिस्ट्री

भारतेन्दु संवाददाता, यमुनानगर। लेक्चरर के डेपुटेशन पर जाने के बाद तरुण इंद्रौरा ने विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होने दी। उन्होंने 11वीं और 12वीं के 36 विद्यार्थियों को केमिस्ट्री पढ़ाने की जिम्मेदारी संभाल ली। दो बार नेट परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके तरुण कठिन से कठिन टॉपिक को सरल तरीके से समझाते हैं। छात्र भी उनके पढ़ाने के तरीके की सराहना करते हैं। तरुण का कहना है कि विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित न हो, यही उनकी प्राथमिकता है। स्कूल में वह माली की अपनी जिम्मेदारी भी निभाते हैं और समय मिलने पर कक्षा में पहुंचकर बच्चों को पढ़ाते हैं।

फतेहाबाद में गैंगवार का खौफनाक वीडियो, युवक पर बरसाए लाठी-डंडे

भारतेन्दु संवाददाता, फतेहाबाद। हरियाणा के फतेहाबाद में गैंगवार की रंजिश में एक युवक की लाठी-डंडों से बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। बदमाशों ने युवक को कमरे में बंद कर घसीट-घसीटकर पीटा, जिससे उसके हाथ-पैर टूटने की बात सामने आई है। घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला गया। वीडियो में हरियाणवी सिंगर अमित सैनी रोहतकिया के गाने 'दीवार पर है फोटो तेरी और फोटो पर है माला' का इस्तेमाल किया गया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

पानीपत फायरिंग में नया मोड़, नाबालिग बोला- भाजपा नेता ने मारी गोली

भारतेन्दु संवाददाता, पानीपत। हरियाणा के पानीपत में फायरिंग के मामले में घायल नाबालिग ने भाजपा नेता लखन पांचाल पर गोली चलाने का आरोप लगाया है। नाबालिग के अनुसार गोली उसके कूल्हे में लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया गया कि वह मौके पर चल रहे झगड़े को देखने के लिए रुका था। नाबालिग का आरोप है कि मामले में समझौता कराने के लिए पुलिस के जरिए उसे सात लाख रुपये देने की पेशकश की गई। हालांकि, ये आरोप हैं और इनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। मामले को लेकर पुलिस की जांच जारी है। घायल नाबालिग का अस्पताल में उपचार चल रहा है और पुलिस घटना से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है।

पुलिस मुठभेड़ में घायल बदमाश को एसीपी ने सुनाई खरी-खोटी

भारतेन्दु संवाददाता, सोनीपत। हरियाणा के सोनीपत में प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय पर फायरिंग करने के बाद भाग रहे दो बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई, जिसमें दोनों बदमाशों के पैरों में गोली लगी। पुलिस ने दोनों को काबू कर उपचार के लिए सीएचसी खरखौदा में भर्ती कराया। घायल आरोपियों की पहचान भटाना निवासी और हाल सोनीपत निवासी अंकित तथा लहराड़ा निवासी हर्ष के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, दोनों ने फायरिंग से करीब एक घंटे पहले प्रॉपर्टी डीलर से दो करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी थी। उन्होंने खुद को दिल्ली के नंदू उर्फ कपिल सांगवान गैंग का गुर्गा बताया था।

पांच दिवसीय बैंकिंग समेत मांगों को लेकर गुरुग्राम में बैंककर्मियों की हड़ताल

भारतेन्दु संवाददाता, गुरुग्राम

पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार को देशव्यापी बैंक हड़ताल का असर गुरुग्राम में भी दिखाई दिया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल में शामिल हुए। इससे कई बैंक शाखाओं में कामकाज प्रभावित रहा और जरूरी बैंकिंग कार्य कराने पहुंचे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

बैंककर्मियों ने ओल्ड ज्यूडिशियल कॉम्प्लेक्स स्थित पंजाब नेशनल बैंक के सामने एकजुट होकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की मांग उठाई। प्रदर्शन के कारण बैंक के आसपास कुछ समय के लिए यातायात व्यवस्था भी प्रभावित रही। यूनाइटेड फोरम आफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर आयोजित इस हड़ताल में सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न बैंकों के कर्मचारी और

अधिकारी शामिल हुए। यूनियनों का कहना है कि पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था को लेकर पहले सहमति बन चुकी है, लेकिन इसके बावजूद इसे अब तक लागू नहीं किया गया है। कर्मचारियों की प्रमुख मांग सप्ताह में केवल पांच दिन बैंकिंग व्यवस्था लागू करने की है।

बैंक यूनियनों ने संशोधित परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआइ) योजना से जुड़े विवाद और अन्य लंबित मांगों को लेकर भी विरोध जताया। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से कई मांगों पर समाधान नहीं निकला है। इसी कारण देशभर में कर्मचारियों को हड़ताल का निर्णय लेना पड़ा। गुरुग्राम में प्रदर्शन के दौरान बैंककर्मियों ने सरकार से मांगों पर जल्द निर्णय लेने की अपील की।

कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि लंबित मांगों का समाधान नहीं किया गया तो आने वाले समय में आंदोलन को और तेज किया जा सकता है। हड़ताल के कारण बैंकिंग सेवाएं प्रभावित होने से ग्राहकों को नकद निकासी, जमा और अन्य जरूरी कार्यों के लिए परेशानी झेलनी पड़ी। हड़ताल के चलते बैंक शाखाओं में जरूरी लेनदेन और अन्य सेवाएं प्रभावित रहीं, जिससे ग्राहकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

नई सतह बिछने के बाद हाईवे पर वाहनों की आवाजाही होगी अधिक सुगम और तेज

दिल्ली-आगरा हाईवे की बढ़ेगी रफ्तार, 120 किमी की गति से दौड़ेंगे वाहन

भारतेन्दु संवाददाता, फरीदाबाद

दिल्ली-आगरा राजमार्ग पर सफर को और सुगम और तेज बनाने के लिए सड़क की कारपेटिंग का काम तेजी से चल रहा है। गदपुरी टोल बैरियर से सराय ख्वाजा टोल बैरियर तक राजमार्ग की सतह को बेहतर बनाने का काम अब मध्य चरण में पहुंच गया है। इससे वाहन चालकों को आने वाले दिनों में अधिक बेहतर सड़क मिलने की उम्मीद है। फिलहाल फरीदाबाद से दिल्ली की ओर जाने वाली सड़क पर कारपेटिंग का काम किया जा रहा है।

संबंधित एजेंसी की ओर से इस हिस्से का काम अगले तीन से चार दिन में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद दिल्ली से फरीदाबाद की ओर जाने वाली सड़क पर कारपेटिंग का काम शुरू किया जाएगा। दोनों दिशाओं में काम पूरा होने के बाद हाईवे की सड़क की सतह पहले की तुलना में अधिक बेहतर और सुगम हो जाएगी। राजमार्ग पर लंबे समय से वाहनों का दबाव बना रहता है। दिल्ली और फरीदाबाद के बीच बड़ी संख्या में रोजाना वाहन आते-जाते हैं। ऐसे में सड़क की सतह बेहतर होने से वाहन चालकों को आवागमन में सुविधा मिलने की उम्मीद

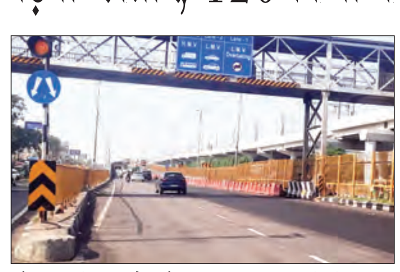

◆ गदपुरी से सराय ख्वाजा तक सड़क सुधार का काम जारी

है। कारपेटिंग के दौरान संबंधित हिस्से में यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए काम आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि सड़क निर्माण के साथ वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित न हो।

कारपेटिंग पूरी होने के बाद दिल्ली-आगरा राजमार्ग पर वाहनों के चलने के लिए बेहतर सतह उपलब्ध होगी। हाईवे को निर्धारित मानकों के अनुरूप तैयार किए जाने के बाद यहां वाहनों की गति बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। राजमार्ग पर वाहनों के लिए 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार का प्रावधान है। हालांकि वाहन चालकों को मौसम, यातायात और सड़क पर लागू नियमों के अनुसार ही वाहन चलाना होगा। गदपुरी से सराय ख्वाजा तक सड़क सुधार का काम पूरा होने के बाद दिल्ली की ओर जाने वाले वाहन चालकों को विशेष राहत मिलने की उम्मीद है। इसके बाद विपरीत दिशा में भी कारपेटिंग की जाएगी। अधिकारियों और निर्माण एजेंसी का प्रयास है कि निर्धारित समय में काम पूरा कर सड़क को यातायात के लिए बेहतर स्थिति में उपलब्ध कराया जाए।

कारपेटिंग के बाद राजमार्ग की सतह पर गड्ढों और खराब हिस्सों की समस्या कम होने की उम्मीद है। इससे वाहनों की आवाजाही अधिक सुचारु हो सकती है और यात्रियों को पहले की तुलना में आरामदायक सफर मिल सकता है। दिल्ली-आगरा मार्ग फरीदाबाद के लिए महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है और रोजाना बड़ी संख्या में लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में सड़क सुधार का काम पूरा होने से स्थानीय वाहन चालकों के साथ दिल्ली और आगरा की ओर आने-जाने वाले यात्रियों को भी लाभ मिलेगा। कारपेटिंग पूरी होने के बाद दोनों दिशाओं में वाहनों की आवाजाही सुगम होगी और यात्रियों को राहत मिलेगी।

आईजीआई एयरपोर्ट पर 48 घंटे में 30 किलो से ज्यादा गांजा जब्त

आईजीआई एयरपोर्ट पर कस्टम्स की कार्रवाई, दो मामलों में पांच गिरफ्तार

एजेंसी, नई दिल्ली

इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डे के टर्मिनल-3 पर कस्टम्स विभाग ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 48 घंटे में 30.3 किलोग्राम से अधिक हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद किया। कार्रवाई के दौरान दो अलग-अलग मामलों में पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। सभी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की गई है।

कस्टम्स विभाग के अनुसार, पहली कार्रवाई नौ सितंबर को खुफिया सूचना के आधार पर की गई। अधिकारियों को तस्करी के जरिए हाइड्रोपोनिक गांजा दिल्ली लाए जाने की सूचना मिली थी। इसके बाद टर्मिनल-3 पर यात्रियों और उनके सामान की निगरानी बढ़ा दी गई। इसी दौरान संदिग्ध गतिविधियां सामने आने पर अधिकारियों ने यात्रियों को रोककर पूछताछ शुरू की। अधिकारियों ने एअर इंडिया की उड़ान एआई-2333 से बैंकाक से दिल्ली पहुंचे दो यात्रियों के सामान पर विशेष नजर रखी। दोनों यात्रियों के बैगेज की निगरानी की जा रही थी। इसी बीच बैगेज बेल्ट के पास अधिकारियों ने देखा कि काठमांडू से पहुंचे दो अन्य यात्री बैंकाक से आए यात्रियों का सामान लेने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी गतिविधियां संदिग्ध लगने पर कस्टम्स अधिकारियों ने दोनों को निगरानी में ले लिया।

दोनों संदिग्ध यात्रियों को ग्रीन चैनल से बाहर निकलते समय पकड़ लिया गया। इसके बाद बैंकाक से दिल्ली पहुंचे दोनों यात्रियों को भी रोककर उनसे पूछताछ की गई। सामान की जांच के दौरान हाइड्रोपोनिक गांजे की खेप बरामद हुई।

बैंकाक-काठमांडू रूट से दिल्ली पहुंची हाइड्रोपोनिक गांजे की खेप

कस्टम्स अधिकारियों ने सामान की विस्तृत जांच की, जिसमें हाइड्रोपोनिक गांजे की खेप बरामद हुई। बरामद गांजे का कुल वजन 30.3 किलोग्राम से अधिक बताया गया है। मामले में सभी पांच आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारियों ने बरामद मादक पदार्थ को जब्त करने के साथ ही आरोपितों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। पूछताछ के दौरान आरोपितों से गांजे की तस्करी से जुड़े नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। कस्टम्स विभाग यह पता लगाने का प्रयास कर रहा है कि मादक पदार्थ की खेप कहां से लाई गई थी और इसे दिल्ली में किसे पहुंचाया जाना था। अधिकारियों के अनुसार, मामले में आगे की जांच जारी है। तस्करी से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका सामने आने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है।

पीडब्ल्यूडी सड़कों का तैयार होगा ऑनलाइन ब्यौरा

14 सितंबर से एक अक्टूबर तक सड़क की स्थिति और सुविधाओं का विवरण होगा ऑनलाइन दर्ज

एजेंसी, नई दिल्ली

लोक निर्माण विभाग के अधीन आने वाली दिल्ली की सड़कों का अब एक जगह पर पूरा और व्यवस्थित ब्यौरा तैयार किया जाएगा। इसके लिए विभाग ने सड़क संबंधी जानकारी को ऑनलाइन व्यवस्था में दर्ज करने और उसका सत्यापन करने की प्रक्रिया शुरू की है। सभी संबंधित अधिशासी अभियंताओं को अपनी-अपनी सड़कों का विवरण निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। यह प्रक्रिया 14 सितंबर से एक अक्टूबर तक चलेगी।

सड़क की पूरी जानकारी होगी दर्ज : इस प्रक्रिया के तहत प्रत्येक सड़क से जुड़ी विस्तृत जानकारी ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। इसमें सड़क कहां से शुरू होती है और कहां समाप्त होती है, उसकी वर्तमान स्थिति, श्रेणी, लेनों की संख्या, सड़क की सतह और चौड़ाई जैसी जानकारियां शामिल होंगी। इसके अलावा यह भी दर्ज किया जाएगा कि संबंधित सड़क का रखरखाव किस विभाग या एजेंसी के जिम्मे है। इससे विभाग के पास प्रत्येक सड़क का एकीकृत और अद्यतन रिकॉर्ड उपलब्ध हो सकेगा।

सुविधाओं का भी रखा जाएगा ब्योरा : सड़कों पर उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं की स्थिति को भी रिकॉर्ड में शामिल किया जाएगा। इसमें सड़क के बीच डिवाइडर है या नहीं, किनारे पार्किंग की व्यवस्था, वर्षा जल की निकासी, साइकिल चलाने के लिए रास्ता, जेब्रा क्रॉसिंग, गति कम करने वाले अवरोध और सड़क किनारे प्रकाश व्यवस्था जैसी जानकारियां दर्ज की जाएंगी। इससे किसी सड़क पर उपलब्ध सुविधाओं और जरूरी सुधारों की पहचान आसानी से की जा सकेगी।

सड़क सुधार की योजना बनाने में मिलेगी मदद

सड़कों का व्यवस्थित रिकॉर्ड तैयार होने से लोक निर्माण विभाग को सड़क सुधार और रखरखाव की योजनाएं तैयार करने में सुविधा होगी। किसी सड़क की लंबाई, चौड़ाई, सतह और वर्तमान स्थिति का विवरण एक ही जगह उपलब्ध होने से जरूरत के अनुसार कार्यों की प्राथमिकता तय की जा सकेगी। इसके अलावा जल निकासी, पार्किंग, प्रकाश व्यवस्था और पैदल यात्रियों से जुड़ी सुविधाओं में सुधार के लिए भी संबंधित सड़कों की पहचान की जा सकेगी।

अधिकारियों के लिए बनाया अलग प्रकोष्ठ : विभाग ने इस काम को पूरा कराने के लिए एमएसओ भवन में एक अलग प्रकोष्ठ बनाया है। संबंधित अधिकारी तय तारीख और समय पर यहां पहुंचकर अपनी सड़कों का विवरण दर्ज और सत्यापित कराएंगे। विभाग की ओर से अधिकारियों को समय सीमा का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि तय अवधि में सड़क संबंधी सभी आंकड़े एकत्र किए जा सकें।

एक जगह मिलेगा अद्यतन रिकॉर्ड : ऑनलाइन रिकॉर्ड तैयार होने के बाद विभाग के पास दिल्ली की सड़कों से संबंधित सूचनाओं का व्यवस्थित संग्रह उपलब्ध होगा। इससे अलग-अलग कार्यालयों से जानकारी जुटाने की आवश्यकता कम होगी और सड़क से जुड़े कार्यों की निगरानी तथा योजना निर्माण अधिक व्यवस्थित तरीके से किया जा सकेगा। जिन सड़कों का विवरण अभी विभिन्न स्तरों पर अलग-अलग उपलब्ध है, उन्हें भी इस व्यवस्था में शामिल किया जाएगा।

13 सितंबर को गुरुग्राम में 34 केंद्रों पर आयोजित होगी सीडीएस-एनडीए परीक्षा

एजेंसी, गुरुग्राम

◆ **परीक्षा को लेकर प्रशासन ने पूरी कीं सभी तैयारियां**

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की ओर से 13 सितंबर को आयोजित होने वाली संयुक्त रक्षा सेवा (सीडीएस) और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) परीक्षा को शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिले में परीक्षा के लिए 34 केंद्र बनाए गए हैं, जहां कुल 11,896 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा तीन पालियों में आयोजित की जाएगी।

परीक्षा की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को लघु सचिवालय में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमित कुमार की अध्यक्षता में केंद्र पर्यवेक्षकों और ड्यूटी मजिस्ट्रेट की बैठक हुई। बैठक में अधिकारियों को यूपीएससी की ओर से जारी नियमों और दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि परीक्षा से जुड़ी जिम्मेदारी बेहद संवेदनशील है, इसलिए किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

सुमित कुमार ने अधिकारियों से कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं समय रहते पूरी कर ली जाएं। परीक्षा से संबंधित किसी अधिकारी को किसी बिंदु पर शंका हो तो परीक्षा शुरू होने से पहले उसका समाधान कर लिया जाए, ताकि परीक्षा के दौरान किसी तरह की परेशानी उत्पन्न न हो। उन्होंने केंद्रों पर तैनात कर्मचारियों को उनकी जिम्मेदारियों की स्पष्ट जानकारी देने पर भी जोर दिया।

13 सितंबर को गुरुग्राम में सीडीएस और एनडीए की लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए 34 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। इन केंद्रों पर 11,896 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा तीन पालियों में होगी। सीडीएस परीक्षा तीन चरणों में, जबकि एनडीए परीक्षा दो चरणों में आयोजित की जाएगी।

रेवाड़ी में डेरी संचालक की हत्या का खुलासा, दोस्त की पत्नी से थे संबंध

◆ **दोस्त की पत्नी से संबंध बने हत्या की वजह, भतीजे संग मिलकर दोस्त ने उतारा मौत के घाट**

एजेंसी, नई दिल्ली। रेवाड़ी के गांव कमालपुर में डेरी संचालक की हत्या के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक के अपने बचपन के दोस्त प्रवीण उर्फ पपला की पत्नी के साथ पिछले करीब दो साल से अवैध संबंध थे। इसी रंजिश के चलते प्रवीण ने अपने भतीजे अमन के साथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों आरोपितों को जड़थल गांव से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार, डेरी संचालक और प्रवीण बचपन से दोस्त थे। दोनों के बीच लंबे समय से परिचय था, लेकिन मृतक के प्रवीण की पत्नी के साथ संबंध होने की जानकारी सामने आने के बाद दोनों के बीच तनाव बढ़ गया। प्रवीण इस बात को लेकर काफी नाराज था और इसी रंजिश में उसने हत्या की साजिश रची। वारदात को अंजाम देने के लिए प्रवीण ने अपने भतीजे अमन को भी साथ मिला लिया।

दोनों ने मिलकर डेरी संचालक की हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और संदिग्धों से पूछताछ के साथ उनके संभावित ठिकानों पर निगरानी रखी।जांच के दौरान पुलिस को आरोपितों के बारे में महत्वपूर्ण सुराग मिले। इसके आधार पर पुलिस टीम ने जड़थल गांव में दबिश देकर प्रवीण और अमन को गिरफ्तार कर लिया। दोनों से पूछताछ में हत्या के कारण और वारदात से जुड़े अन्य पहलुओं की जानकारी जुटाई जा रही है।

ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण के लिए दिल्ली सरकार देगी दो करोड़ तक अनुदान

एजेंसी, नई दिल्ली

◆ **पात्र संस्थाएं ऑनलाइन आवेदन कर संरक्षण परियोजनाओं के लिए ले सकेंगी वित्तीय सहायता**

◆ **परियोजना प्रस्ताव के साथ विस्तृत रिपोर्ट देना होगा जरूरी**

दिल्ली के ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण, जीर्णोद्धार और विकास को गति देने के लिए दिल्ली सरकार ने नई अनुदान योजना शुरू की है। 'दिल्ली मुख्यमंत्री विरासत नवोथान योजना' के तहत गैर-सरकारी संगठनों, न्यास, फाउंडेशन, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य पात्र संस्थाओं को स्मारकों से जुड़ी संरक्षण परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार ने इसके लिए सहायता अनुदान योजना की अधिसूचना जारी कर दी है।

योजना के तहत किसी परियोजना के लिए सामान्य तौर पर एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम दो करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जा सकेगी। सामान्य परियोजनाओं में विभाग और संबंधित संस्था के बीच खर्च का अनुपात 75:25 रहेगा। महत्वपूर्ण स्मारकों से संबंधित संरक्षण कार्यों में सरकार परियोजना लागत का 90 प्रतिशत और संबंधित संस्था 10 प्रतिशत खर्च वहन करेगी। वहीं सरकारी संस्थानों की पात्र परियोजनाओं का पूरा खर्च विभाग द्वारा उठाया जाएगा।

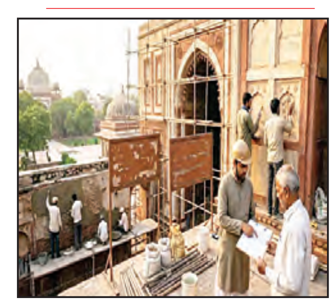

स्मारक की संरक्षण आवश्यकता और अनुमानित लागत को देखते हुए दो करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा बढ़ाने का भी प्रविधान किया गया है। इसके लिए सिफारिश समिति की अनुशंसा आवश्यक होगी। एक स्वैच्छिक संगठन एक वित्तीय वर्ष में केवल एक परियोजना के लिए आवेदन कर सकेगा।

वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र संस्थाओं को दिल्ली सरकार के पुरातत्व विभाग के निदेशक के नाम से जारी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। विश्वविद्यालयों तथा सरकारी अथवा स्वायत्त संस्थानों की ओर से रजिस्ट्रार या विभागाध्यक्ष आवेदन कर सकेंगे। निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त होने वाले या अधूरे आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन के साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसमें प्रस्तावित संरक्षण कार्यों का पूरा विवरण, वित्तीय सहायता की आवश्यकता तथा परियोजना में नियुक्त या नियुक्त किए जाने वाले विशेषज्ञों की योग्यता और अनुभव की जानकारी देनी होगी।

डूसू चुनाव 2026 : एबीवीपी, एनएसयूआई ने घोषित किए प्रत्याशी

एएसएपी से अश्मित कुमार पवार अध्यक्ष पद के उम्मीदवार, पंकज कुमार सचिव की दौड़ में

एजेंसी, नई दिल्ली

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डूसू) चुनाव 2026-27 को लेकर छात्र संगठनों की गतिविधियां तेज हो गई हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) और नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) ने चारों केंद्रीय पदों के लिए अपने अधिकृत प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है।

वहीं, आम आदमी पार्टी से संबंधित एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स (एएसएपी) और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) ने भी अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। एबीवीपी ने अध्यक्ष पद के लिए यश डबास को प्रत्याशी बनाया है। उपाध्यक्ष पद पर इशू मौर्य, सचिव पद पर रिया छाबड़ी और संयुक्त सचिव पद पर लक्ष्यराज सिंह को उम्मीदवार घोषित किया गया है।

डूसू चुनाव में एबीवीपी और एनएसयूआई ने अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित किए, मुकाबला रोचक हुआ।

संगठन की ओर से चारों पदों के लिए प्रत्याशियों के नाम सामने आने के बाद चुनावी गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद है। एनएसयूआई ने अध्यक्ष पद के लिए विजय शंकर मीणा को मैदान में उतारा है। उपाध्यक्ष पद पर वीर छत्रथ, सचिव पद पर नम्रता चौधरी और सह-सचिव पद पर गोपाल चौधरी को अधिकृत प्रत्याशी बनाया गया है। अध्यक्ष पद पर यश डबास और विजय शंकर मीणा के आमने-सामने होने से मुकाबला रोचक होने की संभावना है। आम आदमी पार्टी से संबंधित एएसएपी की ओर से अश्मित कुमार पवार को अध्यक्ष और पंकज कुमार को सचिव पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है।

डूसू चुनाव में बहुकोणीय मुकाबले के आसार

इसके अलावा चुनाव मैदान में अन्य छात्र संगठनों और निर्दलीय प्रत्याशियों की सक्रियता से मुकाबला और बहुकोणीय होने की संभावना है। चारों केंद्रीय पदों के लिए कुल 88 नामांकन पत्र प्रारंभिक जांच में वैध पाए गए हैं। हालांकि, नामांकन पत्रों की विस्तृत जांच और सत्यापन अभी बाकी है। अंतिम सूची जारी होने के बाद ही डूसू चुनाव में प्रत्याशियों की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी। चुनाव को लेकर छात्र संगठनों ने प्रचार और संपर्क अभियान तेज करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके बाद अंतिम सूची के आधार पर छात्र संगठनों की रणनीति और प्रचार अभियान और तेज होने की उम्मीद है।

ब्रिक्स सम्मेलन में चमका कनॉट प्लेस व्यापारियों ने पूछा- आम दिनों में क्यों नहीं?

एजेंसी, नई दिल्ली

राजधानी के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस (सीपी) का भव्य और हेरिटेज स्वरूप एक बार फिर चर्चा में है। हाल ही में ब्रिक्स सम्मेलन और इससे पहले जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। इस दौरान अवैध रेहड़ी-पटरी वालों को हटाए जाने के बाद कनॉट प्लेस के बरामदे और गलियारे काफी साफ-सुथरे नजर आए। पुराने दौर की तरह सीपी का खुला और व्यवस्थित स्वरूप देखकर व्यापारी और स्थानीय लोग भी प्रभावित हुए।

व्यापारियों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के दौरान जिस तरह कनॉट प्लेस को अतिक्रमण मुक्त रखा जाता है, वैसी ही व्यवस्था आम दिनों में भी होनी चाहिए। उनका सवाल है कि यदि कुछ दिनों के लिए रेहड़ी-पटरी और अवैध वेंडिंग हटाकर पूरे क्षेत्र को व्यवस्थित किया जा सकता है तो स्थायी रूप से ऐसा क्यों नहीं किया जाता। व्यापारियों के अनुसार अतिक्रमण के कारण पैदल चलने वालों को परेशानी होती है और बाजार की व्यवस्था भी प्रभावित होती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कनॉट प्लेस राजधानी के प्रमुख पर्यटन और खरीदारी स्थलों में शामिल है। यहां रोजाना बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। ऐसे में बरामदों और गलियारों में अतिक्रमण रहने से लोगों को आने-जाने में दिक्कत होती है। इसके अलावा भीड़ बढ़ने पर सुरक्षा और साफ-सफाई से जुड़ी समस्याएं भी सामने आती हैं।

व्यापारियों ने प्रशासन से मांग की है कि अंतरराष्ट्रीय आयोजनों तक सीमित कार्रवाई के बजाय अतिक्रमण के खिलाफ नियमित और प्रभावी व्यवस्था बनाई जाए। उनका कहना है कि कनॉट प्लेस की ऐतिहासिक पहचान और इसकी वास्तुकला को बनाए रखने के लिए बरामदों और सार्वजनिक स्थानों को खाली रखना जरूरी है। बताया जा रहा है कि अदालत के आदेशों के बावजूद क्षेत्र में अवैध वेंडिंग की समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हो पाई है। सम्मेलन समाप्त होने के बाद रेहड़ी-पटरी वालों की वापसी को लेकर व्यापारियों में चिंता है। उनका कहना है कि यदि फिर से वही स्थिति बनती है तो कुछ दिनों की सफाई और व्यवस्था का कोई स्थायी लाभ नहीं मिलेगा।

स्वतंत्र भारद्वाज की जमानत याचिका पर 14 सितंबर को होगी सुनवाई

एजेंसी, नई दिल्ली

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान सीजेपी कार्यकर्ता के पिता पर हमले के मामले में गिरफ्तार स्वतंत्र भारद्वाज ने नियमित जमानत के लिए पटियाला हाउस कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने मामले में नियमित जमानत दिए जाने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की है। याचिका पर 14 सितंबर को पटियाला हाउस स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई होगी।

जानकारी के अनुसार, जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान सीजेपी की एक कार्यकर्ता के पिता पर कथित तौर पर हमला हुआ था। इस मामले में पुलिस ने स्वतंत्र भारद्वाज को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद अब उन्होंने अदालत में नियमित जमानत के लिए आवेदन किया है। याचिका में अदालत से राहत देने का अनुरोध किया गया है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुन सकती है।

इसके बाद स्वतंत्र भारद्वाज की जमानत पर निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल 14 सितंबर को होने वाली सुनवाई पर सभी की नजर है। जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान हुई घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की थी। हमले से जुड़े तथ्यों और आरोपों की जांच के तहत कार्रवाई की गई। अब आरोपित की ओर से नियमित जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने के बाद मामला न्यायिक प्रक्रिया के अगले चरण में पहुंच गया है।

जमानत याचिका पर दोनों पक्ष रखेंगे अपनी दलीलें

इसके साथ ही अदालत में सुनवाई के दौरान मामले से जुड़े दस्तावेजों और पुलिस की ओर से प्रस्तुत तथ्यों पर भी चर्चा हो सकती है। बचाव पक्ष स्वतंत्र भारद्वाज की गिरफ्तारी और हिरासत से जुड़े बिंदुओं को सामने रखते हुए जमानत देने की मांग करेगा। वहीं, अभियोजन पक्ष मामले की गंभीरता और जांच की स्थिति का हवाला दे सकता है। अदालत दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर निर्णय लेगी। 14 सितंबर की सुनवाई के बाद यह स्पष्ट होगा कि स्वतंत्र भारद्वाज को नियमित जमानत मिलती है या उन्हें फिलहाल न्यायिक हिरासत में रहना होगा।

महापंचायत | गुर्जर-जाट महापंचायत से बढ़ी सियासी हलचल, जुबानी जंग पहुंची मंदबुद्धि तक

जयंत-अखिलेश की जुबानी जंग से गरमाई पश्चिमी यूपी की सियासत

एजेंसी, नई दिल्ली

गुर्जर-जाट महापंचायत के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में सपा और रालोद के बीच बढ़ती दूरी अब केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रह गई है। दोनों दलों के बीच जुबानी जंग में जातीय समीकरण भी प्रमुख मुद्दा बन गए हैं। चवन्नी और दो कौड़ी जैसे तंज के बाद विवाद गुर्जर-जाट समीकरण तक पहुंच गया है।

इसके साथ ही पाल-बघेल समाज को लेकर भी दोनों दल अपनी-अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश में जुटे हैं। पश्चिमी यूपी में जाट और मुस्लिम मतदाताओं के बीच रालोद की पुरानी पकड़ रही है। सपा के साथ गठबंधन के दौरान दोनों दलों ने इस समीकरण को चुनावी ताकत में बदलने की कोशिश की थी।

हालांकि, जयंत चौधरी के भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए के साथ जाने के बाद राजनीतिक परिस्थितियां बदल गईं। अब सपा पश्चिमी यूपी में नए सामाजिक समीकरण को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है।

सपा की कोशिश मुस्लिम, गुर्जर, पाल और बघेल मतदाताओं को साथ जोड़ने की बताई जा रही है। इसी बीच गुर्जर-जाट महापंचायत और उससे जुड़े राजनीतिक बयानों ने माहौल को और गर्म कर दिया है। रालोद भी अपने परंपरागत जाट आधार को मजबूत करने के साथ पश्चिमी यूपी में प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में दोनों दलों की राजनीतिक गतिविधियों का असर आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी पड़ सकता है। जुबानी जंग में मंदबुद्धि जैसे शब्दों के इस्तेमाल ने विवाद को और तीखा कर दिया है। सपा और रालोद के नेताओं के बयानों पर दोनों पक्षों के समर्थक भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

पश्चिमी यूपी में जातीय समीकरणों पर सपा-रालोद आमने-सामने

आने वाले दिनों में दोनों दलों की रणनीति का असर पश्चिमी यूपी की चुनावी राजनीति पर साफ दिखाई दे सकता है। सपा जहां नए सामाजिक गठजोड़ के जरिए अपना आधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है, वहीं रालोद जाट मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ बनाए रखने पर जोर दे रहा है। ऐसे में गुर्जर, पाल और बघेल समाज को साधने की कोशिशें भी तेज हो सकती हैं। राजनीतिक जानकारों की नजर अब इस बात पर है कि दोनों दलों के बीच बढ़ती तल्खी किस तरह चुनावी समीकरणों को प्रभावित करती है। भाजपा भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए है और विपक्षी दलों के बीच बढ़ती दूरी को अपने पक्ष में इस्तेमाल करने की रणनीति बना सकती है। आगामी चुनाव में पश्चिमी यूपी के इन जातीय समीकरणों की भूमिका अहम मानी जा रही है। दोनों दल अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में संगठन मजबूत करने के साथ नए मतदाताओं को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इससे मुकाबला और दिलचस्प होने की संभावना है।

न्यूज ब्रीफ

11 अक्तूबर से होंगे धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। दुर्गा पूजा समिति बिलासपुर की आगामी रजत जयंती दुर्गा पूजा समारोह को लेकर धौलरा मंदिर में समिति की संस्थापिका श्रीमती मल्लिका नड्डा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में 11 से 20 अक्तूबर 2026 तक होने वाले समारोह को भव्य एवं श्रद्धापूर्ण ढंग से मनाने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। समिति ने निर्णय लिया कि रजत जयंती के अवसर पर धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों का विशेष आयोजन किया जाएगा। इसमें भव्य कलश यात्रा, डांडिया नृत्य, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, भंडारा और विभिन्न धार्मिक आयोजन प्रमुख रहेंगे। कलश यात्रा लक्ष्मी मंदिर से शुरू होकर धौलरा मंदिर तक जाएगी। इस दौरान माता श्री नयना देवी और ज्वालाजी माता की पवित्र ज्योतियां भी विशेष रूप से धौलरा मंदिर लाई जाएंगी। समिति के मीडिया प्रभारी स्वदेश ठाकुर ने कहा कि समिति पिछले 25 वर्षों से मां दुर्गा की पूजा एवं समारोह का आयोजन करती आ रही है। इस वर्ष का आयोजन सभी के सहयोग से यादगार बनाया जाएगा। उन्होंने बिलासपुरवासियों से परिवार सहित समारोह में भाग लेने का आग्रह किया।

14 कॉलेजों के खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

भारतेन्दु संवाददाता, बधानी। श्री साई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स बधानी कॉलेज में आईकेजीपीटीयू जालंधर के इंटर कॉलेज टेबल टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में करीब 14 कॉलेजों की टीमों ने हिस्सा लिया, जिनमें 10 पुरुष और चार महिला टीमों ने भाग लिया। कार्यक्रम में लेफ्टिनेंट कमांडर सुमित ओबेरॉय मुख्यातिथि रहे, जबकि श्री साई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के चेयरमैन एस.के. पुंज, एमडी तृप्ता पुंज, सीएमडी कंवर तुषार पुंज और रिया पुंज विशेष रूप से उपस्थित रहे। पुरुष वर्ग में डेविएट जालंधर, सीटी कॉलेज शाहपुर और सीजीसी लांड्रा ने क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। महिला वर्ग में डेविएट जालंधर, सीजीसी लांड्रा और आईकेजीपीटीयू जालंधर मुख्य परिसर ने पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया। विजेता खिलाड़ियों को पदक और प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डायरेक्टर रणजीत सिंह, डॉ. विपिन गुप्ता, डॉ. राजेश गुप्ता, डॉ. दिनेश महाजन, डीन छात्र कल्याण समिंदर तरवाल, डीन स्पोर्ट्स दीपक कुमार सहित स्टाफ व विद्यार्थी मौजूद रहे।

कुलदीप अध्यक्ष, डॉ. सौरव व डॉ. रजत बने उपाध्यक्ष

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। हिमाचल मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन बिलासपुर की नई जिला कार्यकारिणी का गठन क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर के ट्रॉमा सेंटर में सर्वसम्मति से किया गया। बैठक में जिलेभर से चिकित्सकों ने भाग लिया और चिकित्सा बिरादरी के सम्मान, अधिकारों तथा कल्याण के लिए एकजुट होकर कार्य करने का संकल्प लिया। डॉ. शशि दत्त, सीएमओ बिलासपुर को संरक्षक तथा डॉ. भूपिंदर को मुख्य सलाहकार चुना गया। डॉ. कुलदीप ठाकुर को जिला अध्यक्ष, डॉ. सौरव और डॉ. रजत को उपाध्यक्ष तथा डॉ. शुभम को महासचिव बनाया गया। डॉ. वीर कमल, डॉ. वैभव और डॉ. सोनालिका को संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई। डॉ. प्रशांत को कोषाध्यक्ष और डॉ. शिवांशु को प्रेस सचिव चुना गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉ. कुलदीप ठाकुर ने कहा कि एसोसिएशन चिकित्सकों के व्यावसायिक हितों की रक्षा के साथ प्रशासन से रचनात्मक संवाद स्थापित करेगी। उन्होंने जिले में बेहतर समन्वय के साथ स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई।

युवाओं को मानवतावादी सेवा से जोड़ने पर जोर

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, जिला शाखा बिलासपुर की जिला स्तरीय जूनियर रेड क्रॉस एवं यूथ रेड क्रॉस समिति की बैठक बचत भवन में आयोजित हुई। अध्यक्षता अतिरिक्त उपायुक्त एवं रेड क्रॉस सोसाइटी की उपाध्यक्ष रूपिंदर कौर ने की। बैठक में विभिन्न विभागों, शिक्षण संस्थानों, रेड क्रॉस सदस्यों एवं स्वयंसेवकों समेत करीब 35 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। नेपाल में हालिया बाढ़ में जान गंवाने वालों की आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। रूपिंदर कौर ने कहा कि रेड क्रॉस इकाइयों को केवल सदस्यता तक सीमित न रखते हुए युवाओं को सामुदायिक सेवा, मानवीय कार्यों और नेतृत्व के अवसरों से जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने प्राथमिक उपचार, आपदा प्रबंधन, रक्तदान, स्वच्छता, पौधरोपण, साइबर सुरक्षा, नशा मुक्ति और जरूरतमंदों की सहायता जैसी गतिविधियों को नियमित कार्यक्रमों में शामिल करने पर जोर दिया।

बैडमिंटन में जिला स्तर पर लहराया परचम

भारतेन्दु संवाददाता, अर्की। राजकीय उच्च विद्यालय बातल की छात्राओं ने सुबाथू में आयोजित 19 वर्ष से कम आयु वर्ग की छात्राओं की जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में बैडमिंटन में द्वितीय स्थान हासिल कर विद्यालय और अर्की क्षेत्र का नाम रोशन किया है। प्रतियोगिता में कनिष्का कौशल, वंशिका शर्मा, अंशिका और दिव्यांशी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी खेल प्रतिभा का लोहा मनवाया। शारीरिक शिक्षक अखिलेश शर्मा ने बताया कि छात्राओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर अब वे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिला सोलन का प्रतिनिधित्व करेंगी। विद्यालय के मुख्याध्यापक तेजेंद्र शर्मा, एसएमसी प्रधान विकास शर्मा तथा समस्त स्टाफ ने छात्राओं को इस शानदार उपलब्धि पर हार्दिक बधाई दी और राज्य स्तर पर बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दीं।

पनोह में अंडर-14 गर्ल्स जोनल टूर्नामेंट का आगाज

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पनोह में अंडर-14 गर्ल्स जोनल स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के अतिरिक्त महाधिवक्ता वरुण चंदेल ने ध्वजारोहण कर किया। खास बात यह रही कि वरुण चंदेल ने इसी विद्यालय से पहली से आठवीं कक्षा तक शिक्षा ग्रहण की थी। अपने पुराने स्कूल में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचने पर विद्यालय परिवार और क्षेत्रवासियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रतियोगिता में 25 विद्यालयों की 191 छात्राएं भाग ले रही हैं। छात्राओं के बीच कबड्डी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, खो-खो और शतरंज के मुकाबले होंगे। प्रतिभागियों ने मार्च पास्ट कर मुख्य अतिथि को सलामी दी और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। वरुण चंदेल ने कहा कि हार-जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन अनुशासन, खेल भावना और निरंतर मेहनत ही सफलता की असली कुंजी है। उन्होंने छात्राओं को खेलों में बढ़-चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया।

11 केवी लाइनों की मरम्मत के चलते अर्की क्षेत्र में छह दिन प्रभावित रहेगी बिजली आपूर्ति

भारतेन्दु संवाददाता, अर्की। बिजली उपमंडल अर्की के तहत 11 केवी लाइनों की आवश्यक मरम्मत तथा लाइनों के आसपास पेड़ों की टहनियों और झाड़ियों की कटिंग के चलते 14 से 19 सितंबर तक विभिन्न क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। विभाग ने इसके लिए तिथिवार कार्यक्रम जारी किया है। 14 सितंबर को ड्रमैहर फीडर के तहत सानन, सेरी, सरीण, बखालग, शिवघाटी सहित आसपास के क्षेत्रों में बिजली बंद रहेगी। 15 सितंबर को रेहटा फीडर के धनागुघाट, ध्यानपुर, पिपलूघाट व आसपास के क्षेत्रों में आपूर्ति प्रभावित होगी। 16 सितंबर को ड्रमैहर फीडर के बनोह, गंभरपुल, नालत, ज्वाला और देओरा क्षेत्रों में बिजली बाधित रहेगी। 17 सितंबर को रेहटा फीडर के चंदपुर, कुलावन, भलेड व भेल, 18 सितंबर को ड्रमैहर फीडर के पपलोटा, स्यारी, डुमैहर व आसपास तथा 19 सितंबर को रेहटा फीडर के बणिया देवी, खैरघाटी, दिड्डू, शेरपुर व बाहवां क्षेत्रों में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक आपूर्ति प्रभावित रहेगी। सहायक अभियंता नीरज कुमार कतना ने उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है।

पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था की मांग को लेकर प्रदेश में बैंक कर्मचारियों ने की हड़ताल

शिमला में 300 से अधिक बैंक कर्मचारियों-अधिकारियों ने किया धरना प्रदर्शन

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करने की मांग को लेकर शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश में बैंक कर्मचारी व अधिकारी हड़ताल पर रहे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) के आह्वान पर हुई हड़ताल का शिमला सहित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में असर देखने को मिला। शिमला में बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों ने डीसी ऑफिस चौक पर धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ रोष जताया।

यूएफबीयू हिमाचल के अनुसार शिमला में आयोजित धरने में 300 से अधिक बैंक कर्मचारी और अधिकारी शामिल हुए। विभिन्न बैंकों और बैंक कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी प्रदर्शन में हिस्सा लिया। यूनियन नेताओं ने कहा कि पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करने का समझौता होने के बावजूद इस पर अब तक निर्णय नहीं हुआ है। इससे बैंक कर्मचारियों में नाराजगी है। यूएफबीयू हिमाचल के राज्य संयोजक नरेंद्र शर्मा ने कहा कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन और बैंक यूनियनों के बीच मार्च 2024 में हुए 12वें द्विपक्षीय समझौते और नौवें संयुक्त नोट में पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करने पर सहमति बनी थी। इसके बाद प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया, लेकिन दो साल से अधिक समय बीतने के बाद भी इसे लागू नहीं किया गया है।

उन्होंने कहा कि बैंक कर्मचारी इसी मांग को लेकर लगातार सरकार से निर्णय लेने की मांग कर रहे हैं। यूनियन नेताओं ने कहा कि बैंकिंग सेवाओं का बड़ा हिस्सा अब डिजिटल माध्यमों से उपलब्ध है। एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और यूपीआई जैसी सुविधाएं ग्राहकों को लगातार मिल रही हैं। उनका कहना है कि पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू होने से ग्राहकों को मिलने वाली बैंकिंग सुविधाओं पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा।

मांगें नहीं मानी तो 28 से 30 सितंबर तक तीन दिन बैंक हड़ताल की चेतावनी

शिमला में हुए धरने में यूएफबीयू राज्य संयोजक नरेंद्र शर्मा के अलावा एआईबीओसी के राज्य अध्यक्ष आशुतोष शर्मा, राज्य सचिव खेम राज वर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा, आयोजन सचिव सिद्धार्थ जारेट, एसबीआई ऑफिसर्स एसोसिएशन के राज्य अध्यक्ष दीपक कुमार, एनसीबीई के राज्य सचिव अंकुश मेहता, सीबीओए के राज्य सचिव मनीष मच्छान और एआईबीईए के अध्यक्ष अमर चंद सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। एसबीआई ऑफिसर्स पेंशनर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि दीपक शर्मा और यू.एस. नेगी ने भी प्रदर्शन में हिस्सा लिया। यूनियन ने चेतावनी दी है कि लंबित मांगों पर समाधान नहीं हुआ तो 28, 29 और 30 सितंबर को तीन दिन फिर बैंक हड़ताल की जाएगी। इसके बाद भी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो 26 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने का आह्वान किया गया है। यूनियन नेताओं ने सरकार और बैंक प्रबंधन से बातचीत के जरिए मुद्दों का समाधान करने की मांग की है।

विद्या गौरव पुरस्कार से 38 मेधावी छात्र-छात्राएं सम्मानित

भारतेन्दु संवाददाता, बद्दी। श्रीमती विद्या देवी मानव सेवा ट्रस्ट सूरजपुर की ओर से न्यू मॉडल स्कूल बरोटीवाला में विद्या गौरव पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में एसडीएम बद्दी संजीव धीमान ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। स्कूल प्रबंधन एवं ट्रस्ट पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती वंदना और दीप प्रज्वलन से हुआ।

इस दौरान विद्यार्थियों ने स्वागत गीत, नशे के खिलाफ भाषण, गिद्दा तथा देशभक्ति कविताओं की प्रस्तुतियां देकर सभी का मन मोह लिया। ट्रस्ट के ट्रस्टी चंद्रकांत शास्त्री ने ट्रस्ट की ओर से पिछले चार वर्षों से किए जा रहे सामाजिक कार्यों की जानकारी दी। समारोह में मनधाला, बरोटीवाला, कालूझीड़ा, कुड़ावाला सहित विभिन्न स्कूलों के करीब 38 मेधावी छात्र-छात्राओं को विद्या गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा शिक्षा, खेल, उद्योग और समाजसेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले प्रेम चंद शास्त्री, रामलाल मेहता, रणवीर राजपूत, जगदीश मेहता, राजीव मेहता, योगेंद्र ठाकुर, अमरनाथ ठाकुर, तरसेम चौधरी, किरण कौर, रमा चौधरी, सलिंदर पाल चौधरी और मनीष भड़ाना को भी सम्मानित किया गया।

मुख्यातिथि संजीव धीमान ने ट्रस्ट के सामाजिक प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि मेधावी विद्यार्थियों और समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित करना प्रेरणादायक पहल है। अंत में डॉ. श्रीकांत शर्मा ने सभी अतिथियों और सहयोगियों का आभार जताया।

स्वामी विवेकानंद सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता 4 अक्तूबर को, 6.22 लाख के नकद पुरस्कार

भारतेन्दु संवाददाता, धर्मशाला। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) जिला कांगड़ा की ओर से स्वामी विवेकानंद सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन 4 अक्तूबर को किया जाएगा। जिला संयोजक आयुष चौधरी ने बताया कि प्रतियोगिता में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी भाग ले सकेंगे। पंजीकरण 14 से 26 सितंबर तक होगा और शुल्क 30 रुपए रखा गया है। प्रतियोगिता में प्रदेशभर के विद्यार्थियों के लिए कुल 6 लाख 22 हजार 500 रुपए के नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रदेश स्तर पर प्रथम पुरस्कार 31 हजार, द्वितीय 21 हजार और तृतीय 15 हजार रुपए रहेगा। जिला स्तर पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार क्रमशः 10 हजार, 7 हजार और 5 हजार रुपए होंगे। प्रश्नपत्र में करंट अफेयर्स, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, गणित, हिमाचल प्रदेश और विद्यार्थी परिषद से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे।

हिमाचल सरकार के 65 करोड़ रुपए के लंबित बकाये से एम्स बिलासपुर समेत अन्य अस्पताल प्रभावित : अनुराग

भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमकेयर और आयुष्मान भारत योजनाओं के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार पर लंबित भुगतानों को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एम्स बिलासपुर की गवर्निंग बॉडी एवं इंस्टीट्यूशनल बॉडी की बैठकों में भाग लेते हुए करीब 65 करोड़ रुपए के बकाये का मुद्दा प्रमुखता से उठाया।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि लंबित भुगतान के कारण एम्स बिलासपुर सहित अन्य स्वास्थ्य संस्थानों पर वित्तीय दबाव पड़ रहा है। उनके अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा पात्र राशि जारी करने की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है और केंद्र की ओर से हिमाचल स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक फंड उपलब्ध करवाए गए हैं, लेकिन प्रदेश सरकार की ओर से इन निधियों का आगे वितरण नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े भुगतान लंबित रहना केवल वित्तीय या प्रशासनिक विषय नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर मरीजों पर पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना गरीब और जरूरतमंद लोगों को आर्थिक बाधा के बिना उपचार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से शुरू की थी। अनुराग ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण मरीजों और अस्पतालों को परेशानी उठानी पड़ रही है। उन्होंने सरकार से हिमकेयर और आयुष्मान भारत के तहत लंबित करीब 65 करोड़ रुपए का तत्काल भुगतान करने तथा मरीजों को निर्बाध उपचार सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि एम्स बिलासपुर हिमाचल सहित पड़ोसी क्षेत्रों के लोगों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है, इसलिए इसकी वित्तीय एवं परिचालन व्यवस्था प्रभावित नहीं होनी चाहिए।

लधपालवां टोल प्लाजा पर बैरियर तोड़कर भागे टिप्पर

◆ **बिलों की जांच को लेकर चालकों से कहासुनी, तेज रफ्तार में वाहन भगाने से मचा हड़कंप**

भारतेन्दु संवाददाता, पठानकोट। जिला पठानकोट में अवैध खनन और माइनिंग को लेकर तनाव के बीच लधपालवां टोल प्लाजा पर उस समय हंगामा हो गया, जब माइनिंग विभाग की टीम क्रशर मटेरियल लेकर जा रहे टिप्परों की जांच कर रही थी। बिलों की चेकिंग को लेकर वाहन चालकों और विभागीय अधिकारियों के बीच कहासुनी हो गई। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि कुछ टिप्पर चालक टोल प्लाजा का बूम बैरियर तोड़कर तेज रफ्तार में वाहन भगाकर ले गए।

मौके पर मौजूद पुलिस टीम ने वाहनों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन कई टिप्पर वहां से निकलने में सफल रहे। तेज रफ्तार वाहनों के कारण टोल प्लाजा पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर डीएसपी रूरल सुखजिंदर सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। माइनिंग विभाग की कार्रवाई से नाराज ट्रांसपोर्टरों संजय, नीरज और अनुज ने आरोप लगाया कि बड़ी फर्मों और क्रशर मालिकों के वाहनों को कथित तौर पर बिना रोक-टोक जाने दिया जाता है, जबकि छोटे ट्रांसपोर्टरों पर कार्रवाई की जाती है। उन्होंने नाका लगाकर बिना बिल के वाहन निकालने के बदले 500 से 1500 रुपये तक मांगने के आरोप भी लगाए। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। घटना के दौरान कई वाहनों पर नंबर प्लेट न होने का मामला भी सामने आया। स्थानीय लोगों ने सवाल उठाया कि ऐसे वाहन किसी दुर्घटना या आपराधिक घटना में शामिल हों तो उनकी पहचान करना मुश्किल होगा।

क्रशर मालिकों पर कार्रवाई की मांग

भारतीय किसान यूनियन (चढ़ूनी) के यूथ पंजाब अध्यक्ष इंदरपाल सिंह बैंस ने कहा कि मानसून और सरकारी नियमों के चलते पोर्टल बंद होने के बावजूद क्रशरों से बिना बिल माल कैसे भेजा जा रहा है। उन्होंने ड्राइवरों के बजाय अवैध खनन करवाने वाले क्रशर मालिकों पर भी कार्रवाई की मांग की। माइनिंग विभाग के अधिकारियों ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि टीम केवल वाहनों के बिलों की जांच कर रही थी। वैध बिल वाले वाहनों को जाने दिया गया, जबकि बिना बिल वाले वाहनों को रोका गया। डीएसपी सुखजिंदर सिंह ने चेतावनी दी कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

हमीरपुर को मिला उत्तर भारत का पहला स्वतंत्र एलाइड एंड हेल्थकेयर कॉलेज : डॉ. पुष्पेंद्र वर्मा

◆ **मुख्यमंत्री सुक्खू का जताया आभार, चार पाठ्यक्रमों में उपलब्ध होंग कुल 210 सीटें**

अनिल कुमार, भातेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉ. पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की दूरदर्शी सोच और स्वास्थ्य शिक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता से हमीरपुर को एक बड़ी उपलब्धि मिली है।

राष्ट्रीय संबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021 लागू होने के बाद हमीरपुर में उत्तर भारत का पहला पूर्णतः स्वतंत्र एलाइड एंड हेल्थकेयर कॉलेज स्थापित किया गया है। डॉ. वर्मा ने बताया कि इस कॉलेज में प्रारंभिक चरण में चार स्नातक पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। बैचलर ऑफ रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी की 60 सीटें, बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी 60 सीटें, बैचलर ऑफ एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी कृ 60 सीटें, बैचलर ऑफ डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी कृ 30 सीटें। इस प्रकार चारों पाठ्यक्रमों में कुल 210 विद्यार्थियों को प्रत्येक वर्ष प्रवेश का अवसर मिलेगा। आगामी वर्ष में कॉलेज में तीन से चार अन्य रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम भी जोड़े जाने की संभावना है। उन्होंने बताया कि यह कॉलेज पूर्णतः स्वतंत्र संस्थान के रूप में कार्य करेगा। इसके सुचारु संचालन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रधानाचार्य, सहायक प्राध्यापकों तथा ट्यूटर्स सहित फैकल्टी के 16 नए पद सृजित किए गए हैं। इसके अलावा इस कॉलेज में इंस्ट्रूमेंट खरीदने के लिए 7 करोड रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। डॉ. पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा कि एलाइड हेल्थकेयर क्षेत्र आधुनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ है। इस कॉलेज के खुलने से हिमाचल प्रदेश सहित उत्तर भारत के युवाओं को रेडियोलॉजी, मेडिकल लेबोरेटरी, एनेस्थीसिया, ऑपरेशन थिएटर और डायलिसिस जैसे क्षेत्रों में उच्चस्तरीय व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त होगी।

चीनी के भंडारण की संशोधित सीमा 2 हजार क्विंटल निर्धारित

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। जिला नियंत्रक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले बिलासपुर शीतल शर्मा ने बताया कि उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने चीनी के स्टॉक भंडारण की सीमा में संशोधन किया है। नए प्रावधान आगामी 15 सितंबर से प्रभावी होंगे। इस संबंध में जिले के सभी थोक व्यापारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब व्यापारी अधिकतम 2 हजार क्विंटल चीनी का स्टॉक ही भंडारित कर सकेंगे। इससे पहले यह सीमा 4 हजार क्विंटल थी। सभी डीलरों, व्यापारियों और थोक विक्रेताओं को फूड स्टॉक मॉनिटरिंग पोर्टल पर चीनी के स्टॉक की जानकारी नियमित रूप से अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं। जिन व्यापारियों ने पोर्टल पर पंजीकरण नहीं करवाया है, वे शीघ्र पंजीकरण करवाएं। जिला नियंत्रक ने कहा कि नए प्रावधानों का उद्देश्य बाजार में चीनी की उपलब्धता की निगरानी करना और निर्धारित सीमा से अधिक भंडारण पर रोक लगाना है।

'नॉर्मल रूटीन' के नाम पर संविधान और लोकतंत्र की मर्यादा न तोड़े सरकार : जयराम

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भाजपा समर्थित प्रत्याशी की जीत के बाद मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू पर तीखा हमला बोला। उन्होंने मुख्यमंत्री के चुनाव को 'नॉर्मल रूटीन' बताए जाने पर तंज कसते हुए कहा कि यदि यह सामान्य प्रक्रिया थी तो सरकार ने लोकतांत्रिक और संवैधानिक मर्यादाओं को ताक पर क्यों रखा।

जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि पंचायतीराज चुनावों को रोकने के लिए बार-बार प्रयास किए गए और सरकार को कई बार न्यायालय की फटकार का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि जिला परिषद सदस्यों को 'एक दिन की वैल्यू' वाला बताना जनप्रतिनिधियों और जनादेश का अपमान है। उन्होंने सरकार पर नियमों में बदलाव कर अपने करीबियों और समर्थकों को जनप्रतिनिधि बनाने का रास्ता तैयार करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को हार की हताशा में बयान देने के बजाय प्रदेश की जनता के सामने वास्तविक स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। जयराम ठाकुर ने दावा किया कि कांग्रेस के भीतर गुटबाजी बढ़ गई है और इसी कारण कैबिनेट बैठक टाल दी गई तथा जन संवाद कार्यक्रम भी नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की अधिकांश नीतियां शुल्क बढ़ाने और सुविधाएं समाप्त करने से जुड़ी हैं। परिवार रजिस्टर की नकल समेत विभिन्न सेवाओं पर शुल्क लगाने से आम लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर स्पष्टीकरण देने की मांग की।

बस में सवार युवक से पकड़ा चिट्टा, गिरफ्तार

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। शिमला पुलिस की स्पेशल सेल ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शोघी के पास एक बस में सवार युवक से 7.5 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार शुक्रवार को स्पेशल सेल शिमला की टीम शोघी चौकी के पास मौजूद थी। इसी दौरान सोलन से शिमला की ओर आ रही एक बस को जांच के लिए रोका गया। बस की तलाशी के दौरान उसमें सवार नीरज कुमार के कब्जे से 7.5 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक नीरज कुमार (25) सोलन जिला के अर्की का रहने वाला है। बरामदगी के बाद पुलिस थाना बालुगंज में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 के तहत मामला दर्ज किया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। मामले की आगामी जांच जारी है।

परेशानी मॉर्थ दफ्तर शिमला शिफ्ट, मरम्मत का जिम्मा लेने को कोई तैयार नहीं

हमीरपुर-अवाहदेवी हाईवे पर सफर बना मुसीबत

अनिल कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। हमीरपुर से अवाहदेवी तक जाने वाले अटारी-मनाली टू-लेन नेशनल हाईवे की हालत इन दिनों फिर बेहद दयनीय हो चली है।

हमीरपुर से लेकर अवाहदेवी तक यह हाईवे जगह-जगह से उखड़ना शुरू हो गया है, जिससे इस पर सफर करना वाहन चालकों के लिए किसी सजा से कम नहीं है। सबसे ज्यादा खराब स्थिति दरकोटि के पास बनी हुई है, जहां सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे उभर आए हैं। इन गड्ढों के कारण वाहन चालकों को हर पल हादसे का डर सता रहा है। इसी तरह एनआईटी हमीरपुर के आगे कोट के पास भी सड़क की हालत बेहद खराब है। यहां टारिंग उखड़ चुकी है और बजरी बाहर आ गई हैं। टौणी देवी के आसपास भी कई जगह सड़क टूट चुकी है। टौणी देवी से आगे अवाहदेवी तक तो दर्जनों जगह गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि टौणी देवी से एनआईटी तक लगभग पांच जगह पर सड़क का सेंटर वाला हिस्सा पूरी तरह से जर्जर हो चुका है और धंसना शुरू हो गया है। इससे रात के समय हादसे का खतरा कई गुना बढ़ गया है, क्योंकि सामने से आ रहे वाहन को गड्ढे का अंदाजा नहीं लग पाता। इस हाईवे की मरम्मत को लेकर अब एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के तहत इस रोड का निर्माण हुआ है। लेकिन हमीरपुर स्थित इस मंत्रालय का यह दफ्तर अब शिमला ट्रांसफर हो गया है इसलिए इस सड़क के रखरखाव का जिम्मा अब कौन संभालेगा यहां कोई अधिकारी बैठता नहीं है, इसका कोई पता नहीं। अब इस सड़क की मरम्मत कौन करेगा, यह किसी को पता नहीं है, जब इस बारे में हमीरपुर में नेशनल हाईवे का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे अधिशाषी अभियंता दीपक कपिल से बात की गई तो उन्होंने साफ कहा कि यह रोड उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। इसके बारे में मॉर्थ वाले अधिकारी ही बता पाएंगे। वहीं शिमला स्थित मॉर्थ के अधिकारी पिछले एक हफ्ते से फोन तक नहीं उठा रहे हैं। ऐसे में स्थिति यह है कि वाहन चालक हिचकोले खाते रहेंगे और आने वाले कुछ दिनों में बरसात के कारण इस हाईवे का ढांचा और ज्यादा बिगड़ने की आशंका है।

स्थानीय लोगों ने सरकार से मांग की है कि इस हाईवे की मरम्मत की जिम्मेदारी तुरंत तय की जाए। जिस कंपनी ने इसका निर्माण किया है उसके खिलाफ भी करवाई तो होनी ही चाहिए। यह हाईवे पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के समीरपुर स्थित आवास को भी जोड़ता है।

एनआईटी हमीरपुर में जीएसटी रैशनलाइजेशन 2.0 .पर राष्ट्रीय सम्मेलन का सफल आयोजन

अनिल कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर के प्रबंधन अध्ययन विभाग द्वारा भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से तेजी से बदलते और ज्यादा क्षमता वाले सेक्टर में मौके और वेल्थ क्रिएशन के लिए जीएसटी रैशनलाइजेशन 2.0 विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन ग्रोथ-2026 का आयोजन 9-10 सितंबर को सफलतापूर्वक किया गया।

सम्मेलन का आयोजन एनआईटी हमीरपुर के निदेशक प्रो. एचएम सूर्यवंशी के संरक्षण एवं मार्गदर्शन में किया गया। उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। डॉ. अर्चना संतोष नानौटी, कुलसचिव, एनआईटी हमीरपुर विशिष्टातिथि के रूप में उपस्थित रहीं। प्रो. संतोष रंगनेकर, आईआईटी रुड़की तथा इंजीनियर अनुपम ठाकुर, कुलसचिव, हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय ने मुख्य वक्ताओं के रूप में सम्मेलन में भाग लिया और अपने महत्वपूर्ण शैक्षणिक एवं व्यावसायिक विचार साझा किए। डॉ. विवेक तिवारी ने सम्मेलन अध्यक्ष के रूप में दायित्व निभाया, जबकि डॉ. शैम्पी कंबोज एवं डॉ. सुंदर कला नेगी ने सम्मेलन सचिव के रूप में आयोजन का समन्वय किया। दो दिवसीय सम्मेलन में देश के विभिन्न भागों से आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, आईआईआईटी तथा अन्य प्रतिष्ठित सरकारी एवं निजी विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों के शिक्षकों, शोधकर्ताओं, प्रतिनिधियों और शोध-पत्र प्रस्तुतकर्ताओं ने भाग लिया। सम्मेलन के लिए 100 से अधिक शोध-पत्र प्राप्त हुए, जबकि विभिन्न विषयों पर 12 तकनीकी सत्रों का आयोजन किया गया।

न्यूज ब्रीफ

माता श्री बज्रेश्वरी देवी के दरबार पहुंचीं बॉलीवुड अभिनेत्री नायरा बनर्जी, विधिवत की पूजा-अर्चना

भारतेन्दु संवाददाता, कांगड़ा। बॉलीवुड अभिनेत्री नायरा बनर्जी ने शुक्रवार को कांगड़ा स्थित प्रसिद्ध माता श्री बज्रेश्वरी देवी मंदिर पहुंचकर माता के दर्शन किए और विधिवत पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर पहुंचने पर मंदिर के पुजारी राम शर्मा ने उन्हें विधिपूर्वक पूजा-अर्चना करवाई। इस दौरान पुजारी ने नायरा बनर्जी को माता श्री बज्रेश्वरी देवी की महिमा, मंदिर के धार्मिक महत्व और इससे जुड़ी ऐतिहासिक मान्यताओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अभिनेत्री ने मंदिर की धार्मिक व ऐतिहासिक आस्था से जुड़ी विभिन्न जानकारियां भी लीं और मंदिर परिसर का अवलोकन किया। पूजा-अर्चना के बाद उन्होंने माता के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। नायरा बनर्जी के मंदिर पहुंचने की खबर मिलते ही श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में भी उत्साह देखने को मिला। कई लोगों ने उनके साथ तस्वीरें खिंचवाने की इच्छा जताई। इस दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच अभिनेत्री के साथ फोटो लेने को लेकर खासा उत्साह नजर आया।

नूरपुर पुलिस ने ऑनलाइन ठगी का शिकार महिला के 28,500 करवाए वापस

भारतेन्दु संवाददाता, नूरपुर। पुलिस जिला नूरपुर द्वारा साइबर अपराधों से जुड़े मामलों पर तत्परता से की जा रही कार्रवाई के तहत नूरपुर पुलिस के अंतर्गत पुलिस थाना रेहन की टीम ने त्वरित तकनीकी सहायता से यूपीआई फ्रॉड की शिकार हुई एक महिला के 28,500 वापस (रिफंड) करवाए हैं। बीते 2 सितंबर 2026 को शिकायतकर्ता आशा देवी, निवासी गांव बरी, डाकघर बारी, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा ने साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई थी कि एक अनजान कॉलर द्वारा झांसा देकर उनके बैंक खाते से कुल 32,500 की ऑनलाइन धोखाधड़ी की गई है। शिकायत प्राप्त होने पर पुलिस थाना रेहन की टीम द्वारा मामले में आवश्यक तकनीकी प्रक्रिया शुरू की गई। संबंधित पोर्टल/एमआरएम के माध्यम से संपर्क साधकर ट्रांजेक्शन को ट्रैक किया गया। पुलिस टीम के इन प्रयासों से फ्रॉड की गई राशि में से 28,500 पीड़ित महिला के बैंक खाते में सुरक्षित वापस करवा दिए गए हैं। नूरपुर पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के फोन कॉल या संदेश पर विश्वास न करें। किसी के कहने पर पैसे ट्रांसफर न करें और न ही अपना ओटीपी, यूपीआई पिन या बैंक संबंधी विवरण किसी से साझा करें। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की स्थिति में तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें अथवा नजदीकी पुलिस थाने में सूचित करें।

विद्यार्थियों ने समझी मानव व संचार विकास की यात्रा

भगत सिंह गुलेरिया, भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। वल्लभ राजकीय महाविद्यालय, मंडी के पत्रकारिता व जनसंचार विभाग द्वारा 'सोसाइटी इन इन्फॉर्मेशन एजः आदिमानव से आधुनिक मानव तक विकास यात्रा एवं संचार विकास' विषय पर एकदिवसीय संगोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता विभागाध्यक्ष डॉ. चमन ने की। उन्होंने कहा कि आदिमानव से आधुनिक मानव तक की विकास यात्रा संचार के निरंतर विकास की यात्रा भी है। संकेतों, हाव-भाव, ध्वनियों और गुफा चित्रों से शुरू हुआ संचार आज इंटरनेट, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक पहुंच चुका है। इस अवसर पर पृथ्वी की उत्पत्ति से मानव विकास तथा आधुनिक संचार तक की यात्रा पर ज्ञानवर्धक डॉक्यूमेंट्री प्रदर्शित की गई। विद्यार्थियों ने भी विषय पर अपने विचार साझा किए। प्राचार्य डॉ. संजीव कुमार ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को मानव विकास, संचार के बदलते स्वरूप और डिजिटल तकनीक के प्रभाव से परिचित करवाना है। इस अवसर पर विभाग के शिक्षक एवं विद्यार्थी मौजूद रहे।

विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर विद्यार्थियों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति किया जागरूक

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। राजकीय महाविद्यालय बिलासपुर की एनएसएस इकाई के तत्वावधान में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर मानसिक स्वास्थ्य एवं तनाव प्रबंधन विषय पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें करीब 200 विद्यार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय प्राचार्य डॉ. पीएस कटवाल ने की, जबकि एम्स बिलासपुर के मनोरोग विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. ज्योति गुप्ता मुख्य वक्ता रहीं। डॉ. ज्योति गुप्ता ने युवाओं में बढ़ते तनाव, चिंता और अवसाद पर चर्चा करते हुए मानसिक अस्वस्थता के लक्षण, बचाव तथा तनाव प्रबंधन के उपाय बताए। उन्होंने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए चिकित्सीय परामर्श लेना किसी प्रकार का कलंक नहीं है। उन्होंने योग, व्यायाम और नृत्य को मानसिक रूप से स्वस्थ रहने में उपयोगी बताया। कार्यक्रम में एनएसएस स्वयंसेवी, एनसीसी कैडेट्स और बी.वॉक विभाग के विद्यार्थी उपस्थित रहे। प्रश्नोत्तर सत्र में विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान किया गया तथा कुछ विद्यार्थियों की व्यक्तिगत काउंसलिंग भी की गई। अंत में मुख्य वक्ता को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया।

फ्लाई ब्वॉय (ऑफसेट) का परिणाम घोषित

अनिल कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में फ्लाई ब्वॉय (ऑफसेट) के 3 पदों को जॉब ट्रेनी के आधार पर भरने के लिए पोस्ट कोड-25010 के तहत आयोजित कंप्यूटर आधारित परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच के बाद अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि इन पदों के लिए कुल 108 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिनमें से 54 उम्मीदवारों ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा दी थी और इस परीक्षा में 12 उम्मीदवारों का चयन दस्तावेजों की जांच के लिए किया गया था। 3 अगस्त को दस्तावेजों की जांच के बाद 3 उम्मीदवारों निखिल खरियाल, बलवंत कुमार और हितेश कुमार का चयन किया गया है। सचिव ने बताया कि यह अंतिम परिणाम सभी उम्मीदवारों के नाम, रोल नंबर और अंकों सहित आयोग की वेबसाइट एचपीआरसीए.एचपी.जीओवी.इन पर उपलब्ध करवा दिया गया है।

स्कूली शिक्षा में हिंदी माध्यम विकल्प हो उपलब्ध

भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश टीजीटी कला संघ ने प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड एवं स्कूल शिक्षा निदेशक से मांग की है कि कक्षा 1 से 10 तक विद्यार्थियों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों का विकल्प उपलब्ध कराया जाए। संघ ने विशेष रूप से कक्षा 6 की सामाजिक अध्ययन, हिमाचल की लोक संस्कृति एवं योग तथा कला विषयों की पुस्तकें हिंदी माध्यम में भी प्रकाशित करने की मांग उठाई है।संघ के प्रदेश महासचिव विजय हीर ने कहा कि 12 सितंबर 2025 को शिक्षा विभाग की बैठक में कक्षा 6 के सामाजिक अध्ययन के लिए हिंदी माध्यम का विकल्प उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया था तथा इसके निर्देश शिक्षा बोर्ड को भी दिए गए थे। इसके बावजूद वर्तमान सत्र में अधिकांश सरकारी विद्यालयों में सामाजिक अध्ययन की पुस्तकें केवल अंग्रेजी माध्यम में उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से अंग्रेजी में अध्ययन करना पड़ रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350(ए) के अनुसार प्रत्येक राज्य का दायित्व है कि विद्यार्थियों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाए। इसलिए इच्छुक विद्यार्थियों को सामाजिक अध्ययन सहित संबंधित विषयों की पुस्तकें हिंदी माध्यम में उपलब्ध कराना आवश्यक है। संघ ने सुझाव दिया कि सत्र 2026-27 की पाठ्यपुस्तकें प्रकाशित करने से पूर्व प्रत्येक विद्यालय से हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम चुनने वाले विद्यार्थियों की वास्तविक मांग एकत्र की जाए और उसी के अनुसार पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएं। सरकार द्वारा अंग्रेजी माध्यम प्रारंभ करने का निर्णय स्वागत योग्य है, किंतु इसे शिक्षा का एकमात्र माध्यम बनाना नई शिक्षा नीति और मातृभाषा आधारित शिक्षण की भावना के अनुरूप नहीं है।

टांडा मेडिकल कॉलेज में सरकारी दवाइयों की कमी, मरीज बाहर से दवा खरीदने को मजबूर

लोगों ने सरकार से अस्पताल में सभी आवश्यक दवाइयां उपलब्ध करवाने की मांग की

भारतेन्दु संवाददाता, कांगड़ा। प्रदेश के प्रमुख अस्पतालों में शामिल डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं अस्पताल टांडा में सरकारी दवाइयों की उपलब्धता को लेकर मरीजों व तीमारदारों में रोष बढ़ता जा रहा है। यहां हृदय रोग, हड्डी रोग, बाल रोग, स्त्री एवं प्रसूति रोग, मेडिसिन और कैंसर सहित विभिन्न विभागों में प्रतिदिन बड़ी संख्या में मरीज उपचार के लिए पहुंचते हैं। मिली जानकारी के अनुसार रोजाना करीब 3 हजार मरीज ओपीडी में उपचार करवाने आते हैं।

मरीजों का आरोप है कि चिकित्सकों द्वारा लिखी जाने वाली कई सामान्य दवाइयां भी अस्पताल की डिस्पेंसरी में उपलब्ध नहीं हो रही हैं। इनमें पैरासिटामोल, पेट दर्द की दवाइयां, महिलाओं और बच्चों के लिए आवश्यक दवाइयां सहित अन्य दवाएं शामिल हैं। ऐसे में मरीजों को मजबूरन बाजार से महंगे दामों पर दवाइयां खरीदनी पड़ रही हैं। बताया जा रहा है कि सरकार की ओर से टांडा मेडिकल कॉलेज के लिए दवाइयों की उपलब्धता को लेकर बड़े दावे किए जाते हैं। वहीं, अस्पताल को वास्तविक रूप से मिलने वाली दवाइयों की मात्रा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अस्पताल में उपचार के अलावा ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाली आवश्यक सामग्री और ग्लव्स की उपलब्धता को लेकर भी मरीजों ने चिंता जताई है। अस्पताल पहुंचे सुलोचना देवी, करम चंद, प्यार चंद, सुलेखा देवी, प्रीतम चंद और लक्ष्मी देवी सहित अन्य लोगों ने दवाइयों की कमी पर रोष जताया। उन्होंने कहा कि दूर-दराज क्षेत्रों से उपचार के लिए आने वाले मरीजों को यदि दवाइयां बाहर से खरीदनी पड़ें, तो आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। लोगों ने सरकार से अस्पताल में सभी आवश्यक दवाइयां उपलब्ध करवाने की मांग की है।

इस संबंध में टांडा अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी डॉ. विवेक बुनियाल ने बताया कि अस्पताल में दवाइयों की जो सूची तैयार की जाती है, उसमें शामिल सभी दवाइयां हमेशा उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। अस्पताल प्रशासन की ओर से आवश्यक दवाइयों की सूची सरकार को भेजी जाती है। उन्होंने कहा कि दवाइयां उपलब्ध न होने पर मरीजों को जवाब देना उनके लिए भी मुश्किल स्थिति होती है।

हाउस टैक्स न देने वालों पर नप की सख्ती, 35 करदाताओं को नोटिस

◆ 132 दुकानों का करीब एक करोड़ किराया बकाया

अनिल कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। नगर परिषद सुजानपुर ने लंबे समय से हाउस टैक्स और दुकानों का किराया जमा न करवाने वाले बकायेदारों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। परिषद के नौ वार्डों में गृहकर के रूप में करीब 41 लाख रुपये की राशि लंबे समय से बकाया है। नगर परिषद के रिकॉर्ड के अनुसार कुल 2513 गृह करदाता हैं। इनमें से 35 करदाताओं को नोटिस जारी कर बकाया गृहकर निर्धारित समय में जमा करवाने के निर्देश दिए गए हैं।

नगर परिषद ने स्पष्ट किया है कि अब बकाया राशि की वसूली के लिए केवल नोटिस जारी करने तक कार्रवाई सीमित नहीं रहेगी। नियमानुसार आगामी दिनों में और सख्त कदम उठाए जाएंगे। इसी कड़ी में 16 बकायेदारों के बिजली कनेक्शन काटने के लिए बिजली बोर्ड को सिफारिश भेजी गई है। परिषद की इस कार्रवाई के बाद लंबे समय से गृहकर जमा न करवाने वाले लोगों में भी हलचल बढ़ गई है। हाउस टैक्स के साथ नगर परिषद की दुकानों का किराया भी बड़ी समस्या बना हुआ है। परिषद की 132 दुकानों का करीब एक करोड़ रुपये किराया बकाया बताया गया है। किराया जमा न करवाने वाले 24 दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए हैं। परिषद ने बकाया किराये की वसूली के लिए भी प्रक्रिया तेज कर दी है। नगर परिषद के ईओ हर्षित शर्मा ने बताया कि परिषद का काफी पैसा बकाया होने के कारण विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बकायेदारों को समय पर राशि जमा करवाने के निर्देश दिए गए हैं और आवश्यकता पड़ने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि नगर परिषद को शहर की सफाई, स्ट्रीट लाइट, नालियों, सड़कों और अन्य विकास कार्यों के लिए नियमित धनराशि की जरूरत रहती है। ऐसे में बकाया राशि की वसूली से विकास कार्यों को गति मिलेगी और शहरवासियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने में मदद होगी। परिषद की कार्रवाई से अब यह देखना होगा कि कितने बकायेदार समय पर भुगतान करते हैं।

नौकरी देने के बजाय युवाओं को लॉटरी और भांग की खेती में झोंक रही सरकार : जम्वाल

◆ कहा- जनहित में लॉटरी और भांग की खेती पर रोक लगाए सरकार

अमर सिंह ठाकुर, भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। सदर विधायक त्रिलोक जम्वाल ने हिमाचल प्रदेश में लॉटरी दोबारा शुरू करने और भांग की खेती को वैध करने के फैसले को लेकर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है।

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार युवाओं को रोजगार देने के बजाय उन्हें लॉटरी और नशे की ओर धकेल रही है। त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि कांग्रेस ने हर साल एक लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन अब सरकार राजस्व जुटाने के नाम पर लॉटरी शुरू कर रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व में लॉटरी के कारण कई परिवार आर्थिक रूप से तबाह हुए और इसके गंभीर सामाजिक दुष्परिणाम सामने आए थे। इन्हीं कारणों से पूर्व मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने लॉटरी पर प्रतिबंध लगाया था। विधायक ने कहा कि प्रदेश में चिट्टा पहले ही गंभीर समस्या बन चुका है।

इससे युवा प्रभावित हो रहे हैं और आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐसे समय में भांग की खेती को अनुमति देना और लॉटरी शुरू करना सरकार की गलत प्राथमिकताओं को दर्शाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार अपनी चुनावी गारंटियों से भी मुकर चुकी है। पांच लाख नौकरियां, महिलाओं को 1500 रुपए मासिक, 300 यूनिट मुफ्त बिजली, गोबर और दूध खरीद जैसी घोषणाएं पूरी नहीं हुई हैं। उन्होंने सरकार से जनहित में लॉटरी और भांग की खेती पर रोक लगाने की मांग की।

नादौन में सेल्स-मार्केटिंग और सर्विस इंजीनियर के साक्षात्कार 15 को

भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। अणु, हमीरपुर की प्रसिद्ध कंपनी मैसर्स विमांशु एलिवेटर एंड एस्क्लेटर में सेल्स-मार्केटिंग और सर्विस इंजीनियर के 5-5 पदों को भरने के लिए 15 सितंबर को सुबह 10 बजे उपरोजगार कार्यालय नादौन में साक्षात्कार लिए जाएंगे। जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि सेल्स-मार्केटिंग के 5 पदों के लिए 25 से 35 वर्ष तक के बारहवीं पास या इससे अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले पुरुष अभ्यर्थी (फ्रेशर्स) पात्र होंगे। चयनित उम्मीदवारों को 18 हजार से 20 हजार रुपये तक मासिक वेतन मिलेगा। सर्विस इंजीनियर के पदों के लिए भी दसवीं-बारहवीं पास और किसी भी ट्रेड में आईटीआई डिप्लोमाधारक पुरुष उम्मीदवार (फ्रेशर्स) पात्र होंगे। उनकी आयु 25 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। चयनित उम्मीदवारों को 15 हजार से 20 हजार रुपए तक मासिक वेतन मिलेगा।

रैगिंग के दोषी विद्यार्थी को हो सकती है 3 वर्ष की सजा और 50 हजार रुपए जुर्माना

अनिल कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। राजकीय बहुतकनीकी महाविद्यालय हमीरपुर की एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक शुक्रवार को महाविद्यालय के सम्मेलन हॉल में आयोजित की गई।

प्रधानाचार्य चंद्रशेखर की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में कमेटी के सदस्यों, विभिन्न विभागाध्यक्षों, अन्य फैकल्टी मैंबर्स, छात्र प्रतिनिधियों, अभिभावकों और हॉस्टल एवं पीजी संचालकों ने भाग लिया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य ने कहा कि शिक्षण संस्थानों में रैगिंग को रोकने के लिए बहुत ही कड़ा कानून बनाया गया है। इसमें रैगिंग को गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया है। रैगिंग के दोषी विद्यार्थी को 3 साल का कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माना हो सकता है तथा उसे संस्थान से निष्कासित भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि संस्थान एवं हॉस्टल के परिसर के अलावा पीजी और आसपास के स्थानों में विद्यार्थी को किसी भी तरह से शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने जैसी सभी गतिविधियां रैगिंग की श्रेणी में आती हैं।

प्रधानाचार्य ने बताया कि बहुतकनीकी महाविद्यालय परिसर, हॉस्टलों एवं पीजी तथा इनके आस-पास के क्षेत्रों में रैगिंग जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। संस्थान में एंटी रैगिंग कमेटी के अलावा एंटी रैगिंग दस्तों का गठन भी किया गया है। संस्थान, हॉस्टल और इनके आस-पास के सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर हेल्पलाइन नंबर भी प्रदर्शित किए गए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों से कहा कि वे अपनी-अपनी कक्षाओं में विद्यार्थियों को रैगिंग रोधी कानून के विभिन्न प्रावधानों के प्रति जागरुक करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत एंटी रैगिंग कमेटी या एंटी रैगिंग दस्ते के सदस्यों को दें। प्रधानाचार्य ने बताया कि इस वर्ष भी नए विद्यार्थियों को रैगिंग जैसी गतिविधियों के प्रति जागरुक किया गया है। उन्होंने कहा कि एंटी रैगिंग कमेटी, समस्त फैकल्टी और छात्र प्रतिनिधियों के सामूहिक प्रयासों से ही संस्थान और इसके आस-पास के पूरे परिसर को रैगिंग मुक्त बनाया जा सकता है। इस अवसर पर हमीरपुर थाने के एएसआई प्रदीप कुमार और कमेटी के अन्य सदस्यों ने भी रैगिंग रोधी अधिनियम 2009 के विभिन्न प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी।

आईएचएम हमीरपुर में नवागंतुक विद्यार्थियों का हुआ भव्य स्वागत

नैंसी मिस और नितिन बने मिस्टर फ्रेशर

भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टैक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, हमीरपुर में नए विद्यार्थियों का स्वागत समारोह 'अभ्युदय: दीक्षारंभ 2026' आयोजित किया गया, जिसमें हमीरपुर के एडीसी एवं संस्थान के कार्यकारी प्रधानाचार्य अभिषेक गर्ग ने मुख्यातिथि के रूप में शिरकत की।

इस अवसर पर नए विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए अभिषेक गर्ग ने कहा कि इस समारोह का उद्देश्य नवागंतुक विद्यार्थियों और वरिष्ठ विद्यार्थियों के बीच आपसी संवाद, सहयोग, सौहार्द व आत्मीयता को बढ़ावा देना तथा उन्हें संस्थान की समृद्ध शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं से परिचित करवाना है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने जीवन में स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें और उसे प्राप्त करने के लिए अनुशासन, निरंतर मेहनत, सकारात्मक सोच और समर्पण के साथ आगे बढ़ें। उन्होंने विद्यार्थियों को आईएचएम हमीरपुर में उपलब्ध शैक्षणिक एवं व्यावहारिक अवसरों का अधिकतम लाभ उठाने तथा अपने व्यक्तित्व और पेशेवर कौशल के निरंतर विकास के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटैलिटी उद्योग केवल तकनीकी दक्षता पर आधारित नहीं है, बल्कि इसमें प्रभावी संचार, सकारात्मक व्यवहार, टीम भावना, नेतृत्व क्षमता और उत्कृष्ट सेवाभाव का भी विशेष महत्व है। उन्होंने वरिष्ठ विद्यार्थियों से भी आह्वान किया कि वे नवागंतुक विद्यार्थियों के मार्गदर्शक एवं सहयोगी बनकर उन्हें संस्थान के वातावरण में सहजता से घुलने-मिलने में सहायता करें। इससे पहले, संस्थान के विभागाध्यक्ष पुनीत बंटा और लेखा एवं प्रशासनिक अधिकारी पीयूष ठाकुर ने मुख्यातिथि का स्वागत किया। जबकि, विद्यार्थियों ने शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इनमें निहारिका, श्वेतल, चांदनी, सुजल, अजय, सूरज, पूर्वांश और अन्य विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत नाटी लोक नृत्य आकर्षण का केंद्र रहा। समारोह में नैंसी को मिस फ्रेशर 2026 और नितिन ठाकुर को मिस्टर फ्रेशर 2026 चुना गया। विभागाध्यक्ष पुनीत बंटा ने मुख्यातिथि, सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं संस्थान के कर्मचारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, नेतृत्व, टीम भावना, रचनात्मकता और पारस्परिक सम्मान की भावना विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नवागंतुक विद्यार्थियों को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आईएचएम हमीरपुर केवल एक शैक्षणिक संस्थान नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को ज्ञान, कौशल, संस्कार और आत्मविश्वास के साथ एक सफल व संवेदनशील आतिथ्य पेशेवर के रूप में तैयार करने वाला परिवार है।

एचआईवी/एड्स से सुरक्षा हमारा उद्देश्य होमगार्ड अधिकारियों को किया जागरूक

भारतेन्दु संवाददाता, अर्की। हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग एवं एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत चलाए जा रहे एचआईवी/एड्स सूचना, शिक्षा एवं संचार जागरूकता अभियान के अंतर्गत गांव कोटली स्थित होमगार्ड प्रशिक्षण केंद्र में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

यह अभियान 12 अगस्त से 12 अक्तूबर तक चलाया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य एचआईवी/एड्स, यौन संचारित संक्रमण (एसटीआई) और बचाव के उपायों के प्रति लोगों को वैज्ञानिक जानकारी देना रहा। कार्यक्रम का आयोजन ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर अर्की डॉ. मुक्ता रस्तोगी के मार्गदर्शन में किया गया। एचआईवी काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर, सिविल अस्पताल अर्की के काउंसलर डॉ. विजय कुमार शांडिल ने होमगार्ड अधिकारियों को एचआईवी/एड्स के कारण, संक्रमण के माध्यम और बचाव की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एचआईवी मुख्य रूप से असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित रक्त, संक्रमित सुई अथवा सीरिंज के साझा उपयोग तथा कुछ परिस्थितियों में संक्रमित मां से बच्चे में फैल सकता है। वहीं हाथ मिलाने, साथ बैठने, भोजन करने, गले मिलने या मच्छर के काटने से संक्रमण नहीं फैलता। उन्होंने कहा कि समय पर जांच और उपचार से एचआईवी संक्रमित व्यक्ति सामान्य जीवन जी सकता है। कार्यक्रम में एसटीआई के लक्षणों व उपचार को लेकर भी जानकारी दी गई। अंत में होमगार्ड अधिकारियों ने जागरूकता फैलाने, सुरक्षित व्यवहार अपनाने और एचआईवी प्रभावित लोगों से भेदभाव न करने की शपथ ली।

सत्यदेव शर्मा को मिलेगा राजभाषा हिंदी पुरस्कार

भारतेन्दु संवाददाता, अर्की। उपमंडल अर्की की ग्राम पंचायत पलोग के पलोग गांव निवासी सत्यदेव शर्मा को हिंदी में उत्कृष्ट शासकीय कार्य करने के लिए राजभाषा हिंदी पुरस्कार-2026 से सम्मानित किया जाएगा। भाषा एवं संस्कृति विभाग, हिमाचल प्रदेश ने इस संबंध में आधिकारिक पत्र जारी किया है। सत्यदेव शर्मा वर्तमान में हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला में उप सचिव (विधि-राजभाषा) के पद पर सेवाएं दे रहे हैं। विभाग के अनुसार उन्हें अधिकारी वर्ग में हिंदी में उत्कृष्ट राजकीय कार्य के लिए यह सम्मान प्रदान किया जा रहा है। पुरस्कार 14 सितंबर 2026 को राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह के दौरान बचत भवन, रिकांगपिओ, जिला किन्नौर में प्रदान किया जाएगा। समारोह का आयोजन सुबह 11 बजे होगा। सत्यदेव शर्मा की उपलब्धि पर पलोग गांव व ग्राम पंचायत के लोगों ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि राजभाषा हिंदी के क्षेत्र में मिला यह सम्मान पूरे क्षेत्र के लिए गौरव की बात है।

अभियान बच्चों की आंखों की सेहत को लेकर डीसी राहुल कुमार ने की समीक्षा बैठक

15 में मायोपिया व 14 में हाइपरमेट्रोपिया की हुई पहचान

अमर सिंह ठाकुर, भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। डीसी राहुल कुमार ने जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे 'मिशन दृष्टि' अभियान की प्रगति को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत अब तक छह स्कूलों में 3 से 8 वर्ष आयु वर्ग के 225 बच्चों की आंखों की जांच की जा चुकी है। जांच में 29 बच्चों में दृष्टि संबंधी दोष पाए गए हैं। इनमें 15 बच्चे मायोपिया (निकट दृष्टि दोष) और 14 बच्चे हाइपरमेट्रोपिया (दूर दृष्टि दोष) से प्रभावित पाए गए।

डीसी ने कहा कि प्रत्येक बच्चे की जांच का डेटा तैयार किया जा रहा है, ताकि दृष्टि संबंधी समस्याओं की पहचान के साथ उपचार और फॉलोअप की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने दृष्टि दोष वाले बच्चों के अभिभावकों से आग्रह किया कि टीम की सलाह के अनुसार 15 दिनों के भीतर नजदीकी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र में नेत्र रोग विशेषज्ञ से परामर्श लें और आवश्यक सुधारात्मक उपाय करवाएं। राहुल कुमार ने कहा कि अभियान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण एवं दूरदराज क्षेत्रों के बच्चों तक नियमित स्वास्थ्य और नेत्र जांच की सुविधा पहुंचाना है।

बच्चों में आंखों की समस्या के कारण देखने में परेशानी के साथ सिरदर्द, एकाग्रता में कमी और किसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो सकती है। इससे उनकी पढ़ाई और सीखने की क्षमता प्रभावित होती है। समय पर समस्या की पहचान कर चश्मा अथवा अन्य आवश्यक उपचार उपलब्ध करवाने से बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन और दैनिक गतिविधियों में सुधार लाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की टीमों को आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किया जा रहा है। सीएसआर और डीएमएफटी के सहयोग से टीमों को ऑटो-रिफ्रैक्टोमीटर सहित आवश्यक उपकरण उपलब्ध करवाए गए हैं। जिला के सभी चार ब्लॉकों में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की टीमें बच्चों की स्वास्थ्य जांच कर रही हैं और स्वास्थ्य संबंधी दोष पाए जाने पर आवश्यक फॉलोअप सुनिश्चित किया जा रहा है। डीसी ने कहा कि अभियान को मिशन मोड में आगे बढ़ाया जा रहा है।

पहले चरण में अधिक से अधिक बच्चों की स्क्रीनिंग, दृष्टि दोष की पहचान और आवश्यक उपचार पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इसके बाद दूसरे चरण में नियमित निगरानी और फॉलोअप व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों में भी मिशन दृष्टि के तहत बच्चों की आंखों की जांच की जाएगी बैठक में सीएमओ डॉ. शशि दत्त, डीपीओ आईसीडीएस नरेंद्र कुमार, उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा अरुण गौतम, नोडल अधिकारी उच्च शिक्षा स्कूल अनिल कुमार, सचिव जिला रेडक्रॉस अमित कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

गरीब परिवारों को पक्की छत देना सरकार की प्राथमिकता : पठानिया

भारतेन्दु संवाददाता, धर्मशाला। शाहपुर के विधायक व उपमुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने शुक्रवार को नगर पंचायत शाहपुर के 9 पात्र लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान निर्माण के लिए पहली किश्त के रूप में 70-70 हजार रुपए की धनराशि के चेक वितरित किए।

इस दौरान उपमुख्य सचेतक ने कुल 6 लाख 30 हजार रुपए की राशि वितरित की। शाहपुर के मिनी सचिवालय सभागार में आयोजित कार्यक्रम में केवल सिंह पठानिया ने कहा कि नगर पंचायत शाहपुर में अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 99 पात्र लाभार्थियों को करीब 1.60 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की जा चुकी है। योजना के तहत प्रत्येक पात्र लाभार्थी को मकान निर्माण के लिए कुल 2.50 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े गरीब व जरूरतमंद व्यक्ति तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। इसी उद्देश्य से प्रदेश में वर्षों बाद बीपीएल परिवारों का सर्वे करवाया गया है, ताकि कोई भी पात्र परिवार सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं से जरूरतमंद परिवारों को अपना पक्का आशियाना बनाने में महत्वपूर्ण मदद मिल रही है। नगर पंचायत शाहपुर के उपाध्यक्ष राजीव पटियाल ने कार्यक्रम में आने पर मुख्यातिथि का स्वागत किया एवं नगर पंचायत द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं बारे जानकारी दी।

जेस मार्टिन का खूबसूरत व स्टाइलिश अंदाज

जेस मार्टिन एक प्रतिभाशाली खेल महिला हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत, अनुशासन और खेल के प्रति समर्पण से पहचान बनाई है। उनके संघर्ष और उपलब्धियां युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायक हैं। खेल के मैदान पर उनका आत्मविश्वास और निरंतर बेहतर प्रदर्शन उन्हें खास बनाता है।

काउंटी में कुलदीप को 10 विकेट

फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज बने

एजेंसी, लंदन

लीड्स के हेडिंग्ले में एसेक्स के खिलाफ काउंटी चैंपियनशिप मैच में कुलदीप यादव ने 10 विकेट लिए। उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पहली बार एक मैच में 10 विकेट लिए हैं। उनके प्रदर्शन से यॉर्कशायर ने एसेक्स को पारी और 106 रन से हराया। यॉर्कशायर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 390 रन बनाए। कुलदीप ने 94 गेंदों पर 36 रन भी बनाए। इसके जवाब में एसेक्स की पहली पारी 171 रन पर सिमट गई। कुलदीप ने 23 ओवर में 70 रन देकर 4 विकेट लिए। फॉलोऑन खेलते हुए एसेक्स की दूसरी पारी में कुलदीप ने 16 ओवर में 50 रन देकर 6 विकेट लिए। उनकी गेंदबाजी के सामने एसेक्स की टीम 40 ओवर में 113 रन पर ऑलआउट हो गई। कुलदीप ने मैच में कुल 10 विकेट लिए और 120 रन दिए। यॉर्कशायर ने तीसरे दिन ही मुकाबला पारी और 106 रन से अपने नाम कर लिया।

यॉर्कशायर ने एसेक्स को पारी और 106 रन से हराया

कुलदीप यादव को हेडिंग्ले की पिच ने दिया फायदा

कुलदीप यादव ने मैच के बाद हेडिंग्ले की पिच को अपनी गेंदबाजी के लिए बेहतर बताया था। उन्होंने कहा था कि विकेट में पहले से तेजी थी, इसलिए उन्हें गेंद को ज्यादा तेज फेंकने की जरूरत नहीं पड़ी। गेंद में अच्छी स्पिन और सही टप्पा उनकी रणनीति का हिस्सा रहा। उन्होंने भारतीय पिचों से तुलना करते हुए कहा था कि भारत में विकेट धीमे होते हैं और बल्लेबाजों को गेंद खेलने के लिए ज्यादा समय मिलता है। हेडिंग्ले की तेजी के कारण बैकफुट पर जाने वाले बल्लेबाजों के खिलाफ विकेट मिलने के मौके ज्यादा बने।

वर्ल्ड चैंपियनशिप : विनेश को ट्रायल में हिस्सा लेने की नहीं मिली अनुमति

एजेंसी, नई दिल्ली

भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को 2026 सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप के चयन ट्रायल से पहले बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें 14 सितंबर को होने वाले चयन ट्रायल में हिस्सा लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने अंतरिम आदेश में कहा कि अदालत विनेश फोगाट को ट्रायल में शामिल होने के लिए, मौजूदा नियमों से विशेष छूट नहीं दे सकती।

दिल्ली हाईकोर्ट ने विनेश फोगाट की मातृत्व और खेल करियर से जुड़े एक अहम सवाल पर विचार करने की बात कही है। कोर्ट यह देखेगा कि मां बनने के बाद महिला खिलाड़ियों की खेल में वापसी और प्रतियोगिताओं की पात्रता के नियमों के बीच किस तरह संतुलन बनाया जा सकता है। विनेश फोगाट जुलाई 2025 में मां बनी थीं। इसके बाद वह मैटरनिटी लीव से लौट चुकी हैं। उन्होंने 2026 सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए होने वाले महिला चयन ट्रायल में हिस्सा लेने की अनुमति मांगी थी।

क्या है पूरा मामला?

भारतीय कुश्ती महासंघ ने सात सितंबर को चयन ट्रायल के लिए पात्रता से जुड़े नियम तय किए थे। इन नियमों के तहत कुछ अनिवार्य प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना जरूरी है। हाईकोर्ट ने कहा कि ये नियम सभी खिलाड़ियों पर समान रूप से लागू होते हैं। अगर कोई पहलवान तय अनिवार्य प्रतियोगिताओं में शामिल नहीं हुआ है, तो मौजूदा नियमों के तहत उसे चयन ट्रायल के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।

यूएस ओपन : आर्यना सबालेंका और रिबाकिना में होगा खिताबी मुकाबला

सबालेंका ने जेसिका पेगुला को और रायबकिना ने कोको गॉफ को हराया

एजेंसी, न्यूयॉर्क

बेलारूस की आर्यना सबालेंका और कजाकिस्तान की एलेना रायबकिना ने यूएस ओपन महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। सबालेंका ने वीरवार को न्यूयॉर्क के आर्थर ऐश स्टेडियम में खेले गए सेमीफाइनल में अमेरिका की जेसिका पेगुला को 7-5, 6-2 से हराया। वहीं, रिबाकिना ने अमेरिका की कोको गॉफ को 3-6, 6-4, 6-4 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। गॉफ ने पहला सेट जीतकर अच्छी शुरुआत की, लेकिन रायबकिना ने लगातार दो सेट जीतकर मुकाबला अपने नाम कर लिया।

रिबाकिना ने वापसी कर फाइनल में बनाई जगह

गॉफ ने शुरुआत में मजबूत खेल दिखाते हुए पहला सेट 6-3 से अपने नाम किया। इसके बाद रिबाकिना ने गॉफ की गलतियों का फायदा उठाते हुए दूसरा सेट 6-4 से जीतकर मुकाबला बराबर कर दिया। निर्णायक सेट में रिबाकिना ने 5-3 की बढ़त हासिल कर ली। गॉफ ने एक बार फिर वापसी की कोशिश की, पर रिबाकिना ने 6-4 से सेट जीत लिया। इस तरह पहला सेट जीतने के बावजूद गॉफ को सेमीफाइनल में हारकर बाहर होना पड़ा। यूएस ओपन खत्म होने के बाद रिबाकिना नई वर्ल्ड नंबर-1 बन जाएंगी। सबालेंका 99 लगातार हफ्तों से शीर्ष पर हैं, लेकिन रिबाकिना के सेमीफाइनल में पहुंचने के साथ उनकी नंबर-1 रैंकिंग तय हो गई थी। शनिवार का फाइनल इसलिए भी खास होगा कि एक तरफ नई नंबर-1 बनने जा रही रिबाकिना होंगी और दूसरी तरफ लगातार तीसरा यूएस ओपन खिताब जीतने की कोशिश में सबालेंका होंगी।

सबालेंका के पास लगातार तीन यूएस ओपन खिताब जीतने का मौका

इस जीत के साथ सबालेंका की यूएस ओपन में लगातार जीत का सिलसिला 19 मैचों का हो गया। वह 2023 के फाइनल में गॉफ से हारने के बाद से इस टूर्नामेंट में अजेय हैं। यह सबालेंका का यूएस ओपन में लगातार चौथा फाइनल है। वह 2023 में भी खिताबी मुकाबले तक पहुंची थीं, लेकिन कोको गॉफ से हार गई थीं। इसके बाद उन्होंने 2024 और 2025 में लगातार खिताब जीते। अब शनिवार को जीत उन्हें न्यूयॉर्क में लगातार तीन खिताब जीतने वाली दूसरी महिला खिलाड़ी बना देगी, जिसने ओपन एरा में यह उपलब्धि हासिल की है। शनिवार को जीत दर्ज करते ही सबालेंका ओपन ऐरा में लगातार तीन यूएस ओपन खिताब जीतने वाली खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो जाएंगी। सेरेना विलियम्स ने 2012 से 2014 तक लगातार तीन यूएस ओपन खिताब जीते थे, जबकि क्रिस एवर्ट ने 1975 से 1978 के बीच लगातार चार बार यह ट्रॉफी अपने नाम की थी। ओपन ऐरा की शुरुआत 1968 में हुई थी। इसके बाद पहली बार प्रोफेशनल खिलाड़ियों को ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंटों में खेलने की अनुमति मिली थी।

एशिया कप फाइनल के लिए भारत तैयार : दिप्ति

एजेंसी, दुबई

भारत की अनुभवी ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में अब तक के शानदार प्रदर्शन के बावजूद खराब क्षेत्ररक्षण को लेकर जताई जा रही चिंताओं को खारिज करते हुए कहा कि कैच छूटना खेल का हिस्सा है और टीम फाइनल में हर विभाग में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने इस टूर्नामेंट में अभी तक अपने सभी मैच जीते हैं, लेकिन उसका क्षेत्ररक्षण अच्छा नहीं रहा है। विशेषकर उसने कई कैच छोड़े। सेमीफाइनल में भी बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय टीम ने चार मौके गंवाए थे। दीप्ति ने भारत की सेमीफाइनल में बांग्लादेश के खिलाफ 40 रन की जीत के बाद कहा, 'क्षेत्ररक्षण में एक टीम के तौर पर हम अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हम अभ्यास के दौरान भी क्षेत्ररक्षण पर काफी ध्यान दे रहे हैं।' उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि कभी-कभी ऐसा होता है, लेकिन हम फाइनल में तीनों विभागों में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।'

फाइनल में भारत का सामना अपने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान या मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। दीप्ति ने कहा कि टीम इन दोनों टीमों के बीच होने वाले सेमीफाइनल को देखने के बाद अपनी रणनीति बनाएगी। उन्होंने कहा, 'इस मैच के बाद हम कल बैठक करेंगे। इससे हमें फाइनल के लिए रणनीति बनाने में और अधिक मदद मिलेगी।'

कैच-क्षेत्ररक्षण चिंता का विषय नहीं

दीप्ति ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए छह गेंदों में 13 रन बनाए और फिर गेंदबाजी करते हुए 36 रन देकर तीन विकेट लिए। उन्होंने कहा, 'जब भी मुझे बल्लेबाजी का मौका मिलता है, मुझे हमेशा भरोसा रहता है कि मैं बल्लेबाजी में भी योगदान दे सकती हूं। मैं हमेशा टीम के लिए, एक ऑलराउंडर के तौर पर योगदान देना चाहती हूं।'

स्पोर्ट्स विंडो

अन्नू एशियन गेम्स स्क्वॉड से बाहर क्वालिफिकेशन मार्क नहीं छू पाईं

एजेंसी, नई दिल्ली। हांगझोउ एशियन गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट अन्नू रानी जापान एशियन गेम्स के भारतीय स्क्वॉड से बाहर हो गई हैं। वे महिलाओं की जैवलिन थ्रो में क्वालिफिकेशन मार्क हासिल नहीं कर सकीं। अन्नू ने वीरवार को जेएलएन स्टेडियम में इंडियन एथलेटिक्स फाइनल सीरीज में 57.50 मीटर का थ्रो किया। वह 57.62 मीटर के क्वालिफिकेशन मार्क से 12 सेंटीमीटर पीछे रह गईं। इसी इवेंट में चोट से लौटे अविनाश साबले ने 3,000 मीटर स्टीपलचेज में गोल्ड जीता। उन्होंने 8:32.39 सेकेंड का समय निकालकर 8:36.57 सेकेंड का क्वालिफिकेशन मार्क हासिल किया। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने प्रतियोगिता से पहले खिलाड़ियों को साफ कर दिया था कि एशियन गेम्स में जाने के लिए क्वालिफिकेशन मार्क हासिल करना जरूरी है। एएफआई के चेयरमैन ललित भनोत ने कहा, जिसने क्वालिफिकेशन मार्क हासिल नहीं किया है, उसे एशियन गेम्स में नहीं भेजा जाएगा। एएफआई का रुख बिल्कुल साफ था। उन्होंने कहा, अगर अन्नू रानी क्वालिफाई नहीं कर पाई हैं, तो वे नहीं जाएंगी। जिन खिलाड़ियों ने मार्क हासिल नहीं किया है, वे दल का हिस्सा नहीं होंगे।

पांव में खिंचाव के कारण युकी भांबरी का डेविस कप में खेलना संदिग्ध

एजेंसी, नईदिल्ली। अमेरिकी ओपन में मैच से पहले अभ्यास के दौरान दाहिने पांव में खिंचाव आने के कारण भारत के युकी भांबरी का सोल में दक्षिण कोरिया के खिलाफ डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले में खेलना संदिग्ध है। भांबरी वीरवार की रात को कोरिया के लिए रवाना हुए भारतीय खिलाड़ियों के पहले बैच के साथ सोल नहीं गए। इससे उनके इस महत्वपूर्ण मुकाबले में खेलने को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। इस मुकाबले में जीत दर्ज करने वाली टीम आठ टीमों के एलीट डेविस कप फाइनल में अपनी जगह पक्की करेगी। भांबरी ने इसे मामूली मोच बताया। इस भारतीय खिलाड़ी ने कहा कि इस महीने के आखिर में शुरू होने वाले एशियाई खेलों में उनकी भागीदारी को कोई खतरा नहीं है। भांबरी ने पीटीआई से कहा, "अमेरिकी ओपन में मुख्य ड्रॉ के मैच से पहले अभ्यास के दौरान मेरे पांव में खिंचाव आ गया था। यह मामूली चोट है। मेरे पूरी तरह फिट होने के लिए कोई समयसीमा तय नहीं है, लेकिन यह कोई गंभीर चोट नहीं है।' भांबरी की स्थिति पर प्रतिदिन नजर रखी जा रही है। वह अपनी फिटनेस का आकलन करने के लिए देवाशीष दास और यश पांडे सहित भारतीय डेविस कप टीम के सहयोगी स्टाफ के संपर्क में हैं।

दलीप ट्रॉफी में लंबा स्पेल करने से अपनी लय में लौटे मोहम्मद सिराज

एजेंसी, चेन्नई। चेन्नई में भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने कहा कि दलीप ट्रॉफी में लंबे स्पेल करने के बाद उनकी लय और रफ्तार वापस आ गई है। सिराज ने बताया कि 8 जून को अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट खत्म होने के बाद उन्होंने दो महीने का ब्रेक लिया था। ब्रेक के बाद शरीर सुस्त महसूस कर रहा था, जिसका असर श्रीलंका दौरे पर रन-अप और गेंदबाजी की रफ्तार पर पड़ा था। सिराज ने कहा, 'दो महीने के ब्रेक के बाद सीधे श्रीलंका मैच में उतरने से मेरी लय पूरी तरह नहीं बन पाई थी। मैं पूरी तरह लय पर निर्भर गेंदबाज हूं। अगर मेरा तालमेल सही नहीं होता, तो क्रीज से पूरी ताकत के साथ गेंद नहीं निकाल पाता।'

पीएम किसान की 24वीं किस्त के लिए अक्टूबर तक करना होगा इंतजार

एजेंसी, नई दिल्ली

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देशभर के करोड़ों किसान 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना छह हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो दो-दो हजार रुपये की तीन समान किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।

पिछली किस्त जून में जारी होने के बाद अब अगली किस्त को लेकर किसानों में उत्सुकता है। योजना के निर्धारित चार महीने के अंतराल और पिछले वर्षों के रुझान को देखते हुए 24वीं किस्त सितंबर के बजाय अक्टूबर के अंत या नवंबर की शुरुआत में जारी होने की संभावना जताई जा रही है।

हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक किस्त जारी करने की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है। पात्र किसानों को किस्त का लाभ लेने के लिए योजना से जुड़ी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी रखना जरूरी होगा।

मोबाइल रिचार्ज फिर हो सकते हैं महंगे!

एजेंसी, नई दिल्ली। मोबाइल रिचार्ज एक बार फिर महंगे होने की संभावना है। टेलीकॉम कंपनियां अगले दो तिमाहियों में मोबाइल टैरिफ में 10 से 20 प्रतिशत तक बढ़ोतरी पर विचार कर रही हैं। रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया 5जी नेटवर्क विस्तार, डेटा सेंटर और अन्य बुनियादी ढांचे में बड़े निवेश की तैयारी कर रही हैं। ऐसे में कंपनियां बेहतर औसत राजस्व प्रति ग्राहक (एआरपीयू) हासिल करने के लिए दरें बढ़ा सकती हैं। उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि यह बढ़ोतरी जियो के संभावित आरंभिक सार्वजनिक निर्गम से पहले भी हो सकती है। कंपनियां धीरे-धीरे सस्ते शुरुआती प्लान कम कर ग्राहकों को अधिक कीमत वाले पैक लेने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। इससे आने वाले समय में उपभोक्ताओं का मासिक मोबाइल खर्च बढ़ सकता है। इससे पहले दिसंबर 2019 में टैरिफ 15-40 प्रतिशत, दिसंबर 2021 में करीब 20 प्रतिशत और जून 2024 में 10-25 प्रतिशत तक बढ़ाए गए थे।

कच्चे तेल के दबाव से गिरा बाजार, सेंसेक्स 121 अंक गिरा, निफ्टी 23,398 पर थमा

एजेंसी, मुंबई

शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों, बॉन्ड यील्ड में उछाल और निवेशकों की सतर्कता के चलते कारोबार की शुरुआत में सेंसेक्स और निफ्टी में करीब एक प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई।

सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 740 अंक से अधिक फिसलकर 74,160 के स्तर तक पहुंच गया, जबकि निफ्टी 50 करीब 264 अंक टूटकर 23,231 पर आ गया। इस गिरावट के कारण बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों के कुल बाजार पूंजीकरण में शुरुआती समय में पांच लाख करोड़ रुपये से अधिक की कमी आई।

हालांकि, बाद में बाजार में खरीदारी लौटने से प्रमुख सूचकांकों ने निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी की। कारोबार समाप्त होने पर सेंसेक्स 120.83 अंक यानी 0.16 प्रतिशत की गिरावट के साथ 74,781.76 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 79.70 अंक यानी 0.34 प्रतिशत फिसलकर 23,398.10 अंक पर रहा। निफ्टी में डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी, टेक महिंद्रा और विप्रो प्रमुख बढ़त वाले शेयर रहे।

दूसरी ओर हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, आयशर मोटर्स और ओएनजीसी में सबसे अधिक दबाव देखने को मिला। क्षेत्रीय सूचकांकों में निजी बैंक सूचकांक करीब 0.5 प्रतिशत चढ़ा, जबकि धातु और रियल्टी सूचकांकों में दो प्रतिशत से अधिक की गिरावट रही। ऑटो, ऊर्जा, तेल एवं गैस और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सूचकांक भी दबाव में रहे। मिडकैप सूचकांक 0.26 प्रतिशत और स्मॉलकैप सूचकांक 0.6 प्रतिशत नीचे बंद हुए।

आईआरसीटीसी ने एक ही दिन में 20 लाख टिकट बुकिंग का बनाया रिकॉर्ड

एंटी-बॉट तकनीक से आईआरसीटीसी हुआ मजबूत

एजेंसी, नई दिल्ली

इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) ने 7 सितंबर 2026 को एक ही दिन में 20,06,353 ट्रेन टिकट बुकिंग की प्रक्रिया संभालकर नया रिकॉर्ड बनाया। आगामी नवरात्र, दीपावली और छठ जैसे त्योहारों को देखते हुए अग्रिम आरक्षण अवधि में टिकटों की मांग तेजी से बढ़ी है। अगले दिन भी 19.5 लाख से अधिक बुकिंग हुई। इस दौरान नेक्स्ट जेनरेशन ई-टिकटिंग मंच ने भारी दबाव के बावजूद बिना किसी बड़ी रुकावट के बुकिंग व्यवस्था को संभाला। पीक समय में 1.74 करोड़ तक प्रवेश होने के बावजूद प्रणाली ने यात्रियों को सेवाएं उपलब्ध कराईं।

देश में करीब 89 प्रतिशत ट्रेन टिकट अब ऑनलाइन माध्यम से बुक होते हैं। बढ़ती मांग को देखते हुए आईआरसीटीसी ने पुराने हार्डवेयर को बदलकर सर्वर क्षमता दोगुनी की है और प्रणाली के ढांचे में भी सुधार किया है। जुलाई 2026 में नए रूप वाला बीटा उपयोगकर्ता इंटरफेस शुरू किया गया, जिसमें स्लीपर, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी और वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में सीट उपलब्धता एक ही स्क्रीन पर दिखाई देती है।

इससे यात्रियों को विकल्पों की तुलना करने और टिकट बुक करने में सुविधा मिलती है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उन्नत एंटी-बॉट तकनीक और नए कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया है। इससे संदिग्ध बॉट यातायात में 65 प्रतिशत तक कमी आई है। आईआरसीटीसी ने तीन करोड़ से अधिक संदिग्ध उपयोगकर्ता पहचान निष्क्रिय की हैं और 16 हजार से ज्यादा अवैध ईमेल डोमेन को भी प्रतिबंधित किया है। सुबह आठ से 8:10 बजे तक अधिकृत टिकट एजेंटों को बुकिंग की अनुमति नहीं है। इस शुरुआती अवधि में केवल आधार सत्यापित उपयोगकर्ता टिकट बुक कर सकते हैं।

आशंका

ह्यूस्टन में जी20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में टिकाऊ ऊर्जा व्यवस्था पर होगा मंथन

ऊर्जा सुरक्षा पर जी20 में भारत का पक्ष रखेंगे मनोहर लाल

एजेंसी, नई दिल्ली

केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल 14 से 16 सितंबर तक अमेरिका के ह्यूस्टन में आयोजित होने वाली जी20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। अमेरिका की मेजबानी में होने वाली इस महत्वपूर्ण बैठक में जी20 सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। बैठक के दौरान वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा कीमतों, बुनियादी ढांचे के विकास और मजबूत ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े अहम मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री इस दौरान भारत की ऊर्जा नीति और तेजी से बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए किए जा रहे प्रयासों का पक्ष अंतरराष्ट्रीय मंच पर रखेंगे। विद्युत मंत्रालय के अनुसार, मनोहर लाल बैठक के दौरान आयोजित तीन प्रमुख मंत्रिस्तरीय सत्रों में भाग लेंगे।

ऊर्जा क्षेत्र में भारत का नया दृष्टिकोण

मनोहर लाल बैठक में भारत के उस दृष्टिकोण को सामने रखेंगे, जिसके तहत देश में एक सुदृढ़ और भविष्य के लिए तैयार ऊर्जा प्रणाली विकसित की जा रही है। यह प्रणाली देश की तेजी से बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने में सक्षम हो, इस दिशा में नीतिगत और संस्थागत स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अनुमति देने की प्रक्रिया को सरल बनाने और नियामकीय दक्षता बढ़ाने के लिए किए गए सुधारों से भारत के अनुभव को भी साझा करेंगे। उनका जोर इस बात पर रहेगा कि किस तरह प्रभावी नीतियों और बेहतर नियामकीय व्यवस्था के माध्यम से ऊर्जा क्षेत्र में विकास को गति दी जा सकती है।

महत्वपूर्ण खनिजों पर भारत रखेगा अपना पक्ष

बैठक में महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता और उनकी आपूर्ति श्रृंखला भी प्रमुख चर्चा का विषय रहेगी। आधुनिक ऊर्जा व्यवस्था और नई प्रौद्योगिकियों के विकास में महत्वपूर्ण खनिजों की भूमिका लगातार बढ़ रही है। ऐसे में इन खनिजों की आपूर्ति को मजबूत और भरोसेमंद बनाए रखना आवश्यक है। भारत महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में स्रोतों के विविधीकरण, संसाधनों के बेहतर उपयोग और पूरी मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने पर अपना विशेष जोर रखेगा। मंत्रालय ने कहा कि जी20 बैठक में मनोहर लाल की भागीदारी उभरती वैश्विक ऊर्जा चुनौतियों से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग और सामूहिक प्रयासों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करेगी। भारत ऐसे व्यावहारिक, समावेशी और प्रौद्योगिकी-तटस्थ दृष्टिकोण की वकालत करता रहा है, जिसमें अलग-अलग देशों की परिस्थितियों और जरूरतों का सम्मान किया जाए। साथ ही सभी देशों के लिए सुरक्षित, किफायती, विश्वसनीय, मजबूत और टिकाऊ ऊर्जा व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में मिलकर काम करने पर जोर दिया जाएगा।